राष्ट्रीय संस्करण

वर्ष 5 अंक 49

दैनिक जागरण

मूल्य ₹8.00, नई दिल्ली, गुरुवार, 29 जुलाई, 2021

www.jagran.com

पृष्ठ 14

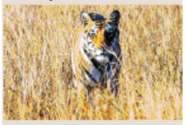


पूजा, दीपिका और सिंधु की जीत ने बढ़ाईं उम्मीदें

» 12

जागरण विशेष

बाघ इतने बढ़ने लगे कि जंगल छोटे पड़ने लगे



नई दिल्ली : देश में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है। चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड या फिर बिहार, सभी जगह बाघों की संख्या में इजाफा हुआ है। मध्य प्रदेश में बढ़ते कुनबे के कारण बाघ नए ठिकाने बना रहे हैं। (पेज-6)

न्यूज गैलरी

राजनीति पृष्ठ 4

बोम्मई ने सीएम बनते ही किया हजार करोड़ के वजीफे का एलान

बेंगलुरु : कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बुधवार को बासवराज बोम्मई ने नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राजभवन में आयोजित समारोह में बोम्मई को राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री के रूप में बोम्मई ने प्रभावी, ईमानदार और मैत्रीपूर्ण सरकार देने का वादा किया है। उन्होंने किसानों की बेटी-बेटों के लिए एक हजार करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति योजना का एलान किया है।

राष्ट्रीय फलक पृष्ठ 5

असम-मिजोरम सीमा पर तैनात होंगे केंद्रीय बल

नई दिल्ली : असम-मिजोरम सीमा की निगरानी की जिम्मेदारी अब केंद्रीय बल संभालेंगे। केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला के साथ बैठक में दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी इसके लिए सहमत हो गए हैं। उल्लेखनीय है कि सोमवार को पूर्वोत्तर के दोनों राज्यों की सीमा पर हुई झड़प में असम पुलिस के पांच जवानों समेत छह लोग मारे गए थे और पुलिस अधीक्षक समेत 50 से अधिक घायल हुए थे।

कोरोना से जंग पृष्ठ 6

केरल में कोरोना विस्फोट, आधे मामले यहीं से

नई दिल्ली : केरल में कोरोना संक्रमण का विस्फोट हुआ है। बीते 24 घंटे में देश में पाए गए संक्रमण के कुल मामलों में से 50 फीसद से अधिक अकेले केरल से हैं। वैसे तो मामलों में अचानक वृद्धि की ठोस वजह नहीं बताई गई है, लेकिन बकरीद के मौके पर पाबंदियों में छूट से संक्रमण बढ़ने की आशंका जताई गई थी। यहां तक कि राज्य की वामदल सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

वैचारिकी पृष्ठ 10

पेंशन खैरात नहीं, सेवा अधिकार है : इलाहाबाद हाई कोर्ट

प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि सिविल सर्विस रेग्युलेशन 351(ए) के अंतर्गत वित्तीय क्षति की भरपाई के लिए कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने से पहले विभागीय कार्यवाही शुरू करनी चाहिए। पेंशन खैरात नहीं है, सेवा अधिकार है। सेवानिवृत्ति के बाद बिना राज्यपाल से अनुमोदन लिए विभागीय कार्यवाही संविधान के अनुच्छेद 300(ए) के विपरीत है।

पहाड़ पर फटे बादल से भारी तबाही, 14 की मौत

- जम्मू के किश्तवाड़ में सात और हिमाचल के तोजिंग नाले में मिले सात लोगों के शव
- किश्तवाड़ में बाढ़ में बहे 17 लोगों को बचाया गया, 19 अब भी लापता
- तोजिंग नाले में बहे 12 लोगों में से दो को बचा लिया गया, तीन अब भी लापता
- घटना पर केंद्र की नजर, प्रधानमंत्री ने दिया हर संभव मदद का भरोसा

जागरण टीम, नई दिल्ली

जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में मूसलधार बारिश, भूस्खलन और कई जगह बादल फटने से आई बाढ़ से भारी तबाही हुई। इससे 14 लोगों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा नुकसान जम्मू संभाग के किश्तवाड़ जिले में हुआ। किश्तवाड़ के दुरदराज के गांव होंजर में बादल फटने से आई बाढ़ के मलबे में दबने से सात लोगों की मौत हो गई, जिनके शव बरामद कर लिए गए हैं। यहां से 17 घायलों को बचा लिया गया है, जिनमें से पांच की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं, 19 लोग अब भी लापता हैं। पुलिस व स्थानीय लोगों के अलावा सेना, एसडीआरएफ की अतिरिक्त टुकड़ियां राहत अभियान में जुटी हुई हैं। मौसम साफ होते ही हेलीकाप्टर से जम्मू व श्रीनगर से एनडीआरएफ की टीमें भी मौके पर पहुंच जाएंगी।

हिमाचल प्रदेश के लाहुल-स्पीति जिले के तोजिंग नाले और कुल्लू के ब्रह्मगंगा नाले में बादल फटने से आई बाढ़ में मां-बेटे समेत 16 लोग बह गए। इनमें गाजियाबाद की युवती भी शामिल है, जो यहां कैंपिंग साइट में मैनेजर के पद पर कार्यरत थी। अब तक सात लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं जबकि सात लापता हैं। दो लोगों को रेस्क्यू दल ने बचा लिया है।



कुल्लू जिले में बुधवार को मणिकर्ण घाटी में बादल फटने के बाद बाढ़ की चपेट में आए मंदिर और घर। प्रेट्र

कई जगह फंसे पर्यटक

लाहुल-स्पीति जिले में बादल फटने से लाहुल घाटी के कई नालों में बाढ़ आ गई है। इससे लेह व काजा मार्ग पर सैकड़ों पर्यटक फंस गए हैं। प्रशासन ने पर्यटकों व वाहन चालकों के लिए एडवाइजरी जारी कर यात्रा न करने की सलाह दी है। मनाली-लेह, तांदी-किलाड़ व ग्रांफू-समदो मार्ग जगह-जगह बंद हो गए हैं। मनाली-लेह मार्ग पर साकस नाले सहित पटसेउ, भरतपुर सिटी व सरचू में सड़क बंद हो गई है।

अमरनाथ गुफा के पास भी फटा बादल

समुद्रतल से करीब 3888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा के पास बादल फटने से अचानक आई बाढ़ में दो लंगर और सुरक्षाकर्मियों के एक शिविर को नुकसान पहुंचा है। यात्रा बंद होने के कारण यहां किसी जनहानि की सूचना नहीं है।

केंद्र की बनी रही नजर

केंद्र सरकार ने दिनभर इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन को हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया है। वहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और जम्मू-कश्मीर पुलिस के महानिदेशक (डीजीपी) दिलबाग सिंह से बात कर स्थिति जानी और जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए।

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपाल ने जताया दुख

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किश्तवाड़ घटना पर गहरा दुख जताते हुए हादसे में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उपराज्यपाल ने लापता लोगों का जल्द से जल्द पता लगाने के लिए बचाव दल को कार्य में तेजी लाने के लिए भी कहा।

कैसे फटता है बादल

मौसम विशेषज्ञ डा. महेंद्र सिंह ने बताया कि जब बादल भारी मात्रा में आद्रता यानी पानी लेकर आसमान में चलते हैं और उनकी राह में कोई बाधा आ जाती है, तब यह अचानक फट पड़ते हैं। यह सब बहुत तेजी से होता है। इस स्थिति में एक सीमित इलाके में कई लाख लीटर पानी एक साथ जमीन पर गिरता है, जिसके चलते उस क्षेत्र में तेज बहाव वाली बाढ़ आ जाती है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर पानी से भरे किसी गुब्बारे को फोड़ दिया जाए तो सारा पानी एक ही जगह तेजी से नीचे गिरता है। ठीक वैसे ही बादल फटने से होता है।



बाराबंकी में खड़ी बस में ट्रक ने मारी टक्कर, 18 लोगों की मौत

- रामसनेहीघाट में कल्याणी नदी के पुल पर हुआ भीषण हादसा
- पलवल से बिहार जा रही निजी बस में सवार थे करीब 135 यात्री



बाराबंकी में पुल पर खड़ी इसी बस में ट्रक ने टक्कर मारी थी। जागरण

जागरण संवाददाता, बाराबंकी

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर मंगलवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। रामसनेहीघाट में कल्याणी नदी के पुल पर खराब खड़ी डबल डेकर बस में लखनऊ की ओर से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। बस में सवार और उसके नीचे सो रहे करीब 135 यात्रियों में से 18 की मौत हो गई।

हरियाणा के पलवल से बिहार के यात्रियों को लेकर रवाना हुई बस रात करीब नौ बजे कल्याणी नदी के पुल के पास पहुंची ही थी कि बस का एक्सल टूट गया। ड्राइवर ने बस को खड़ा कर दिया और मैकेनिक की तलाश में चला गया। अधिकांश यात्री सड़क के किनारे, कुछ बस के नीचे और कुछ आसपास लेटे थे। करीब 12 बजे पीछे से ट्रक के टक्कर मारने से वहां सो रहे यात्रियों को रौंदते हुए 15 मीटर तक आगे बढ़ गई। घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। कुछ ही देर में तेज बारिश होने से मुसीबत और बढ़ गई। रामसनेहीघाट एसडीएम जितेंद्र कुमार और सीओ पंकज सिंह के नेतृत्व में करीब चार घंटे तक चले रेस्क्यू आपरेशन में पुलिस टीम ने शवों और घायलों को बाहर निकाला। गंभीर रूप से घायल 19 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और सीएम ने जताया दुख

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आनंदी बेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया है। पीएम राहत कोष से मृतकों के स्वजन को दो-दो लाख तथा घायलों को पचास-पचास हजार रुपये देने की घोषणा की गई है।

दुनिया में भारत और अमेरिका जैसा अहम रिश्ता दूसरा कोई नहीं : ब्लिंकन

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद भारत के साथ रिश्तों को लेकर संशय तो पहले ही खत्म हो चुका है, लेकिन नई दिल्ली पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बुधवार को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के रिश्ते और गहरे और व्यापक होंगे। ब्लिंकन की दिनभर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ मुलाकात में अफगानिस्तान, चीन, कोरोना महामारी व आर्थिक रिश्तों पर बात हुई। दोनों विदेश मंत्रियों के बीच एक घंटे चली द्विपक्षीय वार्ता के बाद ब्लिंकन का यह कहना, 'भारत और अमेरिका के रिश्तों जैसा दुनिया में और कोई महत्वपूर्ण रिश्ता नहीं है' उनके भारतीय दौरे का सार है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के साथ साझेदारी को मजबूत करना राष्ट्रपति जो बाइडन प्रशासन की अहम प्राथमिकता है।

अमेरिकी विदेश मंत्री ने दिन में भारत की सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों से अलग से मुलाकात करके और बाद में संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में लोकतांत्रिक मूल्यों पर लंबा बयान देकर यह संदेश भी दिया कि अमेरिकी सरकार इन मुद्दों को दरकिनार नहीं कर सकती। जाहिर है कि दोनों मंत्रियों के बीच वार्ता में मानवाधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक मूल्यों आदि पर खुलकर बात हुई और संकेत हैं कि इस मुद्दे पर कुछ विभेद भी रहे हैं।

भारत के साथ मिलकर अफगान सैनिकों को प्रशिक्षित करेगा अमेरिका : अफगानिस्तान को लेकर दोनों देशों के बीच आम राय है कि हिंसा का दौर जल्द समाप्त होना चाहिए और तालिबान व अफगान सरकार के बीच शांति वार्ता होनी चाहिए। वहां जो भी बदलाव हो उसमें सभी पक्षों का प्रतिनिधित्व हो। गत दो दशकों में वहां महिलाओं, अल्पसंख्यकों को अधिकार देने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उसे बरकरार रखा जाना चाहिए। ब्लिंकन ने कहा, अमेरिका भारत के साथ मिलकर अफगानिस्तान की आर्थिक प्रगति और वहां के सैनिकों को प्रशिक्षित करने का काम करेगा।

अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन दलाईलामा के प्रतिनिधि से मिले पेज»3

प्रगाढ़ होते रिश्ते

- मानवाधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़े मुद्दे भी उठे
- हमारे रिश्ते दुनिया में बड़े बदलावों के लिए : जयशंकर
- पीएम मोदी और एनएसए डोभाल से भी अमेरिकी विदेश मंत्री की वार्ता



नई दिल्ली में बुधवार को एंटनी ब्लिंकन के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर। प्रेट्र

मानवाधिकार पर ब्लिंकन बोले

लोकतांत्रिक आजादी को बनाए रखना सतत प्रक्रिया है। अमेरिका भी इन चुनौतियों का सामना कर रहा है। कई बार इसका विद्रूप रूप देखना पड़ता है, लेकिन हम मित्र राष्ट्र की तरह इन मुद्दों पर विमर्श करते रहेंगे और अनुभव साझा करते रहेंगे। हम अपनी जनता की आजादी, बराबरी व अवसरों को काफी गंभीरता से लेते हैं।'

जयशंकर ने दिया खरा जवाब

एक दोस्तहित देश होने का सवाल भारत पर उसी तरह से लागू होता है जैसा कि अमेरिका या अन्य देशों पर। आजादी बहुत जरूरी है, लेकिन इसे खराब गवर्नेंस या गवर्नेंस के नहीं होने के बराबर नहीं रखा जा सकता। 'हर राजनेता का नैतिक दायित्व है कि वह अपने देश के सभी ऐतिहासिक गलत व सही फैसलों के बारे में बताए जिसमें हाल के वर्षों में लिए गए फैसलों की जानकारी भी हो।' बहुलवादी व्यवस्था को लेकर भारत के अपने विचार हैं।

भारत ने क्वाड की तुलना ब्रिक्स से की : ब्लिंकन ने चीन द्वारा क्वाड (अमेरिका, जापान, भारत व आस्ट्रेलिया) को सैन्य संगठन बताए जाने को खारिज किया। उन्होंने कहा, क्वाड दुनिया के समक्ष उत्पन्न कुछ बड़ी चुनौतियों के लिए काम कर रहा है। जयशंकर ने क्वाड की तुलना ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन व दक्षिण अफ्रीका) से करते हुए कहा कि किसी देश को यह नहीं सोचना चाहिए कि दूसरा कोई संगठन उसके खिलाफ गठित किया गया है।

जयशंकर ने हवाई मार्ग पूरी तरह खोलने का किया आग्रह : जयशंकर ने कोरोना महामारी से निपटने में मिल रहे सहयोग और वैक्सीन के लिए कच्चे माल की आपूर्ति में अमेरिकी मदद को असाधारण करार दिया। जयशंकर ने अमेरिका से भारत के साथ हवाई मार्ग को पूरी तरह खोलने का भी आग्रह किया। भारतीय छात्रों को अमेरिका जाने की इजाजत मिलने लगी है, लेकिन भारत का कहना है कि दूसरे यात्रियों को भी सहूलियत दी जानी चाहिए।

संसद में तनातनी आर-पार की ओर बढ़ी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पेगासस जासूसी कांड पर एकजुट हुए 14 विपक्षी दलों ने संयुक्त रणनीति के साथ दोनों सदनों में आक्रामक मोर्चाबंदी करते हुए भारी हंगामा कर लगातार सातवें दिन संसद की कार्यवाही बाधित की। लोकसभा में तो विपक्षी सदस्यों ने हवा में पर्चे उड़ाने के साथ ही आसन की तरफ भी उन्हें फेंका। विपक्ष ने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार चर्चा को राजी नहीं होगी तब तक संसद का संग्राम नहीं थमेगा। वहीं, सरकार ने लोकसभा में दो और राज्यसभा में एक विधेयक पारित कर यह साफ संदेश दे दिया है कि विपक्ष के दबाव की उसे परवाह नहीं।

सत्तापक्ष ने लोकसभा में भारी हंगामे के दौरान कागज उछालने वाले 10 सदस्यों के खिलाफ निलंबन प्रस्ताव लाने के संकेत दिए हैं। ऐसे ही मामले में राज्यसभा से तृणमूल कांग्रेस के शांतनु सेन को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया जा चुका है। विपक्षी सदस्यों के निलंबन की तैयारी से संकेत साफ है कि जासूसी कांड पर सरकार और विपक्ष की तनातनी सियासी आर-पार की ओर बढ़ रही है।

जासूसी मामले का घमासान तेज होने का संकेत तो सुबह सदन शुरू होने से पहले 14 विपक्षी दलों की बहस की मांग से पीछे नहीं हटने पर बनी सहमति से मिल गया था। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में राहुल गांधी समेत दोनों सदनों में 14 विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक हुई। सभी नेताओं ने सदन में कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस देने का फैसला किया। इसमें कांग्रेस, द्रमुक, एनसीपी, शिवसेना, राजद, सपा, माकपा, भाकपा, नेशनल कांफ्रेंस, आइयूएमएल, केसीएम, वीसीके, आरएसपी और आप के नेता शामिल हुए। तृणमूल के नेता इस बैठक और साझा प्रेस कांफ्रेंस से दूर रहे। हालांकि, सदन में विपक्ष के साथ तृक्कं के सदस्य जरूर सक्रिय रूप से शामिल रहे।

विपक्ष के कार्यस्थगन प्रस्ताव को स्पीकर ने किया खारिज : लोस में राहुल समेत विपक्षी नेताओं के जासूसी कांड पर कार्यस्थगन प्रस्ताव के नोटिस को स्पीकर ने खारिज कर दिया और प्रश्नकाल चलाया। इस दौरान विपक्षी सदस्य जमकर नारेबाजी करते रहे और आसन के अलावा सत्तापक्ष से उनकी नोक-झोंक चलती रही।

पांच बार स्थगित हुई कार्यवाही पेज»3



लोकसभा में बुधवार को पेगासस जासूसी कांड समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामे के दौरान विपक्षी सदस्यों ने सदन अध्यक्ष ओम बिरला के आसन की ओर भी पर्चे फेंके। एएनआइ

विपक्ष का वार

- मानसून सत्र के सातवें दिन भी विपक्षी दलों का दोनों सदनों में हंगामा, आसन की तरफ पर्चे उड़ाए
- आक्रामक हुए सरकार विरोधी 14 दलों ने कहा, बहस की मांग से कोई समझौता नहीं

सरकार का पलटवार

- सरकार ने कहा, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं इसलिए संसद को किया जा रहा ठप
- हंगामे के दौरान आसन की तरफ कागज उड़ाने वाले 10 सदस्यों के निलंबन पर किया जा रहा विचार

जवाब से असंतुष्ट हाई कोर्ट ने ट्विटर को लगाई फटकार

नई दिल्ली : नए आइटी नियमों का अनुपालन नहीं करके बार-बार भ्रमित करने वाले जवाब दाखिल करने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्विटर को फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने बुधवार को मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह दाखिल किए गए हलफनामे से संतुष्ट नहीं है। पीठ ने ट्विटर को एक सप्ताह के अंदर स्पष्ट हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई छह अगस्त को होगी। (पेज-5)

बैंक में सुरक्षित रहेगी पांच लाख रुपये तक की रकम

- बैंक खाताधारकों के हित में कैबिनेट का बड़ा फैसला
- बैंक के दिवालिया होने पर 90 दिनों के भीतर मिल जाएंगे पांच लाख रुपये
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में किया था एलान



कैबिनेट के फैसले की जानकारी देती वित्त मंत्री। प्रेट्र

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

बैंक में जमा पांच लाख रुपये तक की राशि हर हाल में सुरक्षित रहेगी। अगर बैंक दिवालिया भी हो जाता है तो जमाकर्ता को सिर्फ 90 दिनों के भीतर पांच लाख रुपये तक अवश्य मिलेंगे। अभी बैंक में जमा सिर्फ एक लाख रुपये का ही बीमा होता है। इस सीमा को बढ़ाने के लिए सरकार डिपाजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी बिल ला रही है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने इस बिल पर मुहर लगा दी। गुरुवार को इसे लोकसभा में पेश किया जा सकता है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि डिपाजिट गारंटी के नए नियम के तहत सभी प्रकार के बैंक में जमा पांच लाख तक की राशि पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। इनमें सरकारी बैंक के साथ, निजी बैंक, ग्रामीण बैंक यहां तक कि भारत में स्थित विदेशी बैंक की शाखा भी शामिल होगी। अगर कोई बैंक मोरेटोरियम में आ चुका है तो उस पर भी नए नियम लागू होंगे। ज्ञात हो, वित्त मंत्री ने इस तरह का बिल लाने की घोषणा बजट भाषण में की थी। वैसे तो यह बिल बजट सत्र में ही पेश किया जाना था, पर कोरोना के चलते सत्र में कटौती करनी पड़ी और इसे पेश नहीं किया जा सका।

फरवरी 2020 से प्रभावी होगा नया कानून : पिछले साल संकट में फंसे पंजाब एंड महाराष्ट्र कोआपरेटिव बैंक के जमाकर्ताओं को राहत देते हुए सरकार ने इंश्योरेंस कवर पांच गुना बढ़ाने का एलान किया था। बिल को संसद से मंजूरी के बाद अगर भविष्य में कोई भी बैंक डूबता है तो जमाकर्ताओं को पांच लाख रुपये तक अवश्य मिलेंगे। पांच लाख रुपये तक का इंश्योरेंस कवर चार फरवरी, 2020 से प्रभावी होगा। यह बढ़ोतरी 27 साल बाद हुई है।

बैंक करेगा इंश्योरेंस के प्रीमियम का भुगतान : इंश्योरेंस की प्रीमियम राशि का भुगतान बैंक करेगा। अभी बैंक को 100 रुपये के इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम के तौर पर 10 पैसे का भुगतान करना होता है। 98.3 फीसद जमा खाते हो जाएंगे पूरी तरह सुरक्षित : नए नियम के लागू होने पर बैंकों के 98.3 फीसद जमा खाते (डिपाजिट अकाउंट) पूरी तरह सुरक्षित हो जाएंगे। वैश्विक स्तर पर 80 फीसद खाते ही डिपाजिट इंश्योरेंस के तहत कवर हैं।

अहम फैसला

केरल सरकार की याचिका खारिज, एलडीएफ विधायकों को राहत नहीं

कानून से बचने के लिए नहीं दे सकते विशेषाधिकार की दलील

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने एक अहम फैसले में कहा कि सभी नागरिकों पर लागू होने वाले आपराधिक कानूनों से छूट का दावा, सदन में मिली छूट और विशेषाधिकार का हवाला देकर नहीं किया जा सकता। आपराधिक कानून से छूट का दावा करना उस भरोसे को धोखा देना होगा जो उन पर जनप्रतिनिधि के तौर पर किया गया है।

कोर्ट ने कहा, जन प्रतिनिधियों को सदन की कार्यवाही के दौरान छूट और विशेषाधिकार इसलिए मिले हैं ताकि वे बिना किसी भय और बाधा के अपना विधायी कार्य कर सकें। सदस्यों द्वारा विरोध जताने में सदन में तोड़फोड़ करना और संपत्ति को नुकसान पहुंचाना विधायी कार्य नहीं है। उल्लेखनीय है इस मामले में पिछली सुनवाई में भी कोर्ट ने काफी तल्ख टिप्पणियां की थीं।

शीर्ष न्यायालय ने जन प्रतिनिधियों को सदन में मिली छूट और विशेषाधिकार के दायरे की संवैधानिक प्रावधानों के आलोक में कानूनी व्याख्या करते हुए एलडीएफ के छह नेताओं के खिलाफ 2015 में दर्ज सदन में तोड़फोड़ और संपत्ति नष्ट करने का आपराधिक मुकदमा वापस लेने की इजाजत देने से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह न्यायहित में नहीं होगा।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आए दिन देश के विभिन्न सदनों में होने वाले हंगामे और सदस्यों के मर्यादा लांघने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए महत्वपूर्ण है। इस फैसले से एक सीमा रेखा खिंचती नजर आती है जो माननीयों को उनका दायरा बताती है।

दूरगामी व्यवस्था देने वाला यह अहम फैसला जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने केरल सरकार की अपीलीय याचिका खारिज करते हुए सुनाया। पीठ ने निचली अदालत और हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया जिसमें छह नेताओं के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की लोक अभियोजक (सरकारी वकील) की अर्जी नामंजूर की जा चुकी है।

शीर्ष न्यायालय ने कहा, सदन में सार्वजनिक संपत्ति को तोड़ना और नुकसान पहुंचाना, अभिव्यक्ति की आजादी और विपक्ष को विरोध के मिले वैध अधिकार के बराबर नहीं है। बजट पेश करने का विरोध करने में सदन में सार्वजनिक संपत्ति को तोड़ना जरूरी विधायी कार्य का निर्वहन नहीं माना जा सकता। ऐसा करना विशेषाधिकार और छूट के तहत नहीं आता।

जस्टिस चंद्रचूड़ और शाह की दो सदस्यीय पीठ ने सांसदों, विधायकों को सदन की कार्यवाही के दौरान मिली छूट और विशेषाधिकार के बारे में आए पूर्व के सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के बारे में आए फैसलों और कानून का विश्लेषण करते हुए कहा कि इससे साबित होता है कि कोर्ट और संसद दोनों मानते हैं कि विरोध के नाम पर सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना सहन नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने सदन में सदस्यों को मिली छूट और विशेषाधिकार के संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या और विश्लेषण किया है।

क्या है मामला पेज»5

सख्त तेवर

- केरल विस में हंगामा व तोड़फोड़ करने वाले माननीयों को बताई मर्यादा
- विरोध में संपत्ति को क्षति पहुंचाना विधायी कार्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट



सुप्रीम कोर्ट। फाइल/इंटरनेट मीडिया

67 नए मरीज राजधानी में कोरोना के बुधवार को मिले। तीन मरीजों की मौत हो गई है। 61 मरीज ठीक हुए, जबकि मरीजों के ठीक होने की दर 98.21 फीसद पर स्थिर बनी हुई है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 29 जुलाई, 2021

न्यूज गैलरी

विधानसभा का दो दिवसीय सत्र आज से

नई दिल्ली : दिल्ली विधानसभा का दो दिवसीय मानसून सत्र बृहस्पतिवार से शुरू होगा। सत्र के पहले दिन आम आदमी पार्टी विधायक नए पुलिस आयुक्त की नियुक्ति पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा का विषय रहेगा- नए पुलिस आयुक्त की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के विरुद्ध। इसके अलावा पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा को भारत रत्न देने के लिए भी सदन में चर्चा होगी। मानसून की बारिश में राजधानी में हुए भारी जलभराव के लिए नगर निगम की असफलता तथा राजधानी में चल रहे कृषि कानून विरोधी प्रदर्शन पर भी चर्चा होगी। मालूम हो कि इस संदर्भ में दिल्ली सरकार के वकीलों के पैनल को उपराज्यपाल द्वारा खारिज कर दिया गया है। मानसून सत्र में यह मामला भी तूल पकड़ सकता है। (राब्यू)

जेएनयू में आनलाइन होंगी मौखिक परीक्षाएं

नई दिल्ली : जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो एम जगदेश कुमार ने कहा कि प्रवेश परीक्षा की तारीखें घोषित हो गई हैं। विवि प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि प्रवेश परीक्षा परिणाम जारी होते ही दाखिले शुरू हों। दाखिले के दौरान मौखिक परीक्षा आनलाइन होगी। छात्रों को मौखिक परीक्षा की तिथि एवं समय की सूचना पूर्व में ही बता दी जाएगी। ताकि छात्र को कोरोना काल में यात्रा नहीं करनी पड़े। दाखिला लेने वाले छात्रों को विवि परिसर में प्रवेश तभी दिया जाएगा जब सरकार से अनुमति मिलेगी। (जासं)

जासूसी मामले में चीनी महिला को मिली जमानत

नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को स्वतंत्र पत्रकार राजीव शर्मा से जुड़े जासूसी मामले में चीनी महिला को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति योगेश खन्ना की पीठ ने निचली अदालत के आदेश को रद करते हुए चीनी महिला किंग शी को जांच अधिकारी को अपना पासपोर्ट सौंपने और एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत देने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि ऐसे में जबकि आरोप पत्र 60 दिनों की अवधि के बाद दायर किया गया है तो शी वैधानिक जमानत पाने की हकदार है। राजीव शर्मा को 14 सितंबर, 2020 को भारतीय खुफिया सूचनाओं साथ गिरफ्तार किया था। (जासं)

वकीलों पर छापेमारी के दिशा निर्देश तैयार करने की मांग

नई दिल्ली : अधिवक्ताओं के परिसरों में तलाशी और जब्ती अभियान चलाने के दौरान जांच एजेंसियों के लिए अनिवार्य दिशानिर्देश तैयार करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने केंद्र सरकार को मामले पर संक्षिप्त जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई तीन सितंबर को होगी। याचिका का विरोध करते हुए केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए एडिशनल सालिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि याचिकाकर्ता ने न तो जांच एजेंसियों को याचिका में पक्षकार नहीं बनाया है और उस वकील के नाम का खुलासा नहीं किया है जिसके परिसर की तलाशी की गई थी। (जासं)

आदेश की अवहेलना पर कोर्ट ने डीसीपी से मांगा जवाब

नई दिल्ली : दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की शिक्षक भर्ती परीक्षा में जाति सूचक प्रश्न पूछने के मामले में सत्र न्यायालय के आदेश की अवहेलना पर पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) से जवाब मांगा है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रवींद्र बेदी के कोर्ट ने अधिवक्ता डा. सत्य प्रकाश गौतम की अर्जी पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। अधिवक्ता ने अपनी अर्जी में पुलिस पर कोर्ट के आदेश के बाद भी मुकदमा दर्ज न करने का आरोप लगाया है। साथ ही दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है। (जासं)

दो दिनों की बारिश से ठंडे पड़े गर्मी के तेवर

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

- बुधवार को भी अलसुबह से शुरू होकर रुक रुककर शाम तक बरसते रहे बदरा
- सात डिग्री गिरा पारा, पिछले 10 सालों में 28 जुलाई रहा सबसे ठंडा

मंगलवार के बाद बुधवार की भी झमाझम बारिश ने दिल्ली की फिजा ही बदलकर रख दी। उमस भरी गर्मी से तो दिल्ली वासियों को खासी राहत मिली ही, अधिकतम तापमान में भी सात डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। पिछले 10 सालों में 28 जुलाई का दिन सबसे ठंडा रहा। आलम यह रहा कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान में सिर्फ ढाई डिग्री का अंतर रह गया।

बुधवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से सात डिग्री कम 27.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड हुआ। 2011 से लेकर पिछले 10 सालों में 27 जुलाई का यह सबसे कम अधिकतम तापमान है। न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम 25.1 डिग्री दर्ज किया गया। हवा में नमी का स्तर 84 से 100 फीसद रहा। खास बात यह कि बुधवार को अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान में केवल 2.5 डिग्री का अंतर दर्ज किया गया। बारिश सुबह साढ़े आठ से शाम साढ़े पांच बजे तक 4.1 मिमी दर्ज की गई। रिज में सर्वाधिक 32.6 मिमी बारिश रिकार्ड हुई।


बारिश के कारण गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन सड़कों पर जाम की समस्या भी रही। बुधवार को कश्मीरी गेट बस अडडे से चंदगीराम अखाड़े की ओर जाने वाले मार्ग पर जाम का नजारा। ध्रुव कुमार

मौसम विभाग के मुताबिक बृहस्पतिवार को भी बादल छाए रहेंगे। मध्यम स्तर की बारिश होने के आसार हैं। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 29 और 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। बृहस्पतिवार के लिए आरेंज, जबकि शुक्रवार और शनिवार के लिए यलो अलर्ट भी जारी किया गया है।

कई जगह अधिकतम और न्यूनतम तापमान में रहा नाममात्र का अंतर

दिल्ली के ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान में काफी कम अंतर देखा गया। जाफरपुर में तो यह अंतर नहीं के बराबर था। यहां का अधिकतम तापमान 26.4, जबकि न्यूनतम तापमान 26.1 डिग्री सेल्सियस रहा। इसी तरह मुंगेशपुर में अधिकतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

कहां कितनी हुई बारिश	
सफदरजंग	4.1 मिमी
पालम	26.8 मिमी
लोधी रोड	6.0 मिमी
रिज	32.6 मिमी
आयानगर	22.4 मिमी

(आंकड़े सुबह साढ़े आठ से शाम साढ़े पांच बजे तक के)

फिजाओं की रवानी में हवा हुई ज्यादा सुहानी

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

- बुधवार को दिल्ली एनसीआर में सभी जगह संतोषजनक श्रेणी में रहा एयर इंडेक्स
- सफर इंडिया का पूर्वानुमान, अगले कई दिन तक मौसम ऐसे ही बने रहने के हैं आसार

मंगलवार के बाद बुधवार को हुई झमाझम बारिश ने दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण का दाग धो डाला है। सुनहरी घटाओं और झोंकेदार हवा के साथ तेज बारिश से एनसीआर में सभी जगह की हवा सुधरकर संतोषजनक श्रेणी में आ गई है। प्रदूषण से राहत का यह दौर अभी कई दिन बरकरार रहने की संभावना है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा जारी एयर क्वालिटी बुलेटिन के अनुसार बुधवार को एनसीआर में सभी जगहों का एयर इंडेक्स 100 से नीचे दर्ज किया गया। इस श्रेणी की हवा को संतोषजनक कहा जाता है। वहीं सफर इंडिया का अनुमान है कि बारिश का यह दौर चूंकि इस पूरे सप्ताह ही जारी रहने के आसार हैं तो ऐसे में वायु प्रदूषण भी अभी नहीं बढ़ेगा।

दिल्ली-एनसीआर का एयर इंडेक्स	
दिल्ली	61
फरीदाबाद	56
गाजियाबाद	57
ग्रेटर नोएडा	74
गुरुग्राम	69
नोएडा	54

अनधिकृत कालोनियों में लैंड पूलिंग की तर्ज पर होगा विकास

बढ़े कदम ▶ 1,731 कालोनियों को नियमित करने के प्रयास

निवासी भी भूखंडों को जोड़कर आवासीय इकाइयों का कर सकेंगे पुनर्विकास

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

मालिकाना हक देने की शुरुआत करने के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) अब अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने की दिशा में भी कदम आगे बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में इन कालोनियों के नए विकास मानक भी जल्द अधिसूचित हो सकते हैं। इनके तहत इन कालोनियों में भी लैंड पूलिंग नीति की तर्ज पर विकास हो सकेगा।

1,731 अनधिकृत कालोनियों के निवासियों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक देने की शुरुआत तो डीडीए 16 दिसंबर, 2019 को ही कर चुका है, लेकिन विभिन्न कानूनी अड़चनों के कारण इन कालोनियों को नियमित करने में मुश्किलें आ रही हैं। लिहाजा, अब इन कालोनियों में लैंड पूलिंग नीति की तरह छोटे-छोटे भूखंडों को आपस में जोड़कर ग्रुप हाउसिंग सोसायटी की तर्ज पर कालोनियों का पुनर्विकास किया जाएगा। इसके संबंध में इन सीटू डेवलपमेंट यानि जो जहां जैसा है, उसे वहीं पर पुनर्विकसित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है।


अनधिकृत कालोनी। फाइल फोटो

अनधिकृत कालोनियों के लिए विकास मानकों को योजनाबद्ध विकास हेतु मार्ग तैयार करने के लिए बनाया गया है। अलग-अलग मानकों 6के साथ द्विस्तरीय दृष्टिकोण को तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य किफायती किराये के मकान मुहैया कराने के साथ ही पर्यावरण व सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना है।

इन मानकों को दिसंबर 2020 में हुई डीडीए की बैठक में अनुमोदित किया गया। फिर जनता से सुझावों और स्थानीय निकायों से चर्चा के आधार पर इनको संशोधित कर दिल्ली विकास अधिनियम की धारा-11क के तहत केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय को भेज दिया गया है। वहां से स्वीकृति मिलते ही इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।

नए मानकों के अनुसार अनधिकृत कालोनियों का विकास करने के लिए दो विकल्प तैयार किए गए हैं। पहला, भूखंडों के समायोजन को बढ़ावा देकर और निर्धारित मापदंडों के साथ भूमि के मूल मालिकों की भागीदारी सुनिश्चित करके कालोनियों का पुनर्विकास किया जाए। दूसरा, न्यूनतम प्लानिंग जरूरतों को पूरा करते हुए मौजूदा कालोनियों का नियमितीकरण किया जाए।

जानकारी के मुताबिक इन कालोनियों के लोग दो हजार वर्गमीटर भूखंड को जोड़कर उसमें 300 एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) पा सकेंगे। 30 फीसद क्षेत्र में हरित क्षेत्र सहित पार्क वगैरह होंगे। 10 फीसद क्षेत्र का व्यावसायिक उपयोग किया जा सकेगा और 10 फीसद क्षेत्र में सामुदायिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा। यहां सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 12 मीटर होनी चाहिए। स्लम एवं जेजे कलस्टर के लिए भी यही मानक हैं बस वहां पर एफएआर थोड़ा ज्यादा यानि 400 रखा गया है। शहरीकृत गांवों में भूखंड जोड़ने की न्यूनतम सीमा 1,670 वर्ग मीटर रखी गई है। यहां सड़क की चौड़ाई साढ़े सात मीटर होनी चाहिए।

डीडीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नए मानकों को लेकर केंद्र सरकार की अधिसूचना जारी होने के बाद इन कालोनियों में विकास कार्य भी गति पकड़ने लगेंगे।

लुटियंस दिल्ली में कम होती हरियाली का पता लगाएगी एनडीएमसी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) इलाके में लगातार हरियाली कम हो रही है। इसको लेकर अधिकारी अब चिंतित हैं। जल्द ही एक सर्वे शुरू कर पेड़ों के कम होने का पता लगाया जाएगा कि आखिर लुटियंस दिल्ली में क्यों पेड़ों की संख्या कम हो रही है। साथ ही विरासत वाले 300 पेड़ भी कम हुए हैं, जिसके बारे के कारणों अध्ययन भी एनडीएमसी करेगी।

अधिकारियों के मुताबिक पिछले छह वर्षों में लगभग 300 विरासत पेड़ों सहित कुल 1,813 पेड़ों की संख्या कम हुई है। इसके कारण राष्ट्रीय राजधानी के इस इलाके की हरियाली अब कम हो रही है। अधिकारियों ने शुरुआती जांच में पाया है कि कंक्रीट के जंगल बढ़ने, बार-बार सड़क काटने, दीमक और मिट्टी के प्रकार (रेतीली बजरी मिट्टी) के कारण पेड़ उखाड़ रहे हैं। एनडीएमसी क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री और सांसदों के अलावा कई शीर्ष उद्योगपतियों के घर हैं, जहां वह रहते हैं। इसके अलावा मंत्रालयों के भवन, संसद भवन, सर्वोच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के आवास भी बने हुए हैं।

आंकड़ों के अनुसार, लुटियंस की दिल्ली में प्रति वर्ष 250 से अधिक पेड़ गिर रहे हैं। 2015 से इस क्षेत्र ने अब तक 1,813 पेड़ खो दिए हैं। एनडीएमसी के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2015-16 और 2021-22 के बीच 1,813 पेड़ों में से लगभग 300 विरासत पेड़ भी नष्ट हो गए हैं।

इनमें 60 से अधिक नीम के पेड़ के साथ गुलमोहर, पीपल व पिलखन समेत अन्य प्रकार के पेड़ हैं।

राकेश अस्थाना ने संभाला दिल्ली पुलिस आयुक्त का पदभार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- दिल्ली पुलिस के 24वें आयुक्त बने गुजरात कैडर के 1984 बैच के वरिष्ठ आइपीएस अस्थाना
- बालाजी श्रीवास्तव के पास अब केवल विजिलेंस की रहेगी जिम्मेदारी

1984 बैच के गुजरात कैडर के वरिष्ठ आइपीएस राकेश अस्थाना ने दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त के रूप में पदभार संभाल लिया है। इससे पहले वे सीमा सुरक्षा बल के निदेशक पद पर तैनात थे। मंगलवार देर रात गृह मंत्रालय ने उन्हें वहां से हटाकर दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी। बुधवार दोपहर उन्होंने मुख्यालय पहुंच कर पदभार ग्रहण कर लिया। वे दिल्ली पुलिस के 24वें आयुक्त बने हैं। अस्थाना का कार्यकाल 30 जुलाई तक ही बचा था। ऐसे में मंत्रालय ने उन्हें आयुक्त बनाने के साथ ही एक साल का सेवा विस्तार भी दिया है। वे 31 जुलाई, 2022 तक आयुक्त रहेंगे।

अस्थाना केंद्र सरकार के बेहद करीबी माने जाते हैं। ऐसे में बेहतर काम करने पर उन्हें दोबारा भी सेवा विस्तार दिया जा सकता है। दोपहर 1:44 बजे वे जय सिंह रोड स्थित पुलिस मुख्यालय पहुंचे। वहां पहले उनका गार्ड आफ आनर देकर स्वागत किया गया फिर दूसरी मंजिल पर जाकर उन्होंने पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के चंद मिनट बाद ही अस्थाना ने मीडिया कर्मियों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस का बेसिक काम कानून व्यवस्था को मजबूत रखने के अलावा अपराध पर रोक लगाना व अपराध के बारे में पता लगाना होता है। उनका फोकस बेसिक पुलिसिंग पर अधिक रहेगा। उन्होंने कहा कि मेरी जहां तक समझ है अगर हम यह काम करेंगे तो जनता को संतुष्टि मिलेगी और कानून व्यवस्था मजबूत रहेगी। बाकी जो अलग-अलग तरह की समस्याएं आएंगी उससे हम निपटते रहेंगे। दिल्ली पुलिस बहुत ही शानदार व पेशेवर फोर्स के तौर पर जानी जाती है। दिल्ली पुलिस का बड़ा नाम है। बड़े से बड़े मामलों को दिल्ली पुलिस ने सुलझाया है। मुझे पूरी उम्मीद व भरोसा है कि हम एक टीम की तरह से काम करेंगे और दिल्ली में बेहतर कानून व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास करेंगे।


पुलिस मुख्यालय में पदभार ग्रहण करते नवनियुक्त पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना। जागरण

उधर, बालाजी श्रीवास्तव के पास अब केवल विजिलेंस की जिम्मेदारी रहेगी। एसएन श्रीवास्तव का कार्यकाल पूरा होने के बाद 31 जून को बालाजी श्रीवास्तव ने पुलिस आयुक्त का अतिरिक्त कार्यभार संभाला था। वे महज 27 दिनों तक आयुक्त रहे। दिल्ली पुलिस के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब 27 दिनों के अंदर पुलिस आयुक्त को हटा दिया गया हो।

दिल्ली सरकार ने शुरू किया एपीजे स्कूल प्रबंधन का टेकओवर

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

- फीस वृद्धि वापस लेने के आदेश का उल्लंघन करने पर स्कूल को भेजा गया नोटिस
- मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने टेकओवर के प्रस्ताव को दी मंजूरी, फाइल एलजी के पास भेजी

दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने शेख सराय स्थित एपीजे स्कूल के प्रबंधन को अपने हाथ में लेने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्णय लिया है। सरकार मनमाने तरीके से बढ़ाई गई फीस को वापस लेने के लिए कई बार आदेश जारी कर चुकी है, लेकिन स्कूल प्रबंधन उन आदेशों का पालन करने में हर बार विफल रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एपीजे स्कूल के प्रबंधन को अपने हाथ में लेने के लिए शिक्षा निदेशालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब यह फाइल एलजी के पास भेजी गई है।

शिक्षा निदेशालय ने वित्तीय वर्ष 2012-2013 से 2018-2019 के लिए एपीजे स्कूल के वित्तीय विवरण का निरीक्षण किया था। उसमें पाया गया कि 2018-2019 के लिए स्कूल के पास कुल धनराशि 49,72,45,586 रुपये थी। इस धनराशि में से 18,87,02,422 रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया गया था। 18,87,02,422 रुपये खर्च होने के बाद भी स्कूल प्रबंधन के पास करीब 30,85,43,164 रुपये की धनराशि शुद्ध रूप से सरप्लस में थी। इसके बाद विभाग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि स्कूल प्रबंधन को अभी फीस बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2018-2019 और 2019-2020 के लिए स्कूल द्वारा प्रस्तावित शुल्क ढांचे को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। इसके बाद निदेशालय ने स्कूल को नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों न स्कूल की मान्यता रद कर दी जाए या फिर सरकार क्यों न स्कूल का प्रबंधन अपने हाथ में ले ले।

28 दिन में परीक्षा परिणाम जारी कर डीयू ने रचा इतिहास

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- डीयू के इतिहास में पहली बार इतने कम समय में जारी हुए परिणाम
- जून महीने में हुई थीं अंतिम वर्ष की परीक्षाएं

कोरोना काल में दिल्ली विश्वविद्यालय के खाते में एक नायाब उपलब्धि जुड़ गई है। डीयू ने परीक्षा समाप्ति के महज 28 दिनों के अंदर अंतिम वर्ष के सभी पाठ्यक्रमों का परिणाम जारी कर दिया है। ऐसा डीयू के इतिहास में पहली बार हुआ है। डीयू के कार्यवाहक कुलपति प्रो. पीसी जोशी ने परीक्षा विभाग के डीन प्रो. डीएस रावत समेत अन्य पदाधिकारियों से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी।

डीयू प्रशासन ने बताया कि सात जून को ओपन बुक परीक्षाएं शुरू हुई थीं, जिसमें 72 हजार परीक्षार्थी बैठे। परीक्षा परिणाम जल्द जारी करने के लिए डीयू ने इस बार पूरी परीक्षा प्रणाली में चार अहम बदलाव किए थे। परीक्षा विभाग के डीन प्रो. डीएस रावत ने कहा 'कापियां असाइन करने के लिए हमारे पास शिक्षकों का एक डेटा मौजूद होता है, जिसमें कुछ खामियां थीं। दरअसल, परीक्षा से पहले हम प्रत्येक कालेज से उनके यहां पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम एवं संबंधित शिक्षक की जानकारी मांगते हैं ताकि परीक्षा के बाद कापियां संबंधित शिक्षक को असाइन की जा सके। कई बार ऐसा होता था कि कापियां असाइन करने के बाद जांची नहीं जाती तो हम कारण पूछते हैं। पता चलता है कि शिक्षक को तो कापियां असाइन ही नहीं हो पाई हैं। इसके पीछे ईमेल आइडी गलत होना भी वजह था। इस बार डीयू ने तय किया कि कालेज जो भी डेटा तैयार करेंगे वो पहले संबंधित शिक्षक से ही सत्यापित कराएंगे। इससे गलती की गुजांइश खत्म हो गई।'


रिकार्ड समय में परीक्षा परिणाम जारी करने पर परीक्षा विभाग के सदस्यों के साथ पहली पंक्ति में डीयू के कार्यवाहक कुलपति प्रो. पीसी जोशी (दाएं से पांचवें), डीन आफ कालेज प्रो. बलराम पाणि (दाएं से चौथे) व परीक्षा विभाग के डीन प्रो. डीएस रावत (दाएं से तीसरे)। सौ. परीक्षा विभाग

कापी जांचने की प्रक्रिया में सुधार : बकौल रावत दूसरा अहम बदलाव कापी जांचने की प्रक्रिया में किया गया। 7 जून से अंतिम वर्ष के छात्रों की ओपन बुक परीक्षाएं शुरू हुई थीं। डीयू में चलन था कि परीक्षा समाप्त होने के बाद कापियां जांचने का काम शुरू होता था, लेकिन पहली बार तीन दिन बाद यानी 10 जून से ही कापियां जांचनी शुरू कर दी गई थीं। डीयू ने इस बार शिक्षकों को प्रोत्साहन सर्टिफिकेट दिया। तय समय में कापी जांचने वाले शिक्षक को सर्टिफिकेट दिया गया। इसका सकारात्मक असर दिखा। साथ ही चौथा व अहम बदलाव एक कमेटी के गठन के रूप में किया गया। परीक्षा विभाग ने एक 14 सदस्यीय कमेटी गठित की थी जो निगरानी करती थी कि किस पाठ्यक्रम की कापियां असाइन करने के बाद भी नहीं जांची गईं। सदस्य संबंधित शिक्षक से बात करते एवं यदि जरुरत होती तो किसी और को असाइन किया जाता। डीयू ने 15 अगस्त डेडलाइन तय की थी, लेकिन इसके पहले ही सभी परीक्षा परिणाम जारी कर दिए गए। सनद रहे कि गत वर्ष परीक्षा परिणाम जल्द जारी करने की मांग को लेकर छात्रों ने अदालत का दरवाजा भी खटखटाया था।

1,078 करोड़ की लागत से पांच माह में बनेंगे 6,834 आइसीयू बेड

वीके शुक्ला, नई दिल्ली

- ये निर्माण कंक्रीट की जगह स्टील के फ्रेम में तैयार किए जाएंगे
- लोक निर्माण विभाग ने जारी किए टेंडर, तीन चरण में होंगे तैयार

दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर इससे निपटने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग ने 6,834 आइसीयू बेड तैयार करने की योजना बनाई है। इस कार्य के लिए करीब 1,078 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत आएगी। लोक निर्माण विभाग का दावा है कि इन्हें पांच माह में तैयार कर लिया जाएगा। विभाग ने इसके लिए टेंडर जारी कर दिए हैं। ये निर्माण कंक्रीट की जगह स्टील के फ्रेम में तैयार किए जाएंगे। अस्पतालों के मामले में यह पहला प्रयोग है।

दिल्ली सरकार ने दूसरी लहर में अधिकतम 15 हजार कोरोना के मरीज प्रतिदिन आने के हिसाब से योजना बनाई थी। विशेषज्ञों की सलाह पर सरकार ने योजना तैयार की थी, क्योंकि पहली लहर में एक दिन में 8,500 ही अधिकतम मरीज आए थे। मगर दूसरी लहर में व्यवस्थाएं उस समय चौपट हो गईं, जब एक दिन में 27 हजार तक मरीज आ गए। दूसरी परेशानी आइसीयू और आक्सीजन बेड की कमी को लेकर हुई। लोग तड़पते रहे और उन्हें बेड नहीं मिल सके। इसी सब को देखते हुए दिल्ली सरकार ने पिछले माह स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए थे कि आइसीयू बेड शीघ्र कैसे तैयार हो सकें, इस पर काम करें, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने 6,834 अस्थायी आइसीयू बेड तैयार करने की योजना बनाई है। इस कार्य तीन चरण में होगा। पहले चरण में 2,413, दूसरे चरण में 2,508 और तीसरे चरण में 1,913 बेड तैयार किए जाएंगे। ये सभी बेड दिल्ली सरकार के पहले से चल रहे अस्पतालों में तैयार किए जाएंगे।

यहां बनेंगे बेड

स्थान	बेड संख्या
शालीमार बाग	1,430
किराड़ी	458
सुल्तानपुरी	525
नेहरू बाल चिकित्सालय	596
जीटीबी परिसर	1,912
सरिता विहार	336
रघुवीर नगर	1,577

आनलाइन गेम्स के विनियमन पर निर्णय करे केंद्र सरकार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को आनलाइन गेम्स के विनियमन पर निर्णय लेने को कहा है। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने केंद्र सरकार से बच्चों को आनलाइन गेम्स की लत लगने से बचाने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग को लेकर दायर याचिका को प्रतिवेदन के तौर पर लेकर उचित निर्णय करने को कहा है।

एनजीओ डिस्ट्रेस मैनेजमेंट कलेक्टिव ने याचिका दायर कर कहा कि आनलाइन गेम्स के कारण बच्चों पर पड़ रहे असर के संबंध में माता-पिता से कई शिकायतें मिल रही हैं। बच्चों के आत्महत्या करने या अवसाद में जाने और आनलाइन गेम के कारण चोरी जैसे अपराध भी बच्चे कर रहे हैं। आनलाइन कक्षाओं के कारण बच्चों को मोबाइल से दूर भी नहीं रखा जा सकता और इस कारण बच्चों को मोबाइल की लत लगती जा रही है।

पुलिस पर 25 हजार रुपये के जुर्माना पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली :

- पुलिस की चुनौती याचिका पर शिकायतकर्ता से मांगा जवाब
- पुलिस को दिया जुर्माना राशि जमा नहीं करने का आदेश

दिल्ली दंगा से जुड़े एक मामले में सत्र न्यायालय की तरफ से दिल्ली पुलिस पर तल्ख टिप्पणी करते हुए 25 हजार रुपये जुर्माना लगाने के फैसले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि सभी पक्षों को सुने बिना टिप्पणी को तो नहीं हटाया जा सकता है, लेकिन जुर्माने की राशि अगली सुनवाई तक जमा करने की जरूरत नहीं है। पीठ ने शिकायतकर्ता मोहम्मद नासिर को नोटिस जारी कर 10 दिन के अंदर जवाब देने को कहा है।

यह था मामला : शिकायतकर्ता मोहम्मद नासिर का दावा है कि दिल्ली दंगा में एक गोली लगने के कारण उनकी एक आंख की रोशनी चली गई। उन्होंने इस मामले में पुलिस को शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया और न कोई कार्रवाई की, जिसके बाद उन्होंने मेट्रोपालिटन कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई, जहां कोर्ट ने पुलिस को केस दर्ज करने का आदेश दिया। पुलिस ने मेट्रोपालिटन कोर्ट के आदेश को कड़कड़डूमा सत्र न्यायालय में चुनौती दी, जिस पर सुनवाई के दौरान 14 जुलाई को सत्र न्यायालय ने कहा कि जांच बहुत ही लापरवाह ढंग से की गई है और पुलिस डायरी लिखने में नियमों का पालन नहीं किया गया है। अदालत ने इस मामले में केस दर्ज करने और पुलिस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया।



दिल्ली हाई कोर्ट। फाइल फोटो

पुलिस ने बताया हो चुकी है जांच : पुलिस ने अपने जवाब में स्पष्ट किया था कि इस घटना को लेकर पहले ही प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है और इसमें शिकायतकर्ता के नाम का भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा शिकायतकर्ता ने जिन सात व्यक्तियों के नाम बताए हैं उनके खिलाफ जांच में कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं।

24 घंटे काम करने वाली हेल्पलाइन की शुरुआत की है राष्ट्रीय महिला आयोग ने घरेलू हिंसा व यौन उत्पीड़न का सामना करने वाली महिलाओं की मदद के लिए। हेल्पलाइन नंबर 7827170170 पीड़िताओं को उनकी जरूरत के मुताबिक अधिकारियों से संपर्क करवाएगा।

'पेगासस जासूसी पर संसद में चर्चा नहीं चाहती है सरकार'

सियासत ▶ राहुल गांधी ने लगाया आरोप, कहा– संसद में हंगामे के लिए विपक्ष को किया जा रहा बदनाम

बहस की मांग से पीछे नहीं हटेगा विपक्ष, सरकार बताए– पेगासस स्पाइवेयर खरीदा या नहीं

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पेगासस जासूसी कांड को लेकर विपक्षी दलों की मजबूत गोलबंदी को देखते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर हमला तेज कर दिया है। पेगासस कांड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा कि पीएम ने हम सभी के फोन में हथियार डाल दिए हैं और इसको लेकर संसद में चर्चा होनी चाहिए। मगर सरकार सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस मामले की जांच ही नहीं, संसद में इस पर बहस कराने से भी इन्कार कर रही है। संसद में गतिरोध के लिए विपक्ष को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है और उसकी आवाज को दबाया जा रहा है। राहुल ने कहा कि विपक्षी दल अपने रुख से पीछे नहीं हटने वाले।

विपक्षी दलों के नेताओं के साथ विजय चौक पर मीडिया से रूबरू होते हुए राहुल ने कहा कि विपक्ष का सिर्फ एक सवाल है कि सरकार ने पेगासस स्पाइवेयर खरीदा या नहीं और इस उपकरण का इस्तेमाल लोगों पर किया गया है या नहीं। संसद में गतिरोध के संदर्भ में उन्होनें कहा कि सरकार ने विपक्ष को साफ बताया है कि पेगासस पर संसद में कोई भी बातचीत नहीं होगी। उन्होंने जानना चाहा कि सदन में पेगासस पर बात क्यों नहीं होनी चाहिए? संसद की कार्यवाही बाधित करने के सरकार के आरोपों को खारिज करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष संसद के कामकाज में व्यवधान नहीं डाल रहा, बल्कि अपनी जिम्मेदारी निभा रह है। केवल कांग्रेस नहीं सभी विपक्षी दलों के नेता बोल रहे हैं कि जिस हथियार का इस्तेमाल आतंकवादियों-देशद्रोहियों के खिलाफ होना चाहिए, उसका इस्तेमाल भारत के लोकतंत्र और उसकी संस्थाओं के खिलाफ किया गया है।


नई दिल्ली में पेगासस जासूसी कांड को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं के साथ विजय चौक पर मीडिया से रूबरू कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी। एएनआइ

विपक्ष के खिलाफ दुष्प्रचार कर रही सरकार

इस मौके पर मौजूद सपा नेता रामगोपाल यादव और शिवसेना के संजय राउत ने कहा कि सरकार यह झूठ प्रचारित कर रही है कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। सच्चाई है कि विपक्ष पहले दिन से पेगासस पर बहस की मांग उठा रहा है क्योंकि इस जासूसी में किसी संस्था को नहीं छोड़ा गया है और इसका सच जनता के सामने आना चाहिए। द्रमुक के टीआर बालू और एनसीपी की सुप्रिया सुले समेत विपक्षी खेमे के दूसरे नेताओं ने भी राहुल गांधी की बातों का समर्थन किया।

'फोन में है जासूसी हथियार तो कराएं एफआइआर'

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पलटवार
- विपक्षी एकता पर भी कसा तंज, कहा- पहले भी हुई एकता की कोशिशों को नकार चुकी है जनता
- केरल में कोरोना के बेकाबू होने के लिए तुष्टीकरण की नीति को ठहराया जिम्मेदार

पेगासस जासूसी को लेकर खड़े हुए विवाद के बीच भाजपा ने राहुल गांधी को चुनौती दी है कि उनके फोन में जासूसी का साफ्टवेयर डाला गया है कि तो एफआइआर क्यों नहीं करवाते। कोरोना जैसे मुद्दे पर चर्चा करने से भागने व संसद को ठप करने पर विपक्ष पर हमला करते हुए केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह देश को बदनाम करने की साजिश चल रही है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने याद दिलाया कि दूसरी लहर के दौरान विपक्षी दल विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे थे, लेकिन अब संसद ठप कर रहे हैं। उन्होंने केरल में कोरोना की नई लहर के लिए राज्य सरकार की तुष्टीकरण की नीति को जिम्मेदार बताया, जिसमें बकरीद के पहले प्रतिबंधों में ढील दे गई थी।

मानसून सत्र में डेढ़ सप्ताह का वक्त गुजर चुका है और सदन की कार्यवाही ठप है। ऐसे में अनुराग ठाकुर ने कहा कि सदन में बहस नहीं होने दी जा रही है। पीठासीन अधिकारियों पर कागज के टुकड़े उछाले जा रहे हैं। पीएम कह चुके हैं कि सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं लेकिन विपक्ष किसी खास मंशा से इसे रोक रहा है। यह देश को बदनाम करने की साजिश है। वहीं, पात्रा ने सरकार के खिलाफ विपक्षी एकजुटता के राहुल के बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि विपक्षी एकता की ऐसी कोशिशों को जनता पहले भी नकार चुकी है। उनके अनुसार 2017 में उप्र विस चुनाव के पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव ऐसी एकजुटता दिखा रहे थे, जिसे जनता ने सिरे से नकार किया। उसके बाद 2018 कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद में सभी विपक्षी नेताओं ने मंच पर एक साथ फोटो खिंचवाकर एकजुटता का परिचय दिया था और 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले भी विपक्षी एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जनता ने उसे स्वीकार नहीं किया।

परिवारिक हितों को बचाने की कोशिश : भाजपा ने आरोप लगाया कि पार्टियां विपक्षी एकजुटता के नारे की आड़ में अपने-अपने परिवार के हितों को बचाने की कोशिश कर रही हैं। संबित पात्रा ने कहा कि आरजेडी, सपा, शिवसेना और यहां तक कि कांग्रेस में परिवार के हितों को बचाने की कवायद जारी है।

कोरोना पर चर्चा से भाग रहा विपक्ष : पात्रा ने कहा कि पूरी दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती कोरोना की है और सरकार इस पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन दूसरी लहर के दौरान अपने घरों में दुबके रहने वाले नेता इससे बचने के लिए संसद को चलने नहीं दे रहे हैं।

राहुल की तरह ही उनके अनुयायी भी गैर जिम्मेदार : पेगासस मुद्दे पर चर्चा से भागने के राहुल के आरोप का जवाब देते हुए पात्रा ने कहा कि विपक्ष ने सदन के भीतर आइटी मंत्री अश्विनी वैष्णव को पेगासस की सच्चाई बताने नहीं दिया और उनके हाथ से कागज लेकर फाड़ दिया। राहुल गांधी को गैर-जिम्मेदार बताते हुए उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह सरकार के अध्यादेश को फाड़ कर राहुल गांधी ने जिस गैर-जिम्मेदाराना रवैये का परिचय दिया था, उनके अनुयायी उसी रास्ते पर चल रहे हैं।


अनुराग ठाकुर। फाइल


संबित पात्रा। फाइल

कोरोना प्रोटोकाल की उड़ा रहे धज्जियां : कोरोना के खिलाफ लड़ाई में गैर-जिम्मेदाराना रवैये को लेकर विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए पात्रा ने कहा कि जहां उप्र और उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद केरल ने तुष्टीकरण के लिए बकरीद पर प्रतिबंधों में ढील दी। नतीजा सामने है। देश में प्रतिदिन कुल नए केस में आधे केरल से आ रहे हैं। इसी तरह से राजस्थान में स्कूल-कालेज बंद हैं, वहां के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने इनडोर स्टेडियम में जन्मदिन की पार्टी दी, जिसमें कोरोना प्रोटोकाल की धज्जियां उड़ाते हुए सैकड़ों लोग शामिल हुए।

पांच बार स्थगित हुई कार्यवाही

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

प्रश्नकाल खत्म होते ही स्पीकर चले गए और भाजपा के राजेंद्र अग्रवाल आसन पर बैठे और कार्यवाही का संचालन शुरू किया। इस पर कांग्रेस तथा कुछ अन्य विपक्षी सदस्य इस पर भड़क गए और कार्यसूची से जुड़े कागजातों को फाड़कर उछालने लगे। कुछ पर्चे आसन की ओर तो कुछ सत्तापक्ष की ओर फेंके गए। तब अग्रवाल ने सदन को 12.30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया और इसके बाद पांच बार के व्यवधान के बाद शाम चार बजे लोकसभा पूरे दिन के लिए ठप हो गई।

विपक्ष के हंगामे को अनसुना करते हुए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अनुपूरक मांगों के साथ विनियोग विधेयक और दिवालिया कानून में संशोधन से जुड़े विधेयक पारित करा लिए। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ बताया तो सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए विपक्ष पर संसद में बहस से भागने और मंत्रियों को जवाब देने से रोकने का आरोप लगाया। संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी ने भी कहा कि हंगामे के अलावा विपक्ष के पास कोई मुदद‌ा ही नहीं है जिस पर वह चर्चा करे।

राज्यसभा में मुश्किल से चला प्रश्नकाल

रास में भी कार्यवाही को शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद हंगामे के चलते स्थगित करना पड़ा। उपसभापति हरिवंश ने 12 बजे शुरू हुए प्रश्नकाल को करीब 40 मिनट तक भारी शोर-शराबे में ही चलाया और फिर दो बजे तक सदन स्थगित हुआ। महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने किशोर न्याय, देखभाल-संरक्षण संशोधन विधेयक को शोर-शराबे में ही ध्वनिमत से पारित करा लिया। तृणमूल के डेरेक ओब्रायन ने इस पर वोटिंग की मांग। पीठासीन सभापति भुवनेश्वर कलिता ने उनकी मांग नहीं मानी और विधेयक को पारित किए जाने का एलान करते हुए सदन को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया।

उचित समय पर जम्मू-कश्मीर को दिया जाएगा पूर्ण राज्य का दर्जा : केंद्र

▶ 2019 के मुकाबले 2020 में आतंकवाद में आई 59 फीसद कमी

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार ने बुधवार को संसद में कहा कि जम्मू-कश्मीर को वहां हालात सामान्य होने के बाद उचित समय पर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उनसे पूछा गया था कि क्या जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का सरकार का कोई प्रस्ताव है और क्या वहां संचार के विभिन्न माध्यमों पर करीब एक साल से जारी प्रतिबंध हटाने के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं।

राय ने बताया कि राष्ट्रहित और जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा के हित में पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य के दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर व लद्दाख में विभाजन और वहां संवैधानिक बदलावों को देखते हुए मोबाइल सेवाओं व इंटरनेट जैसे संचार के विभिन्न चैनलों पर पाबंदिया लगाई गई थीं। ये पाबंदियां अस्थायी थीं। समय-समय पर हालात की समीक्षा की गई और धीरे-धीरे पाबंदियां हटा दी गईं। उन्होंने बताया कि पांच फरवरी से पूरे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में 4जी इंटरनेट सेवाएं बहाल की जा चुकी हैं। याद दिला दें कि केंद्र सरकार ने 2019 में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 को समाप्त कर दिया था।

एक अन्य सवाल के लिखित जवाब में राय ने बताया, '2019 के मुकाबले 2020 में राज्य में आतंकी घटनाओं में 59 फीसद की कमी आई, जबकि जून, 2021 तक इसी अवधि में पिछले साल के मुकाबले आतंकी घटनाओं में 32 फीसद की कमी दर्ज की गई है।' उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर में दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सार्वजनिक परिवहन, सरकारी कार्यालय, शिक्षण एवं स्वास्थ्य संस्थाएं सामान्य रूप से काम कर रही हैं।

कश्मीरी पंडितों पर पूछे गए सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री ने कहा कि कश्मीरी पंडितों ने हाल के दिनों में ज्यादा सुरक्षित महसूस किया है जो इस तथ्य से साबित होता है कि 3,841 कश्मीरी युवा कश्मीर वापस लौट गए हैं और प्रधानमंत्री पुनर्वास पैकेज के तहत कश्मीर के विभिन्न जिलों में नौकरियां कर रहे हैं। इसी योजना के तहत अप्रैल में 1,997 और अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, जल्द ही वे भी कश्मीर पहुंच जाएंगे।

उन्होंने बताया कि कश्मीर लौटने वाले इन युवाओं को आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने व्यापक नीति तैयार की है। उनके लिए 6,000 रिहायशी इकाइयों का तेज गति से निर्माण किया जा रहा है और एक हजार रिहायशी इकाइयों का इन कर्मचारियों द्वारा पहले से इस्तेमाल किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कश्मीरी पंडितों और डोगरा हिंदू परिवारों समेत ऐसे करीब 900 परिवार कश्मीर में रह रहे हैं।

मेडिकल कोटे में आरक्षण की मांग लेकर पीएम से मिले ओबीसी सांसद और मंत्री


नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपते केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, अनुप्रिया पटेल, आरसीपी सिंह सहित अन्य ओबीसी सांसद। सौ. पीआइबी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ नीट के तहत तय होने वाले आल इंडिया कोटे में अभी ओबीसी को नहीं मिलता आरक्षण

उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों में निकट भविष्य में होने वाल विधानसभा चुनाव से पहले मेडिकल में दाखिले की आल इंडिया कोटे की सीटों में ओबीसी को आरक्षण की देने की मांग तेज हो गई है। केंद्रीय श्रम व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय स्टील मंत्री आरसीपी सिंह के नेतृत्व में अनुप्रिया पटेल व अन्य ओबीसी सांसदों और मंत्रियों ने बुधवार को इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। साथ ही उनका ध्यान आरक्षण की विसंगति की ओर खींचा, जिसके तहत मेडिकल कालेजों में दाखिले से जुड़े इस आल इंडिया कोटे में सिर्फ एससी-एसटी को ही आरक्षण दिया जा रहा है। ओबीसी सांसदों की ओर से पहले भी यह मांग उठाई जा चुकी है।

ओबीसी सांसदों ने पीएम से अनुरोध किया कि संविधान के तहत ओबीसी और ईडब्लूएस (आर्थिक रूप कमजोर वर्ग) के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था तय की है, उसे मेडिकल के दाखिले से जुड़े आल इंडिया कोटे में भी लागू किया जाए। मौजूदा समय में मेडिकल कालेजों में दाखिले से जुड़े आल इंडिया कोटे में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलता है। खास बात यह है कि आल इंडिया कोटे के तहत मेडिकल कालेजों में अंडर ग्रेजुएट का 15 फीसद और पोस्ट ग्रेजुएट की पचास फीसद सीटें आरक्षित रहती है। इनमें दाखिला नीट (नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट) के आधार पर ही किया जाता है। हालांकि इसके अतिरिक्त सीटों पर दाखिला राज्यों की ओर से अपने निवासियों का किया जाता है। जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्लूएस सभी को तय आरक्षण का लाभ दिया जाता है।

प्रधानमंत्री मोदी से मेडिकल के आल इंडिया कोटे की सीटों में ओबीसी को आरक्षण देने की मांग को लेकर जिन लोगों ने मुलाकात की उनमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, अनुप्रिया पटेल के साथ सांसद आरपीएन सिंह आदि नेता शामिल रहे। गौरतलब है कि इससे पहले भी भाजपा सांसद गणेश सिंह के नेतृत्व में ओबीसी सांसदों ने मेडिकल में दाखिले से जुड़ी आल इंडिया कोटे में आरक्षण देने की मांग की है।

भारत-अमेरिका साझेदारी की अहमियत आगामी वर्षों में और अधिक होगी : मोदी

नई दिल्ली, आइएएनएस : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी, वैश्विक आर्थिक रिकवरी और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों के संदर्भ में आगामी वर्षों में भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी की वैश्विक अहमियत और भी अधिक होगी।

प्रधानमंत्री ने यह टिप्पणी भारत यात्रा पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ मुलाकात के दौरान की। इस दौरान ब्लिंकन ने राष्ट्रपति जो बाइडन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दीं। ब्लिंकन ने दिन में विदेश मंत्री एस. जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ हुई फलदायी बातचीत के बारे में भी प्रधानमंत्री को अवगत कराया। साथ ही रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार एवं निवेश, जलवायु परिवर्तन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समेत विभिन्न क्षेत्रों में भारत-अमेरिका रणनीतिक रिश्तों को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

प्रधानमंत्री मोदी ने भी राष्ट्रपति बाइडन और उपराष्ट्रपति हैरिस के लिए शुभकामनाएं प्रेषित कीं और क्वाड, कोरोना महामारी व जलवायु परिवर्तन समेत विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रपति बाइडन द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। ब्लिंकन ने भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय मुद्दों पर बढ़ती नजदीकियों और इन नजदीकियों को ठोस एवं व्यवहारिक सहयोग में तब्दील करने की प्रतिबद्धता की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अमेरिका और भारत के समाज लोकतंत्र और स्वतंत्रता के मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध हैं और अमेरिका में भारतीय समुदाय ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने में अत्यधिक योगदान दिया है।

भारत में कोरोना टीकाकरण के लिए मदद देगा अमेरिका

नई दिल्ली, एएनआइ : बाइडन प्रशासन के सत्ता संभालने के बाद पहली बार भारत यात्रा पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत के कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम के लिए 2.5 करोड़ डालर (करीब 175 करोड़ रुपये) की मदद देने का एलान किया। विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ संयुक्त प्रेसवार्ता में ब्लिंकन ने बताया कि कोरोना सहायता के रूप में अमेरिका 20 करोड़ डालर (करीब 1,400 करोड़ रुपये) से अधिक की मदद दे चुका है। 2.5 करोड़ डालर की अतिरिक्त मदद से कोरोना टीकों की आपूर्ति शृंखला को मजबूत करने, टीकों के खिलाफ दुष्प्रचार से निपटने, टीकों के प्रति हिचक खत्म करने व स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करने में सहायता मिलेगी। प्रेट्र के मुताबिक, अमेरिकी दूतावास में आयोजित एक कार्यक्रम में ब्लिंकन ने कहा कि वीजा के लिए इस गर्मी में आपने काफी दबाव बनाया है। अगस्त के आखिर तक 68 हजार छात्रों के लिए वीजा साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा जो पिछले कई वर्षों में सबसे अधिक होंगे।

दलाई लामा के प्रतिनिधि से मिले ब्लिंकन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

▶ बीजिंग को बताया लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा, ऐसी चुनौतियों के समक्ष संयुक्त रूप से खड़े होने का किया आह्वान

भारत की दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीन पर जमकर निशाना लगाया है। सबसे पहले उन्होंने तिब्बत के धार्मिक गुरु दलाई लामा के वरिष्ठ प्रतिनिधि से मुलाकात की और बाद में चीन की तरफ इशारा करते हुए उसे लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा भी करार दिया। चीन को यह बात बहुत बुरी लगी है। संकेत हैं कि आने वाले दिनों में अमेरिका ही नहीं, बल्कि भारत भी तिब्बत को लेकर ज्यादा मुखर हो सकता है। पिछले दिनों दलाई लामा के जन्मदिन पर उन्हें सार्वजनिक तौर पर बधाई देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात के संकेत दिए थे।

ब्लिंकन ने नई दिल्ली में दलाई लामा के प्रतिनिधि और तिब्बत की निर्वासित सरकार के अधिकारी न्गोदूप दोंगचुंग से मुलाकात की। तिब्बत के एक और प्रतिनिधि के साथ उन्होंने सिविल सोसायटी के सदस्य के तौर पर बैठक की। इस बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री ने दुनिया में लोकतांत्रिक मूल्यों के समक्ष उत्पन्न खतरों को लेकर आगाह किया और भारत व अमेरिका को इन चुनौतियों के समक्ष संयुक्त तौर पर खड़ा होने का आह्वान किया।

चीन ने जताई तीखी प्रतिक्रिया

ब्लिंकन के बयान पर चीन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि लोकतंत्र पूरी मानवता का साझा मूल्य है और इस पर किसी देश का एकाधिकार नहीं है। कई राजनीतिक दलों वाली व्यवस्था ही लोकतंत्र का एकमात्र जरिया नही हो सकती और लोकतंत्र को टकराव का जरिया नहीं बनाया जाना चाहिए।

उपलब्धि

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल का एक साल पूरा, अब तक उठाए गए कदमों की देंगे जानकारी, एकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट स्कीम सहित स्थानीय भाषाओं में इंजीनियरिंग कोर्स कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ

पीएम आज करेंगे शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई बड़े एलान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल को एक साल पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार यानी 29 जुलाई को देश भर के शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों को संबोधित करेंगे। जिसमें शिक्षक, छात्र और अभिभावक सभी शामिल होंगे। इस मौके पर वे शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कई बड़े एलान भी करेंगे। इनमें सबसे अहम एकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट स्कीम व स्थानीय भाषाओं में इंजीनियरिंग कोर्स का शुभारंभ शामिल है।

खास बात यह है कि एकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट स्कीम में पढ़ाई बीच में छोड़ना भी अब बेकार नहीं जाएगा, बल्कि क्रेडिट के रूप में जमा रहेगा। जब भी चाहेंगे उसे वहीं से शुरू कर सकेंगे। या फिर नए कोर्स के दाखिले में उसका लाभ मिल जाएगा। छात्रों के लिए यह रोचक स्कीम होगी।

पीएम मोदी इस मौके पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एक साल के भीतर उठाए गए कदमों की भी जानकारी देंगे। साथ ही नीति को आगे बढ़ाने का रोडमैप भी पेश करेंगे। पीएम इसके साथ ही उच्च शिक्षा को नई उंचाई पर ले जाने और उसे अंतरराष्ट्रीय स्वरूप देने पर भी अपनी राय देंगे। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक पीएम इस मौके पर और भी जिन पहलों को शुरू करने का एलान करेंगे, उनमें स्कूलों में पहली ग्रेड के छात्रों के लिए तीन महीने का नाटक आधारित माड्यूल, शिक्षकों के प्रशिक्षण से जुड़ा सफल कार्यक्रम आदि शामिल हैं। इसके साथ ही उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में उठाए गए कदमों की भी जानकारी देंगे। गौरतलब है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को केंद्र सरकार ने पिछले 29 जुलाई को मंजूरी दी थी। इसके बाद ही इसके अमल का पूरा रोडमैप तैयार किया गया था। जिस पर फिलहाल तेजी से काम चल रहा है। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे।


जागरण आर्काइव

शिक्षा मंत्री ने कस्तूरीरंगन से की मुलाकात : नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल का एक साल पूरे होने के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को बेंगलुरु में नीति तैयार करने वाले कमेटी के अध्यक्ष पदम विभूषण डाक्टर के. कस्तूरीरंगन से मुलाकात की। साथ ही नीति के अमल को लेकर चर्चा भी की है। बता दें कि प्रधान को पार्टी ने कर्नाटक में मुख्यमंत्री के चयन के लिए बतौर पर्यवेक्षक भेजा था। इस दौरान उन्होंने राजनीतिक चर्चा के बीच समय निकालकर कस्तूरीरंगन से मुलाकात की है। वे गुरुवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक साल पूरा होने के मौके पर पीएम के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे।

भारत को अभी तक मिल चुके हैं 26 राफेल विमान

नई दिल्ली, प्रेट्र : भारत को अभी तक 26 राफेल विमान मिल चुके हैं। राफेल सौदे के तहत दासौ एविएशन 36 विमानों की आपूर्ति करेगी। रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट ने बुधवार को लोकसभा में एक सवाल के लिखित उत्तर में बताया, '36 राफेल विमान की आपूर्ति प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रही है। आज की तारीख तक 26 विमान मिल चुके हैं।'

फ्रांस की एयरोस्पेस क्षेत्र की बड़ी कंपनी दासौ एविएशन द्वारा निर्मित बहु-भूमिका वाले राफेल जेट को हवाई श्रेष्ठता और सटीक हमले के लिए जाना जाता है। पहला राफेल विमान पिछले साल 29 जुलाई को आया था। इससे चार साल पहले 36 राफेल विमानों की खरीद के लिए 59,000 करोड़ रुपये के सौदे पर भारत और फ्रांस की सरकारों ने हस्ताक्षर किए थे।

रूस से सुखोई जेट आयात किए जाने के बाद 23 वर्षों में राफेल जेट लड़ाकू विमानों की पहली बड़ी खरीद है। राफेल जेट कई सक्षम हथियारों को ले जाने की क्षमता रखता है।

कह के रहेंगे माधव जोशी



3305 गांवों में तिरंगा फहराएगी विद्यार्थी परिषद जम्मू-कश्मीर के। यह आयोजन 15 अगस्त सभी जिलों में एक साथ मनाया जाएगा।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 29 जुलाई, 2021

2024 में कोई भी बने विपक्ष का नेता, मुझे काडर रहना पसंद : ममता

दिल्ली दौरा ▶ विपक्षी एकता बहुत जरूरी पर फिलहाल स्वरूप पर स्पष्ट सोच नहीं

कांग्रेस से संबंधों पर बोलीं, बीती बातों को भुलाकर आगे बढ़ने का वक्त

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

बंगाल चुनाव जीतकर विपक्षी दलों के बीच प्रमुख चेहरा बनीं ममता बनर्जी चाहती हैं कि 2024 के लिए भाजपा के खिलाफ एक मजबूत विकल्प खड़ा हो, लेकिन फिलहाल इसका कोई आकार सामने नहीं है। उनका साफ कहना है, सभी दलों को हिम्मत के साथ खड़ा होना होगा, मन बनाना होगा, तभी कुछ तय हो सकता है। हालांकि वह खुद को ऐसे किसी विकल्प के नेता की दौड़ में शामिल नहीं करना चाहतीं। वह कहती हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं अगर कोई और चेहरा बनता है। वैसे भी कोलकाता में प्यारा सा घर है। मेरी मंशा तो सिर्फ बिल्ली के गले में घंटी बांधने की है। मैं काडर रहना ही पसंद करूंगी।

बंगाल में फिर सत्ता संभालने के बाद पहली बार दिल्ली आईं ममता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से औपचारिक मुलाकात के साथ-साथ कुछ विपक्षी दलों के नेताओं से मिल चुकी हैं। बुधवार को भी उन्होंने सोनिया गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत अन्य नेताओं से मुलाकात की। इससे पहले मीडिया से रूबरू ममता से ज्यादातर सवाल विपक्षी मोर्चे को लेकर हुए। ममता ने बेलाग कहा, 'अभी तो बच्चे का जन्म भी नहीं हुआ और नामकरण की बात शुरू हो गई... भाजपा से लड़ने के लिए मजबूत एकजुटता की जरूरत है, देश भी यही चाहता है, लेकिन इसका आकार, इसकी रणनीति सब कुछ तभी तय होगा, जब सभी मिल बैठेंगे।' उन्होंने कहा कि माहौल बदलते वक्त नहीं लगता, इतिहास गवाह है कि अटल बिहारी वाजपेयी के काल में भी कई चीजें बदल गई थीं, बहुत लंबे समय की जरूरत नहीं, तीन महीने में भी बहुत कुछ हो सकता है। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें कांग्रेस पर भरोसा है तो उन्होंने कहा, 'सोनिया जी से मेरे अच्छे संबंध हैं, मैं कांग्रेस के अंदरूनी मामलों में नहीं जाना चाहती, लेकिन इतना कहूंगी कि जब एकजुट लड़ाई की बात आएगी तो बीती बातें भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश होगी।' वाम दलों के व्यवहार पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें पहले तय करना होगा कि दुश्मन भाजपा है या तृणमूल।

शाम को सोनिया से हुई मुलाकात के बाद भी उन्होंने दोहराया कि विपक्षी एकजुटता समय की मांग है और उस पर जल्द आगे बढ़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में आगामी चुनावों को लेकर उन्होंने कहा कि अभी कुछ भी तय नहीं है।

पेगासस मुद्दे पर बुधवार को राहुल गांधी की अगुआई में मीडिया के सामने विपक्षी एकता के वक्त तो तृणमूल उससे दूर रही, लेकिन ममता पेगासस को लेकर आक्रामक थीं। उन्होंने यह बताने से मना कर दिया कि पीएम ने उनसे क्या कहा, लेकिन जोर देकर कहा कि पेगासस जनता से जुड़ा मुद्दा है। हर हाथ में फोन है और लोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता चाहते हैं। बंगाल सरकार ने न्यायिक आयोग बिठा दिया है जो इसकी जांच करेगा। सुप्रीम कोर्ट कोई और फैसला देता है तो उसका पालन किया जाएगा।



नई दिल्ली में बुधवार कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद प्रस्थान करती बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। इस दौरान राहुल गांधी भी मौजूद रहे। प्रेट्र

'विपक्ष का चेहरा ममता होंगी, यह सोचना मूर्खता है'

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

बंगाल में वामदलों की अगुआई करने वाली मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के भीतर राज्य में अपनी धुर विरोधी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन देने के मुद्दे पर मतभेद सामने आ गए हैं। पार्टी के एक धड़े ने ममता का विरोध करना शुरू कर दिया है। राज्य में पार्टी के वरिष्ठ नेता सुजन चक्रवर्ती ने कहा कि ममता बनर्जी विपक्ष का चेहरा होंगी, यह सोचना भी मूर्खता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ बनने वाले प्रस्तावित गठजोड़ का चेहरा ममता बनर्जी को बनाए जाने पर बुधवार को सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि बंगाल में भाजपा को मजबूत बनाने वाली ममता बनर्जी विरोधी फ्रंट का नेतृत्व कैसे कर सकती हैं? भाजपा के खिलाफ आंदोलन का उनका कोई इतिहास नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा और पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष का एक स्पष्ट चेहरा होना चाहिए, लेकिन वह चेहरा ममता बनर्जी होंगी, यह सोचना मूर्खता है।

दिल्ली में लालू प्रसाद से मिले शरद पवार

राज्य ब्यूरो, पटना : तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सुप्रीमो ममता बनर्जी की बुधवार को दिल्ली में सक्रियता के बीच राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रमुख शरद पवार ने मुलाकात की। लालू की बेटी मीसा भारती के सरकारी आवास पर हुई इस मुलाकात के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव एवं कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य अखिलेश प्रसाद सिंह भी मौजूद थे। चारों वरिष्ठ नेताओं के बीच मुलाकात का मजमून तो बाहर नहीं आया, लेकिन माना जा रहा है कि एक दिन पहले राकांपा की ओर से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही गई थी। इस मुलाकात को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। चारों नेताओं के बीच काफी देर तक राजनीतिक हालात पर चर्चा होती रही। मुलाकात की तस्वीर मीसा भारती ने खुद ट्वीट की है। तस्वीर में मीसा भी दिख रही हैं। मुलाकात के बारे में उन्होंने बताया है कि शरद पवार राजद प्रमुख के स्वास्थ्य की जानकारी लेने आए थे। गौरतलब है कि जमानत पर जेल से निकलने के बाद लालू प्रसाद ने राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी हैं।

ममता को पसंद है आयोग गठन की राजनीति

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस समय दिल्ली दौरे पर हैं। यहां आने से ठीक पहले उन्होंने बंगाल में प्रतिष्ठित लोगों की फोन हैकिंग मामले की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग गठित करने का एलान किया था। इस दो सदस्यीय आयोग में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज एमबी लोकुर और कलकत्ता हाई कोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश ज्योतिर्मय भट्टाचार्य शामिल हैं। यह ममता द्वारा गठित पहला आयोग नहीं है। मुख्यमंत्री के तौर पर 10 साल के कार्यकाल में ममता ने इससे पहले भी 16 आयोग गठित किए हैं। हालांकि, आयोग गठन की इस कसरत का कभी कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है।

कुछ अन्य मामलों में भी बने आयोग

- 1970 में बर्द्धमान जिले में कांग्रेस समर्थक सैन परिवार के तीन सदस्यों की हत्या। हत्या का आरोप माकपा समर्थकों पर लगा था।
- 1971 में कोलकाता में कोसीपोर-बारानगर नरसंहार।
- 1982 में बिजन सेतु पर 16 आनंद मार्ग मिशनरियों की हत्या।
- 21 जुलाई, 1993 को वाम मोर्चा सरकार के आदेश पर ममता बनर्जी की अगुआई में हुई रैली में पुलिस फायरिंग के कारण 13 यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौत।
- 1999 मेदिनीपुर में ट्रक दुर्घटना में 23 आदिवासियों की मौत।

चुनावी वादों के नाम पर किया ताबड़तोड़ गठन

2011 में सत्ता संभालते ही ममता ने चुनावी वादे पूरे करने के नाम पर आठ आयोगों का गठन किया था। अब तक इन पर करीब 40 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन कोई ठोस निष्कर्ष सामने नहीं आया है। 2008 में वाम मोर्चा सरकार के समय एक ब्लाक विकास अधिकारी की आत्महत्या और 2011 में एक माकपा विधायक की आत्महत्या के मामले में गठित आयोगों ने रिपोर्ट सौंपी थी। इनके निष्कर्ष पुलिस से अलग नहीं थे। 2011 में एएमआरआइ अस्पताल में लगी आग को लेकर गठित आयोग के निष्कर्ष भी पुलिस जैसे ही थे।

सारधा घोटाले पर भी आयोग

ममता बनर्जी ने 2013 में सारधा पोंजी स्कीम घोटाला सामने के कुछ दिन बाद इस मामले में श्यामल कुमार सेन आयोग गठित किया था। आयोग का लक्ष्य घोटाले के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का पता लगाना और स्कीम के जमाकर्ताओं को उनके पैसे लौटाना था। आयोग ने 2014 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन इसे विधानसभा में नहीं पेश किया गया। सूत्रों का कहना है कि अब तक आयोग के जरिये 3,93,982 जमाकर्ताओं को 287 करोड़ रुपये लौटाए गए हैं। हालांकि, इसमें से 102 करोड़ रुपये के चेक आयोग के पास वापस आ गए। स्कीम में लगा पैसा वापस पाने के लिए आयोग को 17 लाख से ज्यादा आवेदन मिले थे। ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर आयोग के गठन का लाभ क्या रहा।

नतीजों की अंतहीन प्रतीक्षा

1993 की फायरिंग मामले में गठित सुशांत कुमार आयोग ने 2014 में रिपोर्ट सौंपी थी। 2017 में ममता ने आयोग की सिफारिशें लागू करने की बात कही थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आदिवासियों की मौत पर एनएन भट्टाचार्य आयोग की 2014 में आई रिपोर्ट पर सरकार को छह महीने में कदम उठाना था, लेकिन यह भी ठंडे बस्ते में है। सैन परिवार के सदस्यों की हत्या पर गठित अरुणाभ बसु आयोग और बिजन सेतु मामले में अमिताभ लाला आयोग ने क्रमश: 2012 और 2013 में जांच शुरू की थी। बसु आयोग पर पांच करोड़ और लाला आयोग पर चार करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं, लेकिन जांच पूरी नहीं हुई है। (इनपुट : आइएएनएस)

आइपैक के सदस्यों को छुड़ाने त्रिपुरा पहुंचे ममता के दो मंत्री

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

- आइपैक टीम को क्वारंटाइन किए जाने का तृणमूल कांग्रेस ने किया विरोध
- भाजपा पर बोला हमला, कहा- जहां अन्याय, वहां विरोध में खड़ी हैं ममता

चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर (पीके) की इंडियन पालीटिकल एक्शन कमेटी (आइपैक) की 23 सदस्यीय टीम को कोरोना नियमों के उल्लंघन को लेकर त्रिपुरा पुलिस द्वारा अगरतला के एक होटल में क्वारंटाइन किया गया है। इस मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) भाजपा पर हमलावर है। इस बीच आइपैक टीम को वहां की पुलिस ने समन भेज कर एक अगस्त को पूछताछ के लिए भी तलब किया है।

वहीं, इस पूरी कार्रवाई के विरोध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर बुधवार को बंगाल के दो मंत्री समेत तृणमूल कांग्रेस के तीन नेता आइपैक की टीम के सदस्यों को छुड़ाने त्रिपुरा पहुंचे और इस घटना के खिलाफ प्रतिवाद जताया।

बंगाल के कानून मंत्री मलय घटक, शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु तथा तृणमूल कांग्रेस के श्रमिक प्रकोष्ठ के नेता ऋतब्रत बनर्जी ने इस मुद्दे पर अगरतला में एक संवाददाता सम्मेलन किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा की अगुआई वाली त्रिपुरा सरकार पर आइपैक टीम को बंदी बनाने का आरोप लगाते हुए इसे अलोकतांत्रिक करार दिया। इस दौरान मंत्री ब्रात्य बसु ने कहा कि टीम के सदस्यों के खिलाफ कोरोना नियमों के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है, जबकि सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई है। सभी ने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हैं।

इस दौरान उन्होंने कहा कि जहां अन्याय होगा, वहां ममता बनर्जी विरोध में खड़ी होंगी। इस घटना के खिलाफ एक-दो दिन में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी भी त्रिपुरा जा सकते हैं।

बोम्मई ने सीएम बनते ही किया हजार करोड़ के वजीफे का एलान

- फिलहाल अकेले ली शपथ, जल्द होगा सरकार का विस्तार
- कर्नाटक में पिता के बाद मुख्यमंत्री बनने वाले दूसरे बेटे
- लिंगायत समुदाय के नेता, हैं येदियुरप्पा के खास

बेंगलुरु, प्रेट्र : कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बासवराज बोम्मई ने नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राजभवन में आयोजित समारोह में 61 वर्षीय बोम्मई को राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बोम्मई ने अकेले ही शपथ ली है। जल्द ही वह अपने मंत्रिमंडल का गठन करेंगे। मुख्यमंत्री के रूप में बोम्मई ने प्रभावी, ईमानदार और मैत्रीपूर्ण सरकार देने का वादा किया है। उन्होंने किसानों की बेटी-बेटों के लिए एक हजार करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति योजना का एलान किया है। बोम्मई कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले वह बीएस येदियुरप्पा सरकार में गृह और संसदीय कार्य मंत्री थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोम्मई को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही येदियुरप्पा की भाजपा को मजबूत करने के प्रयासों की प्रशंसा की है।

इससे पहले मंगलवार शाम को कर्नाटक भाजपा विधायक दल की बैठक में बोम्मई को नया नेता चुना गया। उनके नाम का प्रस्ताव निवर्तमान मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने किया था। बोम्मई भी लिंगायत समुदाय से हैं और येदियुरप्पा के विश्वासपात्र हैं। सूत्रों के अनुसार भाजपा आलाकमान को बोम्मई का नाम खुद येदियुरप्पा ने सुझाया था। बासवराज कर्नाटक के सीएम रहे स्वर्गीय एसआर बोम्मई के बेटे हैं। राज्य के वह दूसरे राजनेता हैं जो अपने पिता के बाद सीएम बने हैं। उनसे पहले एचडी देवगौड़ा और उनके पुत्र एचडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बन चुके हैं। बोम्मई हावेरी जिले की शिगगांव सीट से तीन बार विधायक रहे हैं। वह दो बार विधान परिषद के सदस्य भी रहे हैं। उन्हें स्वच्छ छवि वाला और विवादों से परे नेता माना जाता है। राजभवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह में निवर्तमान मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के अलावा पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में गए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, किशन रेड्डी व भाजपा महासचिव अरुण सिंह भी मौजूद थे। मंत्रिमंडल विस्तार के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में बोम्मई ने कहा कि जल्द ही दिल्ली का दौरा करने के बाद मंत्रियों के नाम तय करेंगे। यह कार्य सभी की सहमति से किया जाएगा। 75 वर्ष की आयु सीमा पार कर चुके येदियुरप्पा ने सोमवार को इस्तीफा दिया था।



राजभवन में आयोजित समारोह में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते बासवराज सोमप्पा बोम्मई। प्रेट्र



बासवराज बोम्मई विधानसभा पहुंचे तो अंदर प्रवेश करने से पहले उन्होंने कुछ इस अंदाज में शीश नवाया। प्रेट्र

संध्या सुरक्षा योजना का भुगतान बढ़ाया

बेंगलुरु, आइएएनएस : मुख्यमंत्री बनने के बाद अधिकारियों के साथ पहली बैठक में बासवराज बोम्मई ने किसानों के बेटा-बेटियों के लिए एक हजार करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की। इससे अभावग्रस्त तबके के युवाओं को पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलेगी। साथ ही 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को संध्या सुरक्षा योजना के तहत दी जाने वाली एक हजार रुपये की मासिक पेंशन को बढ़ाकर 1,200 रुपये करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती येदियुरप्पा सरकार के अच्छे कार्यों को जारी रखने की घोषणा की है।

बोम्मई परिवार में खुशी की चर्चा

बासवराज बोम्मई के मुख्यमंत्री बनने से उनका परिवार भी आह्लादित है। बेटे भरत, पत्नी चानम्मा, पुत्रवधू इब्बानी, बेटी अदिति और अन्य रिश्तेदारों ने आरटी नगर स्थित आवास पर कन्नड़ के सुपरहिट गानों को गा-नाचकर अपनी खुशी का इजहार किया। परिवार की खुशी के इन क्षणों का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहा है।

बंगाल सरकार को मिली रिपोर्ट पर पूरक हलफनामा दाखिल करने की अनुमति

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को बंगाल की ममता सरकार को राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद हुई कथित हिंसा पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की जांच समिति की रिपोर्ट के सिलसिले में पूरक हलफनामा दाखिल करने के लिए 31 जुलाई तक का समय दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने निर्देश दिया कि इस विषय को फिर से दो अगस्त को सुनवाई की जाएगी। वहीं एनएचआरसी की रिपोर्ट को चुनौती देते हुए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के दो विधायकों ने कलकत्ता हाई कोर्ट में मामला दायर किया है।

एनएचआरसी की समिति ने 13 जुलाई को सौंपी गई अंतिम रिपोर्ट में बंगाल में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर तल्ख टिप्पणी की थी। हालांकि, राज्य सरकार ने सोमवार को सौंपे गए अपने हलफनामे में रिपोर्ट के निष्कर्षों को खारिज कर दिया था और आरोप लगाया था कि यह राजनीति से प्रेरित है। साथ ही कहा था कि ममता बनर्जी सरकार को बदनाम करने के चलते ऐसी रिपोर्ट तैयार की गई है। इसी कड़ी में पूरक हलफनामा दायर करने की अपील की थी, जिसे हाई कोर्ट ने अनुमति दे दी है।

उधर, बुधवार को हाई कोर्ट में चुनाव बाद हिंसा में मारे गए भाजपा की मजदूर शाखा के नेता अभिजीत सरकार की डीएनए रिपोर्ट भी अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल ने पीठ को सौंपी। अदालत ने पहचान स्थापित करने के लिए सरकार के डीएनए का मिलान उनके भाई से कराने का निर्देश दिया था, क्योंकि अभिजीत के भाई ने सवाल उठाया था कि जिसका पोस्टमार्टम किया गया था, वह उनके भाई का शव नहीं था। मानवाधिकार आयोग के वकील सुबीर सान्याल ने कहा कि रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद भी कई शिकायतें मिलीं, इनमें से 16 ऐसे मामले हैं जहां पुलिस या क्षेत्र के नेता शिकायतें छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। मैं इस पर अतिरिक्त रिपोर्ट देना चाहूंगा, लेकिन बेंच ने अनुमति नहीं दी।

तृणमूल के दो विधायकों ने एनएचआरसी की रिपोर्ट को दी चुनौती

एनएचआरसी की रिपोर्ट को तृणमूल कांग्रेस के दो विधायकों ने कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती दी है। तृणमूल विधायक ज्योतिप्रिय मल्लिक और पार्थ भौमिक के मुताबिक आयोग ने एकतरफा रिपोर्ट दी है। बताते चलें कि एनएचआरसी ने अपनी रिपोर्ट में इन दोनों विधायकों को कुख्यात अपराधियों की सूची में शामिल किया है।

टीएमसी उम्मीदवार ने राज्यसभा के लिए कर दिया नामांकन

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल में राज्यसभा की एक सीट पर नौ अगस्त को होने वाले उपचुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) उम्मीदवार प्रसार भारती के पूर्व सीईओ जवाहर सरकार ने बुधवार को नामांकन कर दिया। जवाहर सरकार ने बंगाल विधानसभा जाकर संबंधित अधिकारी को नामांकन पत्र सौंपा। उधर, भाजपा ने अब तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। राजनीति के गलियारों में ऐसी चर्चा है कि भाजपा ने अभी तक प्रत्याशी का नाम तय नहीं किया है।

गौरतलब है कि बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले दिनेश त्रिवेदी के त्यागपत्र के बाद सूबे में राज्यसभा की यह सीट रिक्त हुई थी। आंकड़ों के हिसाब से जवाहर सरकार का राज्यसभा में जाना तय माना जा रहा है, क्योंकि यह सीट टीएमसी के ही पास थी। हालांकि, भाजपा भी अपना उम्मीदवार उतारेगी, जिसकी घोषणा वह पहले ही कर चुकी है।

दो बच्चों के प्रविधान को बिहार में लागू करने की मांग

राज्य ब्यूरो, पटना

बिहार समेत देश में बढ़ती हुई जनसंख्या का मामला बिहार विस के मानसून सत्र में भी उठा। दिलचस्प यह कि पहली बार सदन में भाजपा को इस मुद्दे पर जदयू का भी साथ मिला। ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से कई विधायकों ने दो बच्चों के प्रविधान को बिहार में लागू करने की मांग सरकार से की। साथ ही जनसंख्या पर वर्ष 1999 के करुणाकरण समिति के सुझावों को भी लागू करने का आग्रह किया।

भाजपा विधायक विजय कुमार खेमका, अवधेश सिंह, कृष्ण कुमार ऋषि, डा. सुनील कुमार और जदयू के विधायक विनय कुमार चौधरी ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर मुखर होकर सदन के अंदर कानून बनाने की मांग की। विजय कुमार खेमका ने आसन से कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। जदयू विधायक विनय कुमार चौधरी ने भी इस मांग का समर्थन करते हुए कहा कि कानून के साथ-साथ जागरूकता अभियान भी चलाना चाहिए। नीतीश कुमार की सरकार लगातार जनसंख्या नियंत्रण के लिए अभियान चला रही है।

कांग्रेस भी बढ़ती आबादी पर अंकुश की हिमायती : कांग्रेस विधायक नीतू सिंह ने भी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने की मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने के पक्ष में कांग्रेस शुरू से है। संजय गांधी ने तो इसके लिए विशेष अभियान चलाने की भी बात कही थी।

सर्वदलीय बैठक में विचार का पक्षधर है राजद : जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर राजद का स्टैंड साफ करते हुए विधायक एवं पार्टी के मुख्य प्रवक्ता वीरेंद्र ने कहा कि भाजपा लोकप्रियता हासिल करने वाले मुद्दे को ही उछालती है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सर्वदलीय बैठक में विचार होना चाहिए।

उप्र में योगी अजेय, लालू बेअसर : सुशील मोदी

राज्य ब्यूरो, पटना : बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी अजेय हैं। अब राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद का कोई असर नहीं रहा, इसलिए उप्र के विधानसभा चुनाव को लेकर सपा, कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं से उनके मिलने का कोई मतलब नहीं है। बिहार से बाहर वे कभी अपने पांच विधायक नहीं जिता पाए। गृह राज्य में भी ताकत खो चुके हैं।

उन्होंने कहा कि उप्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने, अपराधियों में कानून का डर पैदा करने और कोविड प्रबंधन में इतना काम किया है कि उनके नेतृत्व में वहां भाजपा अकेले सब पर भारी पड़ेगी।

सुशील मोदी ने कहा कि केरल की वाम मोर्चा सरकार ने वोट बैंक की राजनीति के तहत बकरीद पर लाकडाउन में तीन दिन की छूट देकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना की, जिससे वहां कोरोना संक्रमण तेजी से फैला।

तैयारी

नड्डा ने की उप्र के सांसदों संग बैठक, विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा, इन यात्राओं के साथ कम से कम तीन लोकसभा क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे नवनियुक्त केंद्रीय मंत्री

उत्तर प्रदेश में भाजपा निकालेगी जन आशीर्वाद यात्रा

नई दिल्ली, एएनआइ : उप्र में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी ने अभी से माहौल बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने अगले महीने 16 अगस्त से जन आशीर्वाद यात्रा निकालने का निर्णय किया है। उप्र के छह क्षेत्रों में तीन के भाजपा सांसदों के साथ बैठक करते हुए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उप्र में पार्टी को मजबूती देने के लिए गहन मंथन किया। बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बैठक को संबोधित करते हुए नड्डा ने भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की अहमियत पर विस्तार से अपनी बात रखी और पीएम नरेंद्र मोदी सहित पार्टी के शीर्ष नेताओं के चुनावों के मद्देनजर राज्य में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की।

सूत्रों ने बताया कि पांच अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के राशन दुकानदारों के साथ डिजिटल माध्यम से संवाद कर सकते हैं। बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किए गए उत्तर प्रदेश के सांसद अपने-अपने संसदीय व आसपास के क्षेत्रों में आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। राजधानी स्थित कांस्टीट्यूशन क्लब में हुई इस बैठक में बृज और कानपुर क्षेत्र के सांसदों के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी सांसद मौजूद रहे। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधामोहन सिंह, राज्य इकाई के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और राज्य के संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी बैठक में शामिल हुए।

बैठक में नड्डा ने सांसदों को टीकाकरण केंद्रों का दौरा करने और वहां लोगों को आ रही परेशानियों को दूर करने तथा कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के उपायों के प्रति जनता में जागरूकता फैलाने को कहा। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य स्वंयसेवकों के बारे में जानकारी दी। साथ ही सरकार की उपलबधियों को जन जन तक पहुंचाने का भी उन्हें निर्देश दिया। बैठक में शामिल वरिष्ठ नेता और मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने बताया कि बैठक में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में सांसदों को विस्तार से बताया गया। उन्हें इसके बारे में जनता को बताने को कहा गया। उन्होंने कहा कि हमारी केंद्र की सरकार ने और प्रदेश की सरकार ने जो विकास कार्य किए हैं उससे उत्तर प्रदेश की छवि बदल गई। इस दौरान विकास के नये आयाम रचे गए। इसके बारे में जनता को बताना है। साथ ही बूथ स्तर पर संगठन को सक्रिय करने के लिए आगामी कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर चर्चा हुई।

अग्रवाल ने बताया कि पिछले दिनों मंत्रिपरिषद में शामिल किए गए मंत्री अपने-अपने संसदीय क्षेत्रों में यात्रा निकालेंगे। उन्होंने कहा, जो मंत्री बने हैं वे 15 अगस्त के बाद अपने-अपने क्षेत्रों में जाएंगे। उनका रूट तय होगा और उसके अनुरूप वह यात्रा निकालेंगे। पार्टी उनका रूट बनाएगी। ज्ञात हो कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में पिछले दिनों हुए विस्तार में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश को मिला। विभिन्न जाति व वर्ग से आने वाले प्रदेश के सात सांसदों को मंत्री बनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी सहित केंद्रीय मंत्रिमंडल में फिलहाल 15 मंत्री उप्र से हैं।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नड्डा ने अपने संबोधन के दौरान राज्य में कानून व्यवस्था का राज स्थापित करने और भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना की और कहा कि पिछले चार सालों में राज्य को उन्होंने नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। उन्होंने सभी सांसदों से अपने संसदीय क्षेत्रों के तहत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने का जिम्मा लेने को कहा और साथ ही कहा कि 2022 के चुनाव में पिछले चुनाव से 'बड़ी लकीर' खींचनी है। यह बैठक दो दिन चलेगी। गुरुवार को इस बैठक में अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र के सांसद भाग लेंगे।

दागी विधायक बोले, संयोग था दिल्ली में एक साथ पहुंचना'

राज्य ब्यूरो, रांची

विधायकों की खरीद-फरोख्त और झारखंड सरकार गिराने की साजिश का मामले समाने आने के बाद कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम विधायकों से लगातार मिल रहे हैं और रिपोर्ट भी तैयार कर रहे हैं। विधायक डा. इरफान अंसारी और उमाशंकर अकेला की उस बात से आलमगीर आलम संतुष्ट नजर आए, जिसमें उन्होंने कुछ दलालों और भाजपा नेताओं के साथ तस्वीर और वीडियो को महज संयोग करार दिया है। हालांकि, इसके बावजूद किसी को क्लीन चिट अभी नहीं दी जा रही है। शीघ्र ही आलमगीर आलम पार्टी हाईकमान को रिपोर्ट भेज देंगे।

आलमगीर आलम ने कहा कि विधायकों की बात सुनी गई है, लेकिन जल्दबाजी में किसी को क्लीनचिट देने से इन्कार भी किया। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह एक सप्ताह के अंदर झारखंड पहुंच सकते हैं। उनके यहां पहुंचने के बाद इस विवाद को समाप्त किया जाएगा। फिलहाल पार्टी स्तर से पुलिस की जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

महाराष्ट्र के छह नेताओं को पुलिस भेजेगी नोटिस : विधायकों की खरीद-फरोख्त और सरकार गिराने की साजिश मामले में एसआइटी ने जांच शुरू कर दी है। केस के जांचकर्ता को कई नए तथ्य मिले हैं। इस आधार पर केस में लगातार नए आरोपितों के नाम सामने आए हैं। अब तक जेल भेजे गए तीन आरोपितों की स्वीकारोक्ति में सामने आए साजिशकर्ताओं के नामों पर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। इस आधार पर महाराष्ट्र के छह नेताओं को नोटिस भेजा जाएगा।

2744 फ्लैट कश्मीरी पंडितों के लिए पांच जिलों में बनेंगे। 278 कनाल जमीन स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी। यह आवास प्रधानमंत्री राहत पैकेज के तहत कश्मीर में नौकरी प्राप्त करने वाले विस्थापितों को ही मिलेंगे।

कई जिंदगियां बचा खुद काल का ग्रास बन गई विनीता...

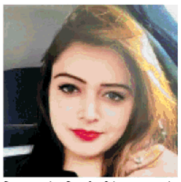
पहाड़ पर आफत

हंसराज सैनी, मंडी

- ब्रह्मगंगा नाले में पानी के तेज बहाव का शोर सुन कैंपिंग साइट करवाई खाली
- विनीता के दोस्त ने उसे बचाने का किया प्रयास, तेज बहाव के आगे एक नहीं चली

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की विनीता कई लोगों की जिंदगी बचा खुद काल का ग्रास बन गई। कुल्लू जिले के मणिकर्ण के पास ब्रह्मगंगा नाले में पानी के तेज बहाव का शोर सुन विनीता ने कैंपिंग साइट खाली करवाई। अपनी जान की परवाह किए बिना टेंट में ठहरे पर्यटकों को जगाया और उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर भेजा। इससे पहले कि विनीता खुद सुरक्षित जगह तक पहुंचती, सैलाब उसे बहा ले गया।

25 वर्षीय विनीता पुत्री विनोद कुमार निवासी गांव निसतौली, नजदीक टिल्ला मोड़, लोनी रोड गाजियाबाद यहां अपने दोस्त अर्जुन की कैंपिंग साइट पांच साल से बतौर मैनेजर कार्यरत थी। बुधवार सुबह जल्दी उठने के बाद वह कैंपिंग साइट में टहल रही थी। तभी ब्रह्मगंगा नाले में अचानक पानी का सैलाब आता देख टेंट खाली करवाने के बाद सामान समेटने लगी। पानी के तेज बहाव ने कैंपिंग साइट के चार टेंट को अपनी चपेट में ले लिया। पानी से खुद को घिरा देख विनीता मदद के लिए चिल्लाई। उसका दोस्त अर्जुन मदद के लिए पहुंचा भी, लेकिन सैलाब के आगे एक नहीं चली। अर्जुन भी तेज बहाव में करीब 10 मीटर तक बहकर चला गया, हालांकि किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहा। गंभीर रूप से घायल अर्जुन को पीजीआइ चंडीगढ़ रेफर किया गया है।


जिला कुल्लू के मणिकर्ण घाटी के ब्रह्मगंगा नाले में बही विनिता चौधरी उर्फ विन्नी। फाइल फोटो

ससुर का कहना माना होता तो पूनम व उसके बेटे की जान पर नहीं बनती

नाले में आए सैलाब से ब्रह्मगंगा गांव के पांच घर पानी से चारों तरफ से घिर गए। गांव की आबादी 25 के करीब है। सुबह लोग अभी नींद से जागे ही थे। इतने में सैलाब आ गया। लोग जान बचाने के लिए सुरक्षित ठिकानों की तरफ भागने लगे। ज्यादातर लोगों ने घरों की छत पर शरण ली। पूनम अपने बेटे निकुंज और ससुर रोशन लाल के साथ घर में थी। उसका पति घर में नहीं था। रोशन ने बहू पूनम को पोते निकुंज के साथ छत पर आने को कहा, लेकिन पूनम ने इस बात पर कोई गौर नहीं किया। घर से बाहर अन्य किसी सुरक्षित जगह जाने के चक्कर में वह पानी की चपेट में आकर बेटे के साथ बह गई। रोशन घर की छत से बहू व पोते को बहता देखता ही रह गया। यह नाला महज 100 मीटर की दूरी पर पार्वती नदी में मिल जाता है।


लाहुल स्पीति में पटन घाटी के तोजिंग नाले में आई बाढ़ में बहे लोगों की तलाश करती रेस्क्यू टीम। जागरण


ऋषिकेश में बुधवार को उफान पर आई बीन नदी में एक लोडर फंस गया। घंटों मशक्कत के बाद अन्य वाहनों की मदद से बाहर निकाला जा सका। यहां से वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। सौ. वन विभाग


हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बुधवार को मूसलधार बारिश से मलबे की चपेट में आए वाहन को निकालने की कोशिश करते लोग। एएनआइ

न्यूज गैलरी

दक्षिण कश्मीर में हिजबुल का आतंकी गिरफ्तार

श्रीनगर : दक्षिण कश्मीर के शारशाली इलाके में सुरक्षाबलों ने बुधवार को हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी को गिरफ्तार कर लिया। इसी दौरान उत्तरी कश्मीर के दुरसु रफियाबाद में सुरक्षाबलों का एक गश्तीदल आतंकियों के ग्रेनेड हमले में बाल-बाल बच गया। जानकारी के अनुसार, पुलिस को शारशाली में तीन से चार आतंकियों को देखे जाने की सूचना मिली थी। (राब्यू)

अच्छी पहल : 20 साल से अलग पति-पत्नी आए साथ

नई दिल्ली : 20 साल चली कानूनी लड़ाई में फंसे पति-पत्नी को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने वापस रिश्ते में बांधने की दिशा में बड़ी पहल की। आंध्र प्रदेश के इस जोड़े के बीच कानूनी लड़ाई 2001 में दहेज उत्पीड़न के मामले को लेकर शुरू हुई थी। पति को मिली एक साल के कारावास की सजा को बढ़वाने के लिए पत्नी शीर्ष न्यायालय में आई थी लेकिन मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने खुद मामले में रुचि लेते हुए वह स्थितियां बना दीं कि अलग रह रहे पति-पत्नी साथ रहने के लिए तैयार हो गए। (प्रेट्र)

श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में हो सकती है नियमित सुनवाई

मथुरा : श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में नियमित सुनवाई की उम्मीद जगी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में चल रहे वाद में नियमित सुनवाई की मांग वाली याचिका स्वीकार कर ली है। याचिका में निचली अदालत को नियमित सुनवाई का आदेश देने की मांग की गई है, ताकि जल्द सुनवाई पूरी हो सके। श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह हटाकर पूरी जमीन ठाकुर केशवदेव को सौंपने की मांग को लेकर अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने सिविल सीनियर डिवीजन की अदालत में गत 23 दिसंबर को वाद दायर किया था। इस मामले में सुनवाई चल रही है। (जासं)

सीबीआइ ने संभाली स्कालरशिप घोटाले की जांच

चंडीगढ़ : दलित विद्यार्थियों के लिए जारी केंद्रीय पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप में हुए घोटाले की जांच केंद्रीय सामाजिक अधिकारिता व न्याय मंत्रालय के कहने पर सेंट्रल ब्यूरो आफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआइ) को सौंप दी गई है। अब सीबीआइ ने पंजाब सरकार से पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप से संबंधित दस्तावेजों की मांग की है, हालांकि इस बात को लेकर पेंच फंस गया है कि क्या बिना राज्य सरकार की अनुमति के सीबीआइ इस मामले की जांच कर सकती है? क्योंकि पंजाब सरकार ने पिछले साल ही विधानसभा में एक बिल पारित किया है, जिसके अनुसार, बिना प्रदेश सरकार की अनुमति जांच नहीं कर सकती। (जासं)

ड्रग्स व मवेशी तस्करों पर सख्ती हो सकती है हिंसा की वजह : हिमंता

झगड़े की जड़ ▶ असम-मिजोरम सीमा विवाद पर असम के सीएम का दावा

कहा, हम अपने राज्य की इंच भी जमीन किसी को नहीं लेने देंगे

सिलचर, प्रेट्र : मिजोरम के साथ सीमा विवाद को लेकर हुई हिंसा पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता विस्व सरमा ने दावा किया है कि उनकी सरकार द्वारा ड्रग्स व मवेशियों की तस्करी और पशु वध रोकने के लिए की जा रही कड़ाई इसकी वजह हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि वो अपने राज्य की एक इंच जमीन भी किसी को लेने नहीं देंगे।


हिमंता बिस्व सरमा। फाइल

उल्लेखनीय है सोमवार को मिजोरम और असम की सीमा पर हुए संघर्ष में असम पुलिस के पांच जवानों और एक आम नागरिक की मौत हो गई थी।

सरमा ने कहा कि मादक पदार्थों की तस्करी का रास्ता म्यांमार से निकलकर मिजोरम और असम की बराक घाटी से होते हुए पंजाब तक जाता है। मेरे पास यह मानने के पुख्ता कारण हैं कि पिछले दो महीनों में असम सरकार के कुछ फैसलों ने मिजोरम में नान स्टेट एक्टर्स को नाराज कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि मिजोरम में प्रवेश करने वाले म्यांमार के शरणार्थियों के एक वर्ग को अभयारण्य प्रदान करने से असम के इन्कार ने भी उन्हें भड़काने का काम किया। उन्होंने कहा कि मेरे पास वीडियो सुबूत हैं। मुझे लगता है कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि क्या कुछ नान स्टेट एक्टर्स मैदान में आए हैं।

उन्होंने मिजोरम के सीएम जोरमथंगा से यह भी जांच करने का आग्रह किया कि पुलिस पर हमला करने के लिए नागरिकों को बुलेटप्रूफ वेस्ट और स्नाइपर राइफल कैसे मिलीं।

असम पुलिस करेगी जांच : पत्रकारों से बातचीत में सरमा ने कहा कि ये घटना असम की सीमा पर हुई है, इसलिए असम पुलिस इस मामले की जांच करेगी। जांच इस बात की भी होगी कि आम नागरिकों को हथियार कैसे मिले।

उन्होंने कहा, मैं एक इंच भी जमीन की किसी को नहीं दे सकता, अगर कल संसद एक कानून बना दे कि बराक घाटी मिजोरम को दे दी जाए, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब तक संसद यह फैसला नहीं लेती, मैं किसी भी व्यक्ति को असम की जमीन नहीं लेने दूंगा। हम अपनी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।

उन्होंने कहा कि हम इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। किसी को भी असम के वन क्षेत्र को बर्बाद करने या अतिक्रमण करने नहीं देंगे। मिजोरम की सीमा से सटे असम के तीन जिलों कछार, करीमगंज और हैलाकंडी में विशेष कमांडो की तीन बटालियन तैनात की जाएंगी।

सरमा ने कहा कि असम एक जिम्मेदार राज्य की तरह बर्ताव कर रहा है। लेकिन मिजो नागरिकों ने हमारे जवानों पर गोलीबारी करने के बाद जिस तरह खुशी का इजहार किया उससे हमें बहुत कष्ट हुआ है। उन्होंने कहा कि सेटेलाइट इमेज स्पष्ट है कि हमारी सीमा में सड़क बनाई गई है और खेती के लिए जंगलों का सफाया किया गया।


असम-मिजोरम सीमा पर हुए संघर्ष में जान गंवाने वाले असम पुलिस के जवान नजमुल हुसैन का पार्थिव शरीर बुधवार को उनके पैतृक निवास बारपेटा के कदमगुरी में पहुंचा। प्रेट्र

क्या है मामला

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

केरल विधानसभा में 13 मार्च 2015 को बजट पेश होने के दौरान एलडीएफ (वाम लोकतांत्रिक मोर्चा) के छह सदस्यों ने, जो उस वक्त विपक्ष में थे, वित्त मंत्री को बजट पेश करने से रोकने के लिए जोरदार हंगामा किया था। विरोध करते हुए ये नेता स्पीकर के डायस पर चढ़ गए। वहां फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया। कंप्यूटर, माइक, इमरजेंसी लैंप और अन्य इलेक्ट्रानिक सामान भी तोड़ दिया। इस तोड़फोड़ में 2,20,093 रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ।

लेजिस्लेटिव सीक्रेट्री के कहने पर सदस्यों के खिलाफ आइपीसी और सार्वजनिक संपत्ति नष्ट करने पर रोक कानून की विभिन्न धाराओं में आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ। इस मामले में लोक अभियोजक (सरकारी वकील) ने निचली अदालत में अर्जी दाखिल कर सभी नेताओं के खिलाफ केस वापस लेने की इजाजत मांगी लेकिन निचली अदालत ने अर्जी नामंजूर करते हुए इजाजत देने से इन्कार कर दिया। निचली अदालत और फिर हाई कोर्ट से निराश होने के बाद केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट आई।

कांग्रेस नेता इमरान मसूद पर लगा सरकारी भूमि कब्जाने का आरोप

जागरण संवाददाता, सहारनपुर

- जिला प्रशासन ने भेजा नोटिस, दो अगस्त तक देना होगा जवाब
- मसूद के परिवार ने कई जगहों पर कब्जाई सरकारी जमीन : एसडीएम

कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और दिल्ली राज्य प्रभारी इमरान मसूद पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगा है। इस संबंध में जिला प्रशासन ने उन्हें नोटिस जारी किया है। आरोप है कि उन्होंने गांव मेघछप्पर में सरकारी जमीन पर कब्जा कर अपना कार्यालय बना लिया है। हालांकि इमरान ने आरोपों को खारिज किया है।

एसडीएम सदर अनिल कुमार के अनुसार गांव मेघछप्पर में सरकारी भूमि है। जांच के दौरान पाया गया कि भूमि के खसरा नंबर 264 की 794 वर्गमीटर भूमि राजकीय आस्थान की जमीन है। इस जमीन के 250 वर्गमीटर हिस्से में कांग्रेस नेता इमरान मसूद का पार्टी कार्यालय बना हुआ है। एसडीएम ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी अखिलेश सिंह को दी। इस पर डीएम ने कार्रवाई के आदेश दिए। एसडीएम ने बताया कि जमीन को खाली करने के लिए इमरान मसूद को कई बार सूचित किया गया, लेकिन उन्होंने गौर नहीं किया। अब एसडीएम ने अपने न्यायालय में पीपी एक्ट की धारा चार के तहत वाद दर्ज कर नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में कहा गया है कि कांग्रेस नेता मसूद दो अगस्त तक न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करें, ऐसा न करने पर बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम ने बताया कि इमरान मसूद के अलावा उनके परिवार के सलमान मसूद, जीशान मसूद और फौजान मसूद ने भी कई स्थानों पर राजकीय आस्थान की जमीन पर कब्जा कर रखा है। जल्द ही इन सभी को नोटिस जारी किया जाएगा।

मसूद बोले, मेरी जमीन पर है कार्यालय : इधर, कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा कि मेरा निजी कार्यालय बीस सालों से चल रहा है। मेरी खुद की चार हजार गज जमीन है, उसके ही हिस्से पर कार्यालय बना है। मुझे सरकारी जमीन कब्जाने की कोई जरूरत नहीं। प्रशासन पैमाइश करवा ले।

जवाब से असंतुष्ट हाई कोर्ट ने ट्विटर को लगाई फटकार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : नए आइटी नियमों का अनुपालन नहीं करके बार-बार भ्रमित करने वाले जवाब दाखिल करने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्विटर को फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि वह दाखिल किए गए हलफनामे से संतुष्ट नहीं हैं। पीठ ने ट्विटर को एक सप्ताह के अंदर स्पष्ट हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई छह अगस्त को होगी।

अमित आचार्य की याचिका पर सुनवाई के दौरान ट्विटर की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता साजन पुवैया ने पीठ को बताया कि मुख्य शिकायत अधिकारी व स्थानीय शिकायत अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है और यह भी स्पष्ट किया गया है कि हम अंतरिम शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस पर पीठ ने कहा कि पहले आपने अंतरिम शब्द का इस्तेमाल किया और अब आकस्मिक का कर रहे हैं, आखिर अब यह क्या है। पुवैया ने जवाब में कहा कि क्योंकि ट्विटर देश से बाहर है और कंपनी इसी शब्द का इस्तेमाल करती है।

धनबाद में न्यायाधीश की मौत, सीसीटीवी देख लगा हत्या हुई

जागरण संवाददाता, धनबाद

- सीसीटीवी में दिखा, सुनसान सड़क पर अचानक जज की ओर मुड़ा आटो और टक्कर मारकर चला गया

धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की बुधवार की सुबह सड़क दुर्घटना में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। प्रथम दृष्ट्या न्यायाधीश की मौत सड़क दुर्घटना मानी जा रही थी, परंतु सीसीटीवी फुटेज आने के बाद हत्या की आशंका को बल मिलने लगा है। फुटेज में नजर आ रहा है कि जज सड़क के एकदम किनारे वाक कर रहे हैं, लेकिन सड़क खाली होने के बावजूद आटो उनकी ओर मुड़ा और टक्कर मारकर बिना रुके भाग निकला। जज काफी देर तक घटनास्थल पर पड़े रहे और उनकी मौत हो गई।

विपक्षी दल भाजपा, बार एसोसिएशन ने इस मामले की गंभीरता से जांच की मांग की है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने इस मामले की एसआइटी जांच कराने की मांग की है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ट्वीट कर धनबाद के उपायुक्त और एसएसपी को इस पूरे प्रकरण की जांच उच्च स्तरीय समिति बनाकर करने को कहा है। साथ ही एक सप्ताह के अंदर इसकी रिपोर्ट तलब की है। झारखंड हाई कोर्ट ने भी जिला जज से इस मामले में रिपोर्ट तलब की है। धनबाद सिविल कोर्ट के रजिस्ट्रार अर्पित श्रीवास्तव की शिकायत पर धनबाद थाने में अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध टक्कर मार देने की प्राथमिकी दर्ज की गई थी, लेकिन पुलिस अब हत्या के एंगल से भी जांच कर रही है। जज उत्तम आनंद हजारीबाग के रहने वाले थे। उनके पिता व भाई हजारीबाग कोर्ट में अधिवक्ता हैं, जबकि उनके दो साले और एक बहनोई आइएएस अधिकारी हैं।

मार्निंग वाक कर रहे थे न्यायाधीश : रोज की तरह न्यायाधीश मार्निंग वाक करने अपने आवास से गोल्फ ग्राउंड जा रहे थे। तभी रणधीर वर्मा चौक के आगे न्यू जजेज कालोनी के पास समान दिशा से आ रहे एक आटो ने उन्हें पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। न्यायाधीश तड़पते रहे परंतु उन्हें उठाने कोई नहीं आया। कुछ देर बाद पीएचडी के एक कर्मचारी पवन पांडेय की नजर उन पर पड़ी तो पवन ने उन्हें आटो पर लादकर एसएनएमसीएच पहुंचाया, जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

स्टेट बार काउंसिल ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग : बार काउंसिल के स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद यह मामला पूरी तरह से हत्या का प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि दो दिन पूर्व ही रांची के तमाड़ में अधिवक्ता मनोज झा की गोली मारकर अपराधियों ने हत्या कर दी थी और आज न्यायाधीश की मौत हुई है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच करे। स्टेट बार काउंसिल के सदस्य हेमंत सिकरवार ने जज की मौत की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।


धनबाद में सड़क पर पैदल सैर करते न्यायाधीश उत्तम आनंद, पीछे सीसीटीवी में कैद हुआ आटो। आशंका जताई जा रही है कि इसी आटो की टक्कर से न्यायाधीश की मौत हुई। स्रोत : पुलिस


दिवंगत न्यायाधीश उत्तम आनंद (फाइल फोटो)। स्रोत : स्वजन

कई चर्चित मुकदमों की कर रहे थे सुनवाई

न्यायाधीश आनंद 2002 बैच के न्यायिक पदाधिकारी थे। 29 मई 2002 को उन्होंने बोकारो में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में योगदान दिया दिया था। इसके बाद उन्होंने चतरा, जमशेदपुर, गुमला, रांची, डाल्टनगंज, तेनुघाट में अपनी सेवा दी थी। 21 सितंबर 20 को उन्होंने धनबाद में योगदान दिया था। वे धनबाद के चर्चित रंजय हत्याकांड व राजेश गुप्ता के घर बमबारी मामले की सुनवाई कर रहे थे। तीन दिन पूर्व ही उन्होंने यूपी के इनामी शूटर अभिनव सिंह और अमन सिंह के गुर्गे रवि ठाकुर व आनंद वर्मा की जमानत खारिज की थी।

हकीम खां सूरी की मजार में तोड़फोड़

विवाद

महाराणा के सेनापति रहे सूरी की हल्दीघाटी के दर्रे में है मजार, मुस्लिमों के साथ ही हिंदू भी उद्वेलित, पुलिस अधीक्षक ने लापरवाही बरतने पर थानाधिकारी को किया लाइन हाजिर

संवाद सूत्र, उदयपुर

महाराणा प्रताप के सेनापति रहे हकीम खां सूरी की हल्दीघाटी स्थित मजार में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। असामाजिक तत्वों ने मजार को क्षतिग्रस्त करने के साथ वहां लगे टिनशैड को भी हटा दिया है। पुलिस अधीक्षक ने इस घटना को लेकर खमनोर थानाधिकारी कैलाश सिंह को लाइन हाजिर कर दिया है। हालांकि, थानाधिकारी ने बाद में मजार की मरम्मत कराई तथा टिनशैड को सही कराया। घटनास्थल पर पुलिस की तैनाती भी सुनिश्चित की गई है।

गौरतलब है कि हल्दीघाटी दर्रे के समीप महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खां सूरी की मजार है। इसे असामाजिक तत्वों ने नुकसान पहुंचाया है। इसका वीडियो वायरल हुआ तो मुस्लिम समाज के लोग ही नहीं, बल्कि हिंदू समाज के लोग भी उद्वेलित हो उठे। घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने कहा कि यह गंभीर मामला। मजार को क्षतिग्रस्त करने और लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का मामला दर्ज किया गया है। मामले में थानाधिकारी कैलाश सिंह की लापरवाही को लेकर शिकायत मिली है और इसकी जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश गुप्ता के नेतृत्व में टीम गठित की गई है। थानाधिकारी कैलाश सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया है। पुलिस-प्रशासन मामले पर नजर रखे हुए है। पुलिस कहा कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।


राजस्थान के राजसमंद जिले में हल्दीघाटी स्थित महाराणा प्रताप के सेनापति हकीम खां सूरी की मजार की मरम्मत कराई गई। असामाजिक तत्वों ने मजार को क्षतिग्रस्त कर दिया था। जागरण

वायरल वीडियो में मस्जिद बनाने का था जिक्र

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश गुप्ता ने बताया कि कुछ दिन पहले इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें मुस्लिम समाज द्वारा मजार पर निर्माण कार्य कर मस्जिद बनाने का जिक्र किया जा रहा था। थानाधिकारी कैलाश सिंह को पूर्व में वायरल वीडियो को लेकर निगरानी के निर्देश दिए थे फिर भी मजार का टूट जाना गंभीर लापरवाही है। निर्देश को गंभीरता से लिया जाता तो मजार पर तोड़फोड़ नहीं होती।

स्टेशन की लिफ्ट में फंसा परिवार, छूट गई ट्रेन

जागरण संवाददाता, मऊ

- मऊ से मोतिहारी के लिए पकड़ने जा रहे थे बापूधाम एक्सप्रेस

बापूधाम एक्सप्रेस (05162) में सवार होकर मऊ जंक्शन से मोतिहारी जाने के लिए आया एक परिवार बुधवार को लिफ्ट में फंस गया, जिससे ट्रेन छूट गई। आरपीएफ के जवानों के साथ ही तकनीकी शाखा के लोगों ने करीब 45 मिनट बाद सभी को लिफ्ट से बाहर निकाला।

कोपागंज विकासखंड के बसारथपुर गांव यात्री इकबाल मुहम्मद सुबह पत्नी व दो छोटे बच्चों के साथ ट्रेन पकड़ने पहुंचे। वह प्लेटफार्म संख्या एक से तीन पर जाने के लिए फुट ओवरब्रिज से लगे लिफ्ट में स्वजन संग सवार हो गए। लिफ्ट ऊपर जाते समय रास्ते में रुक गई। पूरा परिवार उसमें 09:05 से 9:50 तक फंसा रहा। उधर, बापूधाम एक्सप्रेस प्लेटफार्म संख्या तीन से रवाना हो गई। सूचना पर पहुंचे तकनीकी कर्मियों ने काफी प्रयास के बाद पूरे परिवार को लिफ्ट से बाहर निकाला। बाद में उन्हें पूर्वांचल एक्सप्रेस से मोतिहारी भेजा गया। आरपीएफ प्रभारी प्रदीप पांडेय ने बताया कि लिफ्ट के अंदर का चैनल गेट सही से बंद न होने के कारण घटना हुई।

लिफ्ट में कैसे बीते 45 मिनट : इकबाल ने बताया कि लिफ्ट रुकते ही बच्चे जोर-जोर से चिल्लाने लगे। पत्नी भी घबरा गई। लिफ्ट के अंदर लिखे इमरजेंसी नंबर पर फोन करके सूचना दी। साथ ही लिफ्ट के दरवाजे को किसी तरह हल्का सा खोलकर आवाज लगाई तो आसपास के लोग भी समझ गए कि लिफ्ट में कोई फंसा है। बताया कि वे एक निजी कंपनी में तकनीशियन हैं। इसलिए बहुत घबराहट नहीं हुई। पता था कि जल्द ही इसका कोई न कोई समाधान निकल जाएगा।

कालेज प्राचार्य ने एलएलबी की परीक्षा में अपनी जगह चपरासी को बैठाया

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद : उत्तर गुजरात के हेमचंद्राचार्य विश्वविद्यालय की एलएलबी प्रथम वर्ष की आनलाइन परीक्षा में एक कालेज के प्राचार्य ने अपने स्थान पर चपरासी को बैठा दिया। विश्वविद्यालय द्वारा कराई गई जांच में दोषी पाए जाने पर प्राचार्य का परीक्षा परिणाम रद कर दिया गया है और अब उनपर कार्रवाई की तलवार लटक रही है।

हेमचंद्राचार्य विवि की एलएलबी प्रथम वर्ष के पहले सेमेस्टर की आनलाइन परीक्षा मई 2021 में आयोजित की गई थी। मोडासा के एक कालेज के प्राचार्य को इसमें बतौर परीक्षार्थी शामिल होना था, लेकिन उन्होंने अपनी जगह चपरासी को परीक्षा में बैठा दिया। प्राचार्य ने कानून के एक छात्र की भी मदद ली। गुमनाम शिकायती पत्र मिलने के बाद विश्वविद्यालय के कुलपति ने एक सदस्यीय समिति से मामले की जांच करवाई और फर्जी परीक्षार्थी की बात पकड़ी गई।

केरल में कोरोना विस्फोट, आधे मामले यहीं से

हालात ▶ बकरीद पर पाबंदियों में छूट से संक्रमण बढ़ने की जताई थी आशंका

सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले बढ़ने पर सख्त कार्रवाई की दी थी चेतावनी

जेएनएन, नई दिल्ली

केरल में कोरोना संक्रमण का विस्फोट हुआ है। बीते 24 घंटे के दौरान देश में पाए गए संक्रमण के कुल मामलों में से 50 फीसद से अधिक अकेले केरल से हैं। वैसे तो मामलों में अचानक वृद्धि को लेकर कोई ठोस वजह नहीं बताई गई है, लेकिन बकरीद के मौके पर पाबंदियों में छूट से संक्रमण बढ़ने की आशंका जताई गई थी। यहां तक कि राज्य की वामदल सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने भी नाराजगी जताई थी और संक्रमण बढ़ने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी थी। 21 जुलाई को बकरीद थी और उससे पहले विजयन सरकार ने केरल में तीन दिन यानी 18, 19 और 20 जुलाई को कोरोना पाबंदियों में छूट देते हुए बाजार खोलने की अनुमति दी थी।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बुधवार सुबह आठ बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक दिन में कुल 43,654 नए केस मिले हैं, जिनमें से अकेले केरल से ही 22,129 मामले हैं।

केरल में 37 फीसद सक्रिय मामले, संक्रमण दर 12.35 फीसद : केरल में सक्रिय मामले भी ज्यादा हैं। देश में करीब चार लाख सक्रिय केस हैं, जिनमें से 1.45 लाख यानी करीब 37 फीसद अकेले केरल से हैं। केरल के चलते पिछले एक दिन में एक्टिव केस में हजार से ज्यादा की वृद्धि हुई है, क्योंकि राज्य में 22 हजार से अधिक नए संक्रमित मिले हैं तो मात्र 13 हजार लोग स्वस्थ घोषित किए गए। यही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर मंगलवार को संक्रमण दर जहां ढाई फीसद दर्ज की गई केरल में यह 12.35 फीसद रही।

देश में कोरोना की स्थिति

43,654 24 घंटे में नए मामले

3,99,436 कुल सक्रिय मामले

42.44 लाख 24 घंटे में टीकाकरण

44.61 करोड़ कुल टीकाकरण



केरल में भारी पड़ रही है लापरवाही। फाइल फोटो

पूर्वोत्तर को छोड़कर शेष राज्यों में स्थिति नियंत्रण में

केरल के बाद पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में मामले बढ़ रहे हैं, खासकर मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा बाकी के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थिति लगभग नियंत्रण में हैं। मामले घट नहीं रहे हैं तो बढ़ भी नहीं रहे हैं।

बुधवार सुबह आठ बजे तक की स्थिति

43,654 नए मामले

3,14,84,605 कुल मामले

3,99,436 सक्रिय मामले

640 मौतें (24 घंटे में)

4,22,022 कुल मौतें

17,36,957 जांचें (मंगलवार)

46,09,00,978 कुल जांचें

97.39 % ठीक होने की दर

1.34% मृत्यु दर

2.51% पाजिटिविटी दर

2.36% सा. पाजिटिविटी दर

बुधवार शाम छह बजे तक किस राज्य में कितने टीके

राज्य	टीके
मध्य प्रदेश	9.05 लाख
उत्तर प्रदेश	5.31 लाख
राजस्थान	4.12 लाख
महाराष्ट्र	3.24 लाख
बंगाल	2.25 लाख
हरियाणा	1.24 लाख
बिहार	1.01 लाख
पंजाब	0.83 लाख
जम्मू-कश्मीर	0.57 लाख
दिल्ली	0.57 लाख
झारखंड	0.49 लाख
हिमाचल	0.46 लाख
छत्तीसगढ़	0.30 लाख
उत्तराखंड	0.29 लाख

(कोविन प्लेटफाम के आंकड़े)

उप्र में बढ़े ढाई गुना कोरोना रोगी, कानपुर में 22 नए मिले

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : यूपी में बुधवार को कोरोना मरीजों की संख्या में करीब ढाई गुना बढ़ोतरी हुई। प्रदेश में 89 नए रोगी मिले। इसमें से 22 मरीज अकेले कानपुर में ही सामने आए, जबकि एक दिन पहले मंगलवार को यहां केवल दो रोगी सामने आए थे। कानपुर में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम था। उनसे मिलने वालों की सूची में शामिल पांच लोग भी कोरोना पाजिटिव पाए गए। अचानक एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में रोगी बढ़ने से अधिकारियों में खलबली मच गई। बीते मंगलवार को प्रदेश में 36 मरीज मिले थे।

कोरोना से लड़ाई में ढिलाई की कोई गुंजाइश नहीं...

▶ केंद्र ने राज्यों से टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीका और उचित आचरण पर ध्यान बनाए रखने को कहा

▶ कोरोना महामारी संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों को 31 अगस्त तक और बढ़ाया

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश के ज्यादातर हिस्सों में कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में नजर आ रही है। परंतु, केंद्र सरकार ने स्पष्ट कहा है कि महामारी से निपटने में अभी किसी भी तरह की ढिलाई के लिए कोई जगह नहीं है क्योंकि सक्रिय मामले अभी बहुत अधिक हैं। केंद्र ने कोरोना महामारी संबंधी दिशानिर्देशों को 31 अगस्त तक और बढ़ा दिया है।

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से प्रभावी कोरोना प्रबंधन के लिए टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीका और कोरोना संबंधी उचित आचरण की पांच सूत्रीय रणनीति पर ध्यान केंद्रित रखने को कहा है।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में उन्होंने यह भी कहा है कि आने वाले त्योहारों को देखते हुए भीड़भाड़ वाले सभी स्थानों पर कोरोना से बचाव के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक है।

भल्ला ने कहा है कि सक्रिय मामलों में गिरावट के साथ ही आर्थिक और अन्य गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाने लगा है। उन्होंने आगे कहा है, सक्रिय मामलों में गिरावट संतोषजनक है, लेकिन यह ध्यान रखने की जरूरत है कि अभी भी सक्रिय मामले अपेक्षाकृत ज्यादा हैं।

इसलिए, केंद्रीय गृह सचिव ने कहा है कि ढिलाई की कोई गुंजाइश नहीं है। पाबंदियों में छूट देने का फैसला बहुत ही सोच समझकर लिया जाना चाहिए।

भल्ला ने 14 जुलाई को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे अपने पत्र का जिक्र करते हुए कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आर फैक्टर में वृद्धि नहीं हो। आर फैक्टर वह पैमाना है जिसके जरिये यह देखा जाता है कि एक व्यक्ति कितने लोगों को संक्रमित कर रहा है। उन्होंने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे स्थानीय प्रशासन को कोरोना प्रबंधन के लिए आवश्यक उपाय करने के निर्देश दें ताकि समय रहते तीसरी लहर से बचाव हो सके।

हाई कोर्ट ने चारधाम यात्रा पर रोक बढ़ाई

जागरण संवाददाता, नैनीताल : नैनीताल हाई कोर्ट ने चारधाम यात्रा पर रोक को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने तक आगे बढ़ा दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकारी अस्पतालों में खाली पड़े पदों को भरने, एंबुलेंस की उपलब्धता, वैक्सीनेशन सेंटरों की स्थिति, दिव्यांगजन के लिए विशेष व्यवस्था करने, कोरोना से अब तक मौत और डेल्टा वेरिएंट से निपटने के लिए तैयारी के संबंध में सवाल पूछते हुए स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी।

बुधवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली, सच्चिदानंद डबराल सहित अन्य की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई। अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर जो एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में पेश की है, उसमें अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। लिहाजा रोक के आदेश को आगे बढ़ाया जाए।

आइसीएमआर की सलाह से राज्य सीरो सर्वे करें : केंद्र

▶ इससे स्वास्थ्य उपायों को तैयार करने में आवश्यक 'सीरोप्रीवैलेंस' पर जिला-स्तरीय आंकड़ा तैयार किया जाएगा

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आइसीएमआर की सलाह से अपने यहां सीरो सर्वेक्षण करने को कहा, ताकि स्थानीय स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों को तैयार करने में आवश्यक 'सीरोप्रीवैलेंस' पर जिला-स्तरीय आंकड़ा तैयार किया जा सके।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण द्वारा सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों/ प्रधान सचिवों / स्वास्थ्य सचिवों को लिखे गए एक पत्र में यह कहा गया है।

मंत्रालय ने देश के 70 जिलों में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) द्वारा हाल ही में किए गए राष्ट्रीय सीरो सर्वे के निष्कर्षों को भी साझा किया, जिसके अनुसार 11 राज्यों में दो तिहाई आबादी में कोरोना एंटीबाडी पाई गई है। इसमें मध्य प्रदेश में सर्वेक्षण की गई आबादी में सीरोप्रीवैलेंस 79 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 58 प्रतिशत पाया गया। केरल में 44.4 प्रतिशत, राजस्थान में 76.2 प्रतिशत और बिहार में 75.9 प्रतिशत पाया गया। गुजरात में यह 75.3 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 71.0 प्रतिशत, कर्नाटक में 69.8 प्रतिशत, तमिलनाडु में 69.2 प्रतिशत, ओडिशा में 68.1 प्रतिशत, पंजाब में 66.5, तेलंगाना में 63.1, असम में 50.3 और पश्चिम बंगाल में 60.9 प्रतिशत था। आइसीएमआर द्वारा किए गए राष्ट्रीय सीरोप्रीवैलेंस सर्वेक्षण के चौथे दौर के निष्कर्षों का उल्लेख करते हुए, मंत्रालय ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आइसीएमआर के परामर्श से अपने-अपने क्षेत्रों में सीरोप्रीवैलेंस अध्ययन करने की सलाह दी है।

धीरे-धीरे शुरू होने लगीं अंतरराष्ट्रीय उड़ानें

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : कोरोना की दूसरी लहर के बाद सरकार एक बार फिर से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें खोलने का मन बना रही है। हालांकि अंतरराष्ट्रीय उड़ान की इजाजत के लिए संबंधित देश की मंजूरी की भी जरूरत है। इसलिए सरकार कई देशों से इस दिशा में बातचीत कर रही है। फिलहाल मलेशिया, कतर और मालदीव के लिए एयर इंडिया की उड़ानों को इजाजत दे दी गई है।

मालदीव के लिए एयरइंडिया की फ्लाइट 28 जुलाई से उड़ान भरेगी। दिल्ली और मुंबई से यात्री फ्लाइट ले सकेंगे। दक्षिण भारत से भी मालदीव के लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ान भरने की इजाजत दी है। मलेशिया के लिए भी अगस्त महीने से एयर इंडिया की फ्लाइट उड़ान भरेगी। वहीं कतर के लिए अगस्त से फ्लाइट सेवा शुरू की जा रही है। हालांकि एयर इंडिया की तरफ से यह भी कहा गया है कि कतर जाने वाले यात्री के शहर में प्रवेश की जिम्मेदारी उनकी होगी।

'टीके के प्रति झिझक दूर करें धार्मिक नेता'

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता की तुलना में टीकाकरण की धीमी रफ्तार को देखते हुए सरकार इसके प्रति लोगों की उदासीनता दूर करने के प्रयासों में जुट गई है। इस सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को धार्मिक और सामुदायिक नेताओं के साथ बैठक की और उनसे टीके प्रति लोगों में बैठी झिझक दूर करने में मदद की अपील की। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए अभी से चार लाख स्वास्थ्य स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करने का अभियान शुरू किया है जो गांव गांव में मौजूद होंगे।

प्रधानमंत्री ने कोरोना के दौरान मंदिरों, गुरुद्वारों, मस्जिदों और गिरिजाघरों समेत तमाम धार्मिक स्थलों में मरीजों के इलाज का प्रबंध करने और जरूरतमंदों को हर तरह की मदद उपलब्ध कराने के लिए धार्मिक संगठनों और नेताओं के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने इसे 'एक भारत, एकनिष्ठ भारत' का बेहतरीन उदाहरण बताया। प्रधानमंत्री ने अब उनसे वैक्सीन के प्रति फैलाये जा रहे दुष्प्रचारों के खिलाफ आम जनता को सचेत करने और उन्हें टीकाकरण के लिए तैयार करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीकाकरण कोरोना के खिलाफ लड़ाई का अहम हथियार है और इसके माध्यम से सभी देशवासियों को सुरक्षित करना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने धार्मिक नेताओं को बताया कि भारत किस तरह दो-दो स्वदेशी वैक्सीन तैयार करने में सफल रहा है। दूसरी ओर, भाजपा अध्यक्ष ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान को हरी झंडी दिखाई। हर बूथ कोरोना मुक्त के नारे साथ इस अभियान के तहत चार लाख स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जो दो लाख गांवों में कोरोना के संक्रमितों को इलाज में मदद करेंगे।

आजादी के अमृत महोत्सव में भी बढ़ाएं भागीदारी : वैक्सीन के प्रति लोगों में उदासीनता दूर करने के साथ ही प्रधानमंत्री ने धार्मिक नेताओं से आजादी के 75वें साल के समारोह में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने की भी अपील की। बैठक में केंद्रीय धार्मिक जन मोर्चा के संयोजक व जमात-ए-इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष सलीम इंजीनियर, भारतीय सर्व धर्म संसद के राष्ट्रीय संयोजक महाऋषि पीठाधीश्वर गोस्वामी सुशील महाराज समेत अन्य धार्मिक नेता मौजूद थे।

भाजपा का मकसद लोगों की सेवा करना

नड्डा ने कहा कि भाजपा सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि उसका मूल उद्देश्य लोगों की सेवा करना है। इन प्रशिक्षित स्वयंसेवकों को किट भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें पल्स आक्सीमीटर, थर्मामीटर, रैपिड एंटीजन टेस्ट किट और अन्य साजो-सामान मौजूद होंगे। शुरुआती जांच के बाद ये संक्रमितों को अस्पताल में भर्ती कराने में भी मदद करेंगे।

राष्ट्रीय फलक

देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में आठ शहरों में छापा

▶ पुणे व मुंबई में 'एनकाउंटर स्पेशलिस्ट' एसीपी संजय पाटिल और मुंबई में डीसीपी राजू भुजबल के परिसर शामिल

नई दिल्ली, प्रेट्र : महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआइ ने राज्य के आठ शहरों में 12 स्थानों पर छापे मारे। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि इन स्थानों में एसीपी संजय पाटिल और डीसीपी राजू भुजबल के परिसर भी शामिल हैं। छापों की यह कार्रवाई मुंबई, पुणे, अहमदनगर, नासिक, ठाणे, सोलापुर, सांगली और उस्मानाबाद में की गई।

पुणे व मुंबई में 'एनकाउंटर स्पेशलिस्ट' पाटिल के परिसरों और अहमदनगर व मुंबई में भुजबल से जुड़े परिसरों पर भी अभियान के दौरान छापेमारी की गई। यह अभियान मंगलवार रात समाप्त हुआ। अन्य परिसर कथित बिचौलियों के हैं जिनके नाम जांच एजेंसी ने उजागर नहीं किए हैं। सीबीआइ ने देशमुख एवं अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम कानून और आपराधिक साजिश से जुड़ी भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। मुंबई पुलिस आयुक्त पद से हटाए जाने के बाद परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में आरोप लगाया था कि देशमुख ने सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाझे को शहर के बार एवं रेस्तरां से 100 करोड़ रुपये की वसूली करने को कहा था। सीबीआइ की प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है, 'प्रारंभिक जांच में प्रथमदृष्टया सामने आया कि मामले में संज्ञेय अपराध हुआ है जहां महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख और अन्य अज्ञात व्यक्तियों ने अपनी सार्वजनिक जिम्मेदारियों के अनुचित और बेईमान प्रदर्शन से अनुचित लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया।'

सीबीआइ ने गैंगस्टर छोटा राजन की जमानत अर्जी का किया विरोध

मुंबई (प्रेट्र): सीबीआइ ने बुधवार को बांबे हाई कोर्ट में छोटा राजन की जमानत अर्जी का विरोध किया और कहा कि गैंगस्टर ने देश के कानून का कभी सम्मान नहीं किया। मामले की अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी।

जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई की एकल पीठ से विशेष लोक अभियोजक प्रदीप घराटे ने कहा कि राजन के खिलाफ कई मामले लंबित हैं और कई में सजा हो चुकी है। घराटे ने कोर्ट से आग्रह किया कि गैंगस्टर की जान को खतरा है, इसलिए उसे जमानत न दी जाए। राजन ने छद्म नाम व पासपोर्ट के जरिये कई देशों की यात्रा की।

अवैध कोयला खनन मामले में सीबीआइ ने 15 जगहों पर की छापेमारी

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल स्थित ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की एक खदान से कोयला चोरी कर बेचने के मामले में सीबीआइ ने बुधवार को बंगाल, उत्तर प्रदेश और ओडिशा सहित 15 स्थानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान 20 लाख रुपये की नगदी, जेवरात और संपत्ति के दस्तावेज बरामद हुए हैं। छापेमारी के दौरान अनेक बैंक लॉकरों का भी पता चला है, जिन्हें खोला जाना अभी बाकी है। सीबीआइ के मुताबिक, छह आरोपितों एवं अन्य अज्ञात के विरुद्ध 27 नवंबर 2020 को मामला दर्ज किया गया था। इसमें वरिष्ठ अधिकारियों समेत केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कुछ अधिकारी-कर्मचारी भी शामिल हैं।

'प्रतिशोध का आरोप लगा बच नहीं सकते परमबीर'

राज्य ब्यूरो, मुंबई

महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को बांबे हाई कोर्ट में कहा कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह यह कहकर अपने ऊपर लगे आरोपों की जांच से नहीं बच सकते कि उनके विरुद्ध बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार के वकील ने यह बात परमबीर सिंह द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई के दौरान कही, जिसमें सिंह ने हाल ही में अपने विरुद्ध दर्ज दो मुकदमों को चुनौती दी है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने इस बात पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है कि परमबीर की याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं।

जस्टिस एसएस शिंदे व जस्टिस एनजे जमादार की पीठ ने परमबीर की याचिका पर सुनवाई करते हुए जब उनके विरुद्ध शुरू की गई दो प्राथमिक जांच के बारे में जानना चाहा तो सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त लोक अभियोजक जयेश यागनिक ने बताया कि दोनों जांच अभी जारी हैं। राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता डेरियस खंबाटा ने हाई कोर्ट द्वारा सिंह की याचिका सुने जाने पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि यह मामला एक अधिकारी सेवा से संबंधित है। इसकी सुनवाई सिर्फ प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में ही हो सकती है। खंबाटा ने कहा, 'सिर्फ इसलिए कि आपने अनिल देशमुख के विरुद्ध कुछ आरोप लगाए हैं, आप अपने विरुद्ध लगे आरोपों से बच नहीं सकते। आपके विरुद्ध इंस्पेक्टर अनूप डांगे ने दो फरवरी, 2021 को शिकायत दर्ज कराई थी। उस समय तक इस प्रकरण की शुरुआत भी नहीं हुई थी।' परमबीर के वकील महेश जेठमलानी ने कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल को अभी कोई समन प्राप्त नहीं हुआ है। यह कार्रवाई बदले की भावना से की जा रही है। जेठमलानी ने आरोप लगाया कि सरकार डीजीपी संजय पांडे के साथ मिलकर देशमुख के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को वापस कराने की साजिश रच रही है। डीजीपी पांडे की ओर से पेश वकील नवरोज सीरवाल ने आरोपों को खारिज कर दिया।

देशमुख के खिलाफ जांच में सहयोग नहीं कर रही महाराष्ट्र सरकार

मुंबई, प्रेट्र : सीबीआइ ने बुधवार को बांबे हाई कोर्ट को बताया कि राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जांच में महाराष्ट्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है। जबकि, हाई कोर्ट ने सीबीआइ को देशमुख के खिलाफ पुलिस कर्मियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं।

मिथुन को राहत, जज ने कहा- डायलाग से नहीं फैलती हिंसा

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा में शामिल होने वाले दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को बुधवार को कथित भड़काऊ भाषण मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी। इस मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश कौशिक चंद ने कहा कि किसी फिल्म के डायलाग से हिंसा नहीं फैलती। न ही अशांति होती है।

न्यायाधीश ने कहा कि शोले फिल्म में अमजद खान से लेकर बहुत से अभिनेताओं ने अब तक हजारों लोकप्रिय डायलाग दिए हैं। ऐसे में चुनाव के बाद की अशांति व हिंसा के लिए मिथुन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसके साथ ही न्यायाधीश चंद ने कोलकाता पुलिस को इस मामले में जांच की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई अब तीन अगस्त को होगी। गौरतलब है कि बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में भाजपा का दामन थामने वाले बालीवुड अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी फिल्म के डायलाग बोले थे। उन्होंने कहा था- मारबो एखाने, लाश पोड़बे शशाने, यानी मारूंगा यहां, तो लाश गिरेगी श्मशान में।

जागरण विशेष

अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस (29 जुलाई)

बाघ इतने बढ़ने लगे कि जंगल छोटे पड़ने लगे

मध्य प्रदेश में अब नए जंगलों को ठिकाना बना रहे बाघ, कार्बेट में भी तीन गुना बढ़ी संख्या

जागरण टीम, नई दिल्ली: देश में बाघों का कुनबा बड़ा हो रहा है। चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या बिहार, सभी जगह बाघों की संख्या में इजाफा हुआ है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के मुताबिक विश्वविख्यात कार्बेट टाइगर रिजर्व (सीटीआर) बाघों की संख्या के मामले में देश के 51 टाइगर रिजर्व में नंबर एक है। हालांकि राज्यों में बाघों की संख्या के लिहाज से उत्तराखंड तीसरे स्थान पर है। वहीं, मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या इतनी बढ़ी है कि वहां के जंगल छोटे पड़ने लगे हैं। उन स्थानों पर बाघ के पगमार्क (पदचिह्न) देखे गए हैं जहां से वह गायब हो चुके थे। बिहार के वाल्मिकी टाइगर रिजर्व में भी बाघ बढ़े हैं। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस (29 जुलाई) पर जानिए देश में कहां और किन प्रयासों से बढ़ रही है बाघों की संख्या।

मप्र ने धोया कलंक: मध्य प्रदेश के माथे पर करीब 15-20 वर्ष पहले बाघों के बेतहाशा शिकार का कलंक लगा था, लेकिन सख्ती और संरक्षण के प्रयासों का नतीजा है कि अब वहां संख्या बढ़ने के बाद बाघ अपने लिए नए ठिकाने बना रहे हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में देश के सर्वाधिक 526 बाघ हैं, जबकि 524 बाघों के साथ कर्नाटक दूसरे स्थान पर है।

नई जगहों पर भी पहुंचे: टाइगर स्टेट कहे जाने वाले मध्य प्रदेश में इंदौर, गुना, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, सतना जिले में पिछले दो दशक से बाघ नहीं देखे गए थे, वहां भी अब इनके पगमार्क मिल रहे हैं। गुना जिले के राघौगढ़ क्षेत्र में करीब आठ माह पहले बाघ के पगमार्क मिले हैं। खंडवा जिले में मां नर्मदा के किनारे जंगल में भी दो दशक बाद बाघ की उपस्थिति दर्ज हुई है। वन अधिकारी बताते हैं कि वर्ष 2002 में जब प्रदेश में करीब 725 बाघ थे, तब इन क्षेत्रों में बाघ पाए जाते थे।

शिकारी गिरोह का था आतंक: मध्य प्रदेश में वर्ष 1995 से वर्ष 2000 के बीच शिकार की सबसे ज्यादा घटनाएं हुईं। संसार चंद और ठोकिया जैसे दुर्दांत शिकारी गिरोह के कारण बाघों का बेतहाशा शिकार हुआ। पन्ना टाइगर रिजर्व से तो बाघ खत्म ही हो गए थे। बीते आठ साल में राज्य सरकार ने शिकंजा कसा। स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स का गठन किया गया, जिसमें डाग स्क्वाड भी है। शिकार में 80 फीसद तक कमी आ गई। बाघ संरक्षण पर भी ठोस काम किया गया। आठ साल में 269 बाघ बढ़ गए।

...और बढ़ने लगी संख्या: वर्ष 2010 में मध्य प्रदेश में 257 बाघ थे, जो वर्ष 2018 में 526 पाए गए। 2006 में तो प्रदेश में महज 300 बाघ बचे थे। बाद में शिकार इतना कम हो गया कि 2020 में 29 बाघों की मौत में से सिर्फ चार में शिकार की पुष्टि हुई। शेष की मौत प्राकृतिक कारणों, वर्चस्व की लड़ाई या ट्रेन से टकराने के चलते हुई। वन्यप्राणी मुख्यालय में पदस्थ उप वनसंरक्षक रजनीश सिंह कहते हैं कि पन्ना, बांधवगढ़ सहित कुछ इलाकों में करीब दो दर्जन बाघों की ट्रैकिंग की जाती है।

इस बार मिलेंगे 700 बाघ: मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व में इस साल जनवरी में गिनती हुई है, जो प्रदेश का टाइगर स्टेट का तमगा बरकरार रखने की उम्मीद जगाती है। संभावना है कि प्रदेश में इस बार बाघों की संख्या 700 के आसपास रहेगी। वन अधिकारी बताते हैं कि वर्ष 2020 की तुलना में 15 से 20 फीसद की वृद्धि हो सकती है। 2020 में सतपुड़ा नेशनल पार्क में 45, पेंच नेशनल पार्क में 64, कान्हा में 118, पन्ना में 42, संजय दुबरी राष्ट्रीय उद्यान में 13 और बांधवगढ़ में 164 बाघ गिने गए थे, जो वर्ष 2018 में क्रमशः 40, 61, 88, 25, पांच और 124 थे।

जैव विविधता से कार्बेट में बढ़े बाघ: दूसरी तरफ, उत्तराखंड के कार्बेट नेशनल पार्क में प्राकृतिक आवास, प्राकृतिक व पक्के वाटरहोल व भरपूर पानी बाघों को सुरक्षित माहौल देते हैं। 700 फील्ड स्टाफ, कई किलोमीटर तक निगाह रखने वाले हाइटेक थर्मल कैमरे, ड्रोन मानिटरिंग, रामगंगा नदी में मोटरबोट से गश्त के इंतजाम यहां के बाघों को संरक्षित रखने का काम कर रहे हैं। कार्बेट नेशनल पार्क का दायरा नैनीताल एवं पौड़ी गढ़वाल जिले तक है।

(इनपुट : भोपाल से मनोज तिवारी, बालाघाट से श्रवण शर्मा, रामनगर से त्रिलोक रावत, बेतिया से शशि कुमार मिश्र)

सीटीआर में बाघों की संख्या

वर्ष	बाघ
2006	160
2010	186
2014	215
2018	231

(2019 में सीटीआर ने आंतरिक गणना भी कराई जिसमें 252 बाघ थे। 2021 में दो बाघ राजाजी रिजर्व हरिद्वार भेजने से अब यहां 250 बाघ वर्तमान में मौजूद है।)



मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क में स्वच्छंद विचरण करता बाघ और उसे निहारते सैलानी ● सौ.: रवि पालेवार, सदस्य, बालाघाट टूरिज्म कौंसिल

मध्य प्रदेश में बाघ

टाइगर रिजर्व	बाघ	शावक
कान्हा नेशनल पार्क	118	40
पन्ना टाइगर रिजर्व	65-70	20 से ज्यादा
पेंच नेशनल पार्क	65	करीब 35
बांधवगढ़ नेशनल पार्क	124	40 से ज्यादा

बिहार के वीटीआर में तीन गुना बढ़े बाघ

बिहार के पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (वीटीआर) में बीते 10 साल में बाघों की संख्या तीन गुना बढ़ी है। वीटीआर को 1994 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। उस समय बाघों की संख्या 26 थी। 2010 में 15 और 2014 की गणना में 31 बाघ मिले थे। 2018 में इनकी संख्या बढ़कर 37 हो गई थी। वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर 45 से 50 होने के संकेत हैं।

> कार्बेट में बाघों के संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों का ही परिणाम है कि यहां इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। जैव विविधता के बीच अनुकूल माहौल में बाघों की बढ़ती संख्या सुखद पहलू है।
> **राहुल**, निदेशक, सीटीआर, रामनगर

> संरक्षण के उपायों ने बाघ को बचाने का काम किया है। अब उनकी आबादी इतनी हो गई है कि जंगल छोटे पड़ने लगे हैं।
> – **एके सिंह**, निदेशक, कान्हा नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश

> मध्य प्रदेश में संसार चंद और ठोकिया जैसे गिरोह खत्म हुए तो बाघ के शिकार पर रोक लगी है। संरक्षण पर ठोस काम हुआ है।
> – **आरके दीक्षित**, पूर्व संचालक, रातापानी अभयारण्य, मध्य प्रदेश

> प्रदेश में बाघों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इस वर्ष भी मध्य प्रदेश अपना टाइगर स्टेट का सम्मान बरकरार रखने में कामयाब रहेगा।
> – **आलोक कुमार**, मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, मध्य प्रदेश

इस खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए स्कैन करें

राष्ट्रीय संस्करण
गुरुवार 29 जुलाई, 2021
दैनिक जागरण
बिजनेस
www.jagran.com

डिजिटल भुगतान में 30.2 फीसद का उछाल

मुंबई : पिछले एक साल के दौरान डिजिटल भुगतान में 30.19 फीसद की बढ़ोतरी हुई है। आरबीआइ द्वारा जारी किए गए इन आंकड़ों से पता चलता है कि लोग बहुत तेजी से कैशलेस ट्रांजेक्शन को अपना रहे हैं। नवगठित डिजिटल भुगतान सूचकांक (आरबीआइ-डीपीआइ) के अनुसार मार्च, 2021 के अंत तक यह बढ़कर 270.59 हो गया था। एक साल पहले यह 207.84 के स्तर पर था। (प्रेट्र)

जरूरी जानकारियां मुहैया कराने के मामले में कई सूचीबद्ध कंपनियों का रवैया उदासीन रहा है। यह खानापूर्ति के लिए किया जाने वाला काम नहीं है।
- अजय त्यागी
चेयरमैन, सेबी



सेंसेक्स	52,443.71	▼ 135.05
निफ्टी	15,709.40	▼ 37.05
सोना प्रति दस ग्राम	₹ 46,607	▼ ₹ 61
चांदी प्रति किलोग्राम	₹ 64,779	▼ ₹ 1094
डॉलर	₹ 74.38	▼ ₹ 0.09
क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल	$ 74.08	

आर्थिक विकास के लिए सेबी बनाएगा सोशल एक्सचेंज

इससे सामाजिक विकास के लिए वित्तीय व्यवस्था का होगा निर्माण

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : पूंजी बाजार नियामक सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी ने कहा है कि कैपिटल मार्केट अर्थव्यवस्था के विकास में अहम भूमिका निभाने जा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए सेबी कैपिटल मार्केट को और मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रहा है। उद्योग संगठन फिक्की के कार्यक्रम में बुधवार को त्यागी ने बताया कि सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए फंड जुटाने को आसान बनाने के लिए सेबी की तरफ से अलग से कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत सोशल स्टाक एक्सचेंज की स्थापना की जाएगी ताकि सामाजिक क्षेत्र के विकास से जुड़ी वित्तीय व्यवस्था के लिए एक पूरा वातावरण तैयार हो सके। उन्होंने बताया कि सेबी ने स्टार्ट-अप्स को एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने में सहूलियत के लिए इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफार्म का गठन किया है। प्रतिभूति बाजार में घरेलू बचत के तहत होने वाले निवेश की हिस्सेदारी बढ़ रही है और इससे कैपिटल मार्केट के साथ अर्थव्यवस्था को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

इसी कार्यक्रम में त्यागी ने यह भी कहा कि नियामक को जरूरी जानकारियां मुहैया कराने में कई कंपनियों का रवैया उदासीन सा रहा है। वे इस महत्वपूर्ण काम को खानापूर्ति के अंदाज में कर रही हैं, जो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा, सूचीबद्ध कंपनियों के लिए नियामक और बाजारों को जानकारियां देने के दो प्रारूप हैं। एक के तहत उन्हें नियमित अंतराल पर कुछ जानकारियां देनी होती हैं। उन्हें दूसरे के तहत समय-समय पर वे जानकारियां देनी होती हैं जो निदेशक बोर्ड द्वारा लिए जाते हैं और निवेशकों के लिए अनिवार्य हैं।

स्पाट मार्केट के माध्यम से सोने के आयात पर विचार

मुंबई, प्रेट्र : पूंजी बाजार नियामक सेबी के पूर्णकालिक निदेशक जी. महालिंगम ने देश में एक अलग गोल्ड स्पाट एक्सचेंज का विचार रखा है। उन्होंने भविष्य में सभी तरह के स्वर्ण आयात सिर्फ स्पाट एक्सचेंज के माध्यम से करने की सलाह दी है। उन्होंने यह भी कहा कि इस विचार को अभी तक सेबी ने किसी भी दस्तावेज का हिस्सा नहीं बनाया है।

डीएफआइ का लोगो बनाइए, पांच लाख रुपये इनाम पाइए

15 अगस्त तक भेज सकते हैं वित्त मंत्रालय को प्रविष्टियां

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के बजट भाषण के दौरान नए डीएफआइ की घोषणा की थी

नई दिल्ली, आइएएनएस : मैन्यूफैक्चरिंग में नई तकनीकों को विकसित करने के लिए नवाचार का प्रयोग लगातार किया जा रहा है। अब वित्त मंत्रालय ने इसके माध्यम से हाल ही में स्थापित डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन (डीएफआइ) का नाम, लोगो और टैगलाइन तय करने का फैसला किया है। इसके लिए उसने एक खुली प्रतियोगिता आयोजित की है। 15 अगस्त तक देश का कोई भी नागरिक इंट्री भेज सकता है।

सर्वश्रेष्ठ नाम, टैगलाइन और लोगो के लिए पांच-पांच लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के बजट भाषण के दौरान नए डीएफआइ की घोषणा की थी। मार्च में संसद के दोनों सदनों ने नेशनल बैंक फार फाइनेंसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट (एनएबीएफआइडी) बिल, 2021 को मंजूरी प्रदान की थी। सरकार अगले महीने तक नए डीएफआइ को शुरू करना चाहती है।

इससे पहले डीएफआइ की तरह रुपये का लोगो बनाने के लिए भी सरकार ने एक खुली प्रतियोगिता आयोजित की थी। इसमें 3,000 डिजाइनरों ने इसमें हिस्सा लिया था। अंतिम पांच डिजाइनों में चेन्नई के डी. उदयकुमार के लोगो पर सरकार ने अपनी मुहर लगाई थी। उन्हें इस डिजाइन के लिए ढाई लाख का इनाम दिया गया था।

मनरेगा में पौने सात करोड़ को रोजगार



5.25 लाख लोगों ने 100 कार्यदिवसों का लक्ष्य चार महीने में ही किया हासिल

11.50 करोड़ अधिक आवंटन योजना को पिछले साल के मुकाबले

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : कोरोना संक्रमण और लाकडाउन के चलते गावों की ओर पलायन करने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए मनरेगा वरदान साबित हुई है। गांवों में रोजगार का प्रमुख साधन बनी इस योजना में काम की मांग बढ़ी है। चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीने में पौने सात करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। इनमें से 5.25 लाख मजदूरों ने निर्धारित 100 कार्यदिवसों का लक्ष्य हासिल कर लिया है और उन्हें अतिरिक्त कार्यदिवसों की जरूरत है।

पिछले वर्ष के मुकाबले चालू वित्त वर्ष में योजना पर काम का दबाव और बढ़ा है। इसके मद्देनजर चालू वित्त वर्ष के लिए 11,500 करोड़ रुपये की वृद्धि के साथ कुल 73,000 करोड़ का आवंटन किया गया है। आने वाले दिनों में मनरेगा के लिए अतिरिक्त धनराशि की जरूरत पड़ सकती है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कुल 11.19 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया कराया गया था। चालू वित्त वर्ष के शुरुआती चार माह के भीतर ही 6.72 करोड़ लोगों को मनरेगा में काम दिया जा चुका है। इससे स्पष्ट है कि चालू वित्त वर्ष में काम मांगने वालों की संख्या बढ़ेगी, जिसके लिए अतिरिक्त बजट की जरूरत पड़ सकती है। अप्रैल से जुलाई के दौरान मनरेगा में 100 दिनों तक काम कर चुके मजदूरों की संख्या 5.25 लाख से अधिक हो चुकी है।

शहरों में काम नहीं मिलने और पलायन कर गांव पहुंचे ग्रामीण मजदूरों को काम की जरूरत है, जिसके लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत रोजगार बेहद मददगार साबित हो रहा है। मांग आधारित योजना होने की वजह से इसके लिए बजट के आवंटन में कोई कमी नहीं की जा सकती है। कोरोना प्रभावित निचले तबके के लोगों और पलायन कर चुके प्रवासी मजदूरों के लिए केंद्र सरकार पहले ही कई योजनाएं चालू कर रखी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों को प्रत्येक महीने पांच किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से अनाज मुफ्त दिया जा रहा है। यह अनाज राशन प्रणाली के तहत हर महीने प्राप्त होने वाले 35 किलो प्रति परिवार से अलग है।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है, मनरेगा के माध्यम से स्थायी निर्माण को प्राथमिकता दी जा रही है। चालू वित्त वर्ष में 73% कार्य कृषि और उससे जुड़े उद्यमों से कराने की योजना है। मनरेगा से कुल 25 लाख स्थायी निर्माण कार्य कराए जा चुके हैं।

रेरा को लेकर अभी भी जागरूकता का अभाव

30 फीसद ग्राहकों को इस कानून के बारे में जानकारी नहीं

50 फीसद कानून के इस्तेमाल की व्यापकता से अनभिज्ञ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : पांच वर्ष पहले केंद्र ने जिस उम्मीद के साथ रियल एस्टेट नियमन व विकास कानून (रेरा) लागू किया था, उसको लेकर अभी बड़े पैमाने पर जागरूकता फैलाने की जरूरत है। घर खरीदने की योजना बना रहे 30 फीसद ग्राहकों को अभी भी इस कानून के बारे में जानकारी नहीं है। लगभग 50 फीसद उपभोक्ता इस कानून के इस्तेमाल की व्यापकता को लेकर अंधेरे में हैं। हालांकि 65 फीसद रियल एस्टेट कंपनियां इस कानून से संतुष्ट हैं, लेकिन 45 फीसद कंपनियों ने यह भी कहा है इसमें संशोधन की जरूरत है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप और ओमिड्यार नेटवर्क इंडिया द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के आधार पर रिपोर्ट में कहा गया है कि रेरा कानून को ज्यादा लोकप्रिय बनाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

रिपोर्ट में मोटे तौर पर यह माना गया है कि जो ग्राहक इसके बारे में जानते हैं उनके बीच रियल एस्टेट व्यवस्था को लेकर ज्यादा भरोसा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि रेरा के तहत हर रियल एस्टेट परियोजना का पंजीयन जरूरी है। इसके साथ ही ग्राहक को अब डेवपलपर्स की तरफ से होने वाले भुगतान के बारे में पता होता है। डेवलपरों को ग्राहकों से मिली रकम की जानकारी भी इस कानून के तहत देनी होती है। रिपोर्ट के मुताबिक जिन ग्राहकों को रेरा के बारे में मालूम हैं उनमें से 76 फीसद ने कहा है कि वह इस कानून के तहत पंजीबद्ध परियोजना में ही आवास खरीदेंगे। 78 % ने कहा है कि कानून के तहत शिकायतों को निर्धारित समय में निपटाने की व्यवस्था होनी चाहिए।

व्यापारियों और उद्योग संगठनों ने की ई-कामर्स कंपनियों की शिकायत

नई दिल्ली, प्रेट्र : व्यापारियों और उद्योग संगठनों से सरकार को ई-कामर्स कंपनियों के खिलाफ एफडीआइ नियमों के उल्लंघन की शिकायतें मिली हैं। लोकसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री सोमप्रकाश ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन आरोपों के अनुसार ई-कामर्स कंपनियों ने ना केवल मालिकाना हक को लेकर एक जटिल ढांचा तैयार किया, बल्कि वे अपने प्लेटफार्म पर उन्हीं विक्रेताओं को वरीयता देती रही हैं, जो किसी न किसी रूप में उनसे संबद्ध हैं।

वाणिज्य राज्यमंत्री के मुताबिक उद्योग संगठनों ने आरोप है कि ई-कामर्स कंपनियां भारी-भरकम छूट देने और दूसरों का बाजार बिगाड़ने वाली मूल्य नीति सहित मोबाइल जैसे उत्पादों की एक्सक्लूसिव लांचिंग भी करती हैं। वर्तमान एफडीआइ नीति ई-कामर्स कंपनियों को सिर्फ बिजनेस-टु-बिजनेस व्यापार की अनुमति देती है। ई-कामर्स के मार्केटप्लेस माडल में आटोमैटिक रूट के तहत 100 फीसद एफडीआइ की भी अनुमति है।

स्पाइसजेट ने 127 करोड़ रुपये उधार लिए: स्पाइसजेट और गो फर्स्ट एयरलाइंस ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत क्रमशः 127.51 करोड़ रुपये और 25.65 करोड़ रुपये उधार लिए हैं। यह जानकारी नागरिक उड्डन राज्यमंत्री वीके सिंह ने बुधवार को संसद में दी। गो फर्स्ट को पहले गोएयर के नाम से जाना जाता था।

52,391 स्टार्ट-अप मान्यता प्राप्त

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआइआइटी) द्वारा 14 जुलाई तक 52,391 कंपनियों को स्टार्ट-अप के तौर पर मान्यता दी गई है। वाणिज्य और उद्योग राज्यमंत्री सोम प्रकाश ने लोकसभा में यह जानकारी दी। जिन स्टार्ट-अप को मान्यता दी गई है, उसमें 53 यूनिकार्न (100 करोड़ डालर मूल्य से अधिक की कंपनी) हैं और इनका कुल मार्केट कैप 1.4 लाख करोड़ रुपये हैं।

आइबीसी संशोधन बिल लोकसभा से पारित

लोकसभा ने बुधवार को दिवालिया प्रक्रिया से जुड़े आइबीसी संशोधन बिल को बिना किसी बहस के पास कर दिया। कारपोरेट मामलों के राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बिल को सदन में रखा, लेकिन विपक्षी सदस्य हंगामा करते रहे। यह बिल चार अप्रैल को आए अध्यादेश की जगह लेगा। वहीं लोकसभा ने पूरक मांगों पर भी मुहर लगा दी है। इसके बाद सरकार 23,675 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च कर सकेगी।

स्माल एलएलपी की परिभाषा में बदलाव

जाब्यू, नई दिल्ली : बुधवार को कैबिनेट ने छोटी कंपनियों को कारोबारी राहत देने के लिए लिमिटेड लायब्लिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी। इसके तहत एलएलपी के तहत काम कर रही 2.30 लाख कंपनियों को फायदा होगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया, स्माल एलएलपी की नई परिभाषा तय की गई है। अभी 25 लाख रुपये तक के योगदान और 40 लाख तक टर्नओवर वाली फर्म को स्माल एलएलपी माना जाता है, लेकिन नई परिभाषा के तहत पांच करोड़ तक के योगदान और 50 करोड़ तक के टर्नओवर वाली फर्म को स्माल एलएलपी माना जाएगा। एलएलपी को कारोबारी राहत देने के लिए उनके खिलाफ होने वाली कार्रवाई के प्रविधान को घटाकर 22 कर दिया गया है।

एलआइसी के आइपीओ का रास्ता साफ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : एलआइसी के प्रारंभिक पब्लिक आफर (आइपीओ) का रास्ता साफ हो गया है। बुधवार को कैबिनेट कमेटी ने जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एक्ट, 1972 में संशोधन की मंजूरी दे दी। इसके साथ ही इस कानून के तहत इंश्योरेंस सेक्टर में स्थापित सरकारी बीमा कंपनियों में निजी कंपनियों की भागीदारी हो सकेगी। सूत्रों के मुताबिक मुख्य रूप से एलआइसी में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए सरकार ने यह मंजूरी दी है।

इंश्योरेंस बिजनेस कानून, 1972 में संशोधन के बगैर सरकार एलआइसी में अपनी हिस्सेदारी नहीं बेच सकती है। बजट घोषणा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दो सरकारी बैंकों और एक इंश्योरेंस कंपनी के विनिवेश की घोषणा की थी। चालू वित्त वर्ष (2021-22) में सरकार ने विनिवेश से 1.75 लाख करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखा है। चालू वित्त वर्ष में अब तक सरकार विनिवेश से सिर्फ 7,646 करोड़ जुटा सकी है। हाल ही में सरकार ने तेल व गैस क्षेत्र की सार्वजनिक कंपनियों में 100 फीसद विदेशी निवेश की मंजूरी दी है, ताकि विदेशी निवेशक इनमें हिस्सेदारी खरीद सके।

दूसरी तरफ, बुधवार को वित्त मंत्रालय के निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव टीके पांडेय ने एक कार्यक्रम में बताया कि चालू वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही (जनवरी-मार्च, 22) में एलआइसी का आइपीओ लाने की तैयारी चल रही है। विभाग ने एलआइसी के आइपीओ के लिए इंवेस्टमेंट बैंकर्स और कानूनी सलाहकार को प्रस्ताव देने के लिए आमंत्रित किया है। उद्योग संगठन फिक्की के कार्यक्रम में पांडेय ने कहा कि एलआइसी का आइपीओ भारत समेत वैश्विक बाजारों के लिए उत्सुकता का विषय है।

राष्ट्रीय फलक

न्यूज गैलरी

पान मसाला कंपनी पर छापा, एक अरब की गड़बड़ी मिली

कानपुर : आयकर अधिकारियों ने एसएनके पान मसाला निर्माताओं के घर, फैक्ट्री, गोदाम समेत 19 स्थानों पर बुधवार को एक साथ छापेमारी की। सुबह सात बजे कानपुर, उरई, दिल्ली और नोएडा में एक साथ कार्रवाई शुरू हुई। अब तक एक अरब रुपये से अधिक की गड़बड़ी पकड़ी गई है। यह रकम मुखौटा कंपनियों के जरिये कारोबार में लगाई गई थी। ये पान मसाला एजे सुंगधी कंपनी में बनता है। (जासं)

ओडिशा में ठगी का आरोपित बरेली में गिरफ्तार

बरेली : ओडिशा में चिटफंड कंपनी बना करोड़ों की ठगी का आरोपित राजस्थान के बीकानेर के त्रिपोलिया निवासी दिलीप जैन फाइव स्टार होटल रेडिसन में छिपा हुआ था। बुधवार को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड लेने के बाद ओडिशा क्राइम ब्रांच सीओ इतिदास व उनकी टीम उसे ओडिशा ले गई। वह वर्ष 2016 से फरार चल रहा था। (जासं)

इनामी नक्सली गिरफ्तार, 11 ने किया आत्मसमर्पण

दंतेवाड़ा : छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में नक्सलियों के शहीदी सप्ताह के पहले जियाकोड़ता के जंगल से उसने पांच लाख के इनामी मिलिशिया कमांडर इन चीफ हांदा कर्रा मंडावी को गिरफ्तार कर लिया है। डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड (डीआरजी) के जवानों ने चिरमुर के जंगल में महिला नक्सली पाले व विज्जो के बने स्मारक को ध्वस्त किया है। वहीं, किरंदुल थाने में एक लाख के इनामी समेत 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। (नईदुनिया)

सिंडिकेट बैंक फर्जीवाड़े में करोड़ों की संपत्ति जब्त

नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बताया कि उसने सिंडिकेट बैंक की बेंगलुरु शाखा में हुए फर्जीवाड़े में आरोपितों की पांच करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। कुछ समय पहले शुरू हुई जांट में पाया था कि आरोपित आकाश ने जयराम, नागराजू, रेवन्ना, सिद्दागंगैया व अन्य के साथ मिलकर कर्नाटक स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड के नाम पर फर्जी करंट अकाउंट खोला था। (प्रेट्र)

सारधा समूह के मुखिया सुदीप्त के पास अब जमानत के लिए रुपये नहीं

राज्य ब्यूरो, कोलकाता



ज्यादा की चाहत में सब गवां बैठे सुदीप्त सेन। फाइल फोटो

कभी अरबों रुपये के मालिक रहे सारधा समूह के प्रमुख सुदीप्त सेन के पास अब अपनी जमानत कराने तक के लिए रुपये नहीं हैं। सारधा चिटफंड घोटाले में सुदीप्त सेन पिछले आठ वर्षों से जेल में हैं। उसके खिलाफ विभिन्न अदालतों में चार मामले चल रहे हैं, जिनमें से तीन में उसे जमानत मिल गई है। अदालत की ओर से सुदीप्त सेन को व्यक्तिगत मुचलके के तौर पर 30,000 रुपये जमा कराने को कहा गया है, लेकिन उसके पास इतने रुपये भी नहीं हैं।

सुदीप्त सेन के अधिवक्ता ने कहा कि वह उसे 1980 से जानते हैं। अब उसकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। उसकी दो पत्नियां व बच्चे हैं। सभी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। सारे रिश्तेदारों ने उससे नाता तोड़ लिया है। गौरतलब है कि सुदीप्त सेन के खिलाफ सीबीआइ की तरफ से दो मामले दर्ज किए गए हैं। दोनों मामले अलीपुर अदालत में विचाराधीन हैं। एक अन्य मामला बिधाननगर अदालत में चल रहा है, जबकि चौथा मामला बैंकशाल कोर्ट में चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में है।

एक समय बेहद शानोशौकत भरी रही है सुदीप्त की जिंदगी : सुदीप्त सेन की जिंदगी एक समय बेहद शानोशौकत भरी रही है। वह कभी आलीशान बंगले में रहता था। उसके पास कई महंगी गाड़ियां थीं। महंगे कपड़े और घड़ियां पहनने का उसे शौक था। वह विदेशी परफ्यूम का इस्तेमाल करता था। दर्जनों नौकर उसकी सेवा में लगे रहते थे। उसने सारधा समूह के तहत खोली गई अपनी विभिन्न कंपनियों में मोटी तनख्वाह पर लोगों को नौकरी दी थी। वह अक्सर शानदार पार्टियां दिया करता था।

दुष्कर्म की शिकायत लेकर आई नाबालिग का थाने में हुआ प्रसव

छिंदवाड़ा (नईदुनिया प्रतिनिधि)।

- नाबालिग और उसका बच्चा स्वस्थ, पुलिस ने आरोपित को हिरासत में लिया

अपने साथ हुई दुष्कर्म की शिकायत करने थाने आई नाबालिग की बुधवार को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के कुंडीपुरा थाने में ही प्रसूति हो गई। उसने स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। नाबालिग को प्रसव पीड़ा होने पर थाना प्रभारी पूर्वा चौरसिया, एक महिला पुलिसकर्मी व अन्य महिलाओं ने प्रसव करवाया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपित युवक आकाश युवनाती के खिलाफ दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है।

थाना प्रभारी के मुताबिक नाबालिग को प्रसव पीड़ा होने पर एक महिला आरक्षक और परिसर में घरेलू काम करने वाली महिलाओं की मदद से उसकी डिलीवरी करवाई गई। पीड़िता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नाबालिग और उसका बच्चा पूरी तरह स्वस्थ हैं। पीड़िता ने शिकायत में बताया था कि उसी के गांव के आकाश युवनाती ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और उसका गर्भ ठहर गया। आरोपित बीते नौ महीने से शादी की बात कहकर उसे थाने आने से रोक रहा था। तीन दिन पहले वह शादी से मुकर गया। इसके बाद पीड़िता बुधवार को थाने पहुंची। गौरतलब है कि नौ मार्च को लवाघोघरी थाने में भी इसी तरह का मामला सामने आया था। उस वक्त महिला आरक्षक शीतल वाघमारे ने थाने में प्रसव करवाया था।

बंधक बनाकर नौ साल की बच्ची से दुष्कर्म

जासं, बाहरी दिल्ली : शालीमार बाग इलाके में बंधक बनाकर नौ साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस बाबत दुष्कर्म, पोक्सो व अपहरण की धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपित सलीम को गिरफ्तार कर लिया गया है। अस्पताल में भर्ती बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार बच्ची रविवार को दिन में लगभग 12 बजे अपने घर के निकट खेल रही थी। उसी दौरान आरोपित ने बच्ची को कपड़े व टाफी दिलाने की बात कही और उसे ई रिक्शा पर बैठाकर झुग्गी में लेकर गया, जहां उसने चाकू का डर दिखाकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और इसके बाद शाम करीब छह बजे बच्ची को ई रिक्शा से वापस उसके घर के निकट छोड़कर फरार हो गया। वह जब घर पहुंची तो बेहोश हो गई। बच्ची को अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया।

खेल जागरण

श्रीलंका ने भारत को चार विकेट से दी शिकस्त

क्रुणाल के पाजिटिव आने व आठ अन्य के क्वारंटाइन में जाने से बनी अजीब स्थिति

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

मध्य क्रम के बल्लेबाज धनंजय डिसिल्वा के नाबाद 40 रन व सलामी बल्लेबाज मिनोद भानुका के 36 रन की बदौलत श्रीलंका ने बुधवार को कोलंबो में दूसरे टी-20 मैच में भारत को चार विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल कर ली। भारत ने कप्तान शिखर धवन की 42 गेंदों पर पांच चौकों की मदद से खेली गई 40 रन की पारी की बदौलत पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में पांच विकेट पर 132 रन का स्कोर बनाया। जवाब में श्रीलंका ने 19.4 ओवर में छह विकेट पर 133 रन बनाकर जीत दर्ज की। डिसिल्वा ने 36 गेंदों पर एक चौका व एक छक्का जड़ा, जबकि भानुका ने 31 गेंदों पर चार चौके जड़े। भारत की ओर से कुलदीप यादव (2/30)सबसे सफल गेंदबाज रहे।

लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने नियमित अंतरात पर विकेट खोए, लेकिन पहले भानुका और फिर उसके बाद डिसिल्वा ने एक छोर थामे रखा। डिसिल्वा ने निचले क्रम में पांचवें विकेट के लिए वानिंदु हसरंगा (15) के साथ 28 रन और सातवें विकेट के लिए चमिका करुणारत्ने (नाबाद 12) के साथ 28 रन की अटूट साझेदारी की और अपनी टीम को जीत दिलाई।

भारत ने कराया चार खिलाड़ियों को पदार्पण

नई दिल्ली : कोलंबो में मैच शुरू होने से पूर्व भारत के पास अंतिम एकादश चुनने के लिए अतिरिक्त विकल्प नहीं था। क्रुणाल पांड्या के पाजिटिव पाए जाने के बाद उनके संपर्क में आए आठ अन्य क्रिकेटरों का बुधवार सुबह रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया, जिसकी दोपहर तक रिपोर्ट निगेटिव आ गई थी। हालांकि, इन सभी को एहतियातन मैदान पर नहीं उतारने का फैसला किया गया। मैच से पहले कोच राहुल द्रविड़ ने कहा, 'अब जब स्थिति ऐसी हो गई है कि क्रुणाल पांड्या के पाजिटिव पाए जाने के बाद उनके संपर्क में आए आठ लोग नहीं नहीं खेल पाएंगे तो जो भी अब हमारे पास 11 बचे हैं, उन्हें ही खेलना होगा।' ऐसे में चार खिलाड़ियों रुतुराज गायकवाड़, देवदत्त पडीक्कल, नीतीश राणा और चेतन सकारिया को टी-20 पदार्पण करने का मौका मिला।

कोहली व राहुल अपने स्थान पर कायम, भुवी व चहल चढ़े

दुबई, प्रेट्र : भारतीय कप्तान विराट कोहली और बल्लेबाज केएल राहुल बुधवार को जारी ताजा आइसीसी टी-20 रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में क्रमशः पांचवें और छठे स्थान पर बरकरार हैं। राहुल और कोहली उस भारतीय टीम का हिस्सा नहीं हैं, जो श्रीलंका में टी-20 सीरीज खेल रही है। लेकिन, इस सीरीज में खेल रहे तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को रैंकिंग में फायदा मिला, जो पहले टी-20 मैच में 22 रन देकर चार विकेट झटकने की बदौलत गेंदबाजों की सूची में 16वें स्थान पर पहुंच गए। लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल पहले मैच में किफायती रहे थे, उन्हें 10 पायदान का फायदा मिला, जिससे वह सूची में 21वें नंबर पर पहुंचने में सफल रहे।

क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने उतरेगी हाकी टीम

ओलिंपिक डायरी

टोक्यो, प्रेट्र : पिछले मैच में शानदार वापसी करने वाली भारतीय पुरुष हाकी टीम गुरुवार को यहां मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना की कड़ी चुनौती से पार पाकर टोक्यो ओलिंपिक के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह सुरक्षित करने की कोशिश करेगी।

भारत ने अभी तक तीन मैचों में दो जीत दर्ज की हैं और वह पूल-ए में दूसरे स्थान पर है। इस पूल में आस्ट्रेलिया ने अभी तक अपने तीनों मैच जीते हैं और वह शीर्ष पर है। अर्जेंटीना वर्तमान में विश्व में सातवीं रैंकिंग पर है। वह एक जीत, एक हार और एक ड्रा से चौथे स्थान पर है।

न्यूजीलैंड के खिलाफ संघर्षपूर्ण जीत के बाद भारतीयों को आस्ट्रेलिया के हाथों 1-7 की करारी हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम हालांकि स्पेन पर 3-0 की जीत से वापसी करने में सफल रही। इस जीत से टीम का मनोबल बढ़ा है।



मीराबाई चानू इंफाल स्थित अपने घर में स्वजन के साथ भोजन करती हुई। सौ. ट्विटर

सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहेंगे गोल्फर लाहिड़ी और माने : अनिर्बान लाहिड़ी और उदयन माने गुरुवार से यहां शुरू हो रही गोल्फ प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। दोनों ने कहा, वे यहां कासुमिगासेकी कंट्री क्लब में ठोस प्रदर्शन करके देश में खेल का चेहरा बदलना चाहते हैं। गोल्फ में 60 खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे और कोई कट लागू नहीं होगा। लाहिड़ी इस टूर्नामेंट में भारत के घरेलू सर्किट में शीर्ष गोल्फरों में शुमार एस चिकारंगप्पा को कैडी के रूप में लाए हैं। माने अपने नियमित कैडी रूपेश के साथ उतरे हैं।

जीत की लय को कायम रखना चाहेंगी मेरी कोम

टोक्यो : छह बार की विश्व चैंपियन भारतीय महिला दिग्गज मुक्केबाज एमसी मेरी कोम बुधवार को अंतिम-16 के मैच में कोलंबिया की इंग्रिट लोरेन वेलेंसिया की चुनौतियों का सामना करेंगी। वहीं, पुरुषों में +91 किग्रा में सतीश कुमार जमैका के रिकार्डो ब्राउन के खिलाफ अपना अंतिम-16 का मुकाबला खेलेंगे।

छाप छोड़ना चाहेंगे फवाद मिर्जा

टोक्यो : घुड़सवारी में भारत की उम्मीदें फवाद मिर्जा पर टिकी हैं, जिन्होंने पिछले एशियाई खेलों में रजत जीतने के बाद खेलों के इस महाकुंभ के लिए क्वालीफाई करके 20 साल बाद भारत की नुमाइंदगी पक्की की। वहीं, तैराकी में पुरुषों की 100 मीटर बटरफलाई में भारत की तरफ से साजन प्रकाश उतरेंगे।

दैनिक जागरण

व्यक्ति की मति ही उसकी नियति निर्धारित करती है

खतरे की घंटी सुने अमेरिका

भारत आए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अफगानिस्तान के ताजा हालात पर चिंता जताते हुए वहां साझा रणनीति की जो जरूरत जताई, उसकी पूर्ति कैसे होगी, यह भी उन्हें बताना चाहिए। अमेरिका को यह आभास होना चाहिए कि उसने अफगानिस्तान को एक तरह से अधर में छोड़ दिया है। जो मुट्ठी भर अमेरिकी सैनिक वहां बचे हैं, वे भी अगले माह के अंत तक लौट जाएंगे। अमेरिकी सेनाओं के इस तरह अफगानिस्तान छोड़ने से ही वहां हालात खराब होते जा रहे हैं और तालिबान बर्बरता के साथ मनमानी करने में लगा हुआ है। अमेरिका ने जैसे अफगानिस्तान को अधर में छोड़ा, वैसे ही वह इराक से भी अपनी सेनाएं बुलाने जा रहा है। उसने यही काम वियतनाम में भी किया था और कोरिया में भी। अमेरिका अफगानिस्तान में आतंकवाद का खात्मा करने के इरादे से आया था, लेकिन आज वह उसे एक तरह से उन तालिबान के हवाले करने जा रहा है, जो न केवल खुद आतंकियों जैसी हरकतें कर रहे हैं, बल्कि अलकायदा और ऐसे ही अन्य आतंकी संगठनों को संरक्षण भी दे रहे हैं। यदि अफगानिस्तान पर फिर से तालिबान का कब्जा होता है तो इसके लिए अमेरिका ही जवाबदेह होगा। भले ही अमेरिका यह कह रहा हो कि वह तालिबान पर हवाई हमले जारी रखेगा, लेकिन ये हमले तब कामयाब होंगे, जब अमेरिकी सैनिकों और उसके खुफिया तंत्र की अफगानिस्तान की जमीन पर मौजूदगी हो।

अमेरिका को यह पता होना चाहिए कि यदि तालिबान अफगानिस्तान पर हावी हो जाते हैं तो वहां ऐसी विदेशी ताकतों का वर्चस्व कायम हो सकता है, जो इस पूरे क्षेत्र को त्रस्त कर सकती हैं। इसका संकेत तालिबान नेताओं के चीन दौरे से मिलता है। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि चीन अफगानिस्तान में उस रिक्तता को भरने की फिराक में है, जो अमेरिका के वहां से निकलने से उपजी है। चीन ने तालिबान नेताओं को जिस तरह अपने यहां बुलाया, उससे यह भी स्पष्ट है कि वह उनका भरोसा जीतने और उनका सहयोग-समर्थन करने की कोशिश में है। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि इसमें पाकिस्तान की सक्रिय भूमिका होगी। यदि तालिबान के वर्चस्व वाला अफगानिस्तान चीन और पाकिस्तान का खुला मैदान बनता है तो यह भारत के साथ-साथ मध्य एशिया के देशों के लिए भी खतरे की घंटी होगी। अमेरिका को खतरे की इस घंटी को अभी से न केवल सुनना चाहिए, बल्कि ऐसे हरसंभव प्रयास भी करने चाहिए, जिससे अफगानिस्तान सभ्य समाज के लिए खतरा बने तालिबान की जकड़न में न फंसने पाए। यदि तालिबान अफगानिस्तान पर काबिज होते हैं तो इससे अमेरिका की साख को चोट पहुंचने के साथ उसकी विश्वसनीयता भी घटेगी।

हरियाणा में तीसरा मोर्चा

हरियाणा के पांच बार मुख्यमंत्री रह चुके इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) प्रमुख ओमप्रकाश चौटाला एक बार फिर तीसरे मोर्चे के गठन के प्रयास में लगे हैं। इसके लिए सरदार प्रकाश सिंह बादल, शरद पवार, ममता बनर्जी और मुलायम सिंह यादव आदि नेताओं से वह भेंट करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बसपा सुप्रीमो मायावती को भी चौटाला तीसरे मोर्चे से जोड़ना चाहते हैं। चौटाला भले ही तीसरे मोर्चे की गठन की बात कह रहे हों, लेकिन उस मोर्चे का हरियाणा में कोई प्रभाव पड़ेगा, ऐसी संभावनाएं दूर-दूर तक नहीं दिखतीं। कारण यह कि जिन दलों को एक छतरी के नीचे लाने की बात चौटाला कह रहे हैं, वे सब क्षेत्रीय दल हैं और अपने-अपने प्रदेशों तक ही सीमित हैं। चौटाला के अपने दल का हरियाणा में आधार अवश्य है, लेकिन उनको अन्य किसी दल को साथ लेने से कोई लाभ नहीं होगा, वह जो कुछ भी हरियाणा में हासिल करेंगे अपने जनाधार से ही कर पाएंगे।

यह भी स्मरण रहे कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल के शिरोमणि अकाली दल (शिअद) से पहले भी चौटाला के दल इनेलो का गठबंधन होता रहा है। इनेलो अपने प्रभाव क्षेत्र वाली एक दो सीटें शिअद को देकर बादल को अनुगृहीत करता था। इसका बड़ा कारण बादल और चौटाला परिवारों में मित्रता थी। स्पष्ट है कि चौटाला जिस तरह से शिअद को अनुगृहीत करते थे, उस तरह से बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी को तो कर नहीं सकते। यदि ऐसा करेंगे तो अपने लिए क्या रखेंगे। संभव है कि एक दो सीट मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी मांग ले, क्योंकि कभी उसके भी एक विधायक होते थे। बसपा से इनेलो का समझौता होता रहा है और टूटता रहा है। दोनों मिलकर भी कोई कमाल नहीं दिखा पाए। फिर बड़ा प्रश्न यह भी है कि कांग्रेस तीसरे मोर्चे में शामिल होगी या नहीं। होगी तो निश्चित रूप से वह हरियाणा में मुख्यमंत्री पद पर अपनी दावेदारी करेगी। यह चौटाला को स्वीकार नहीं होगा। यदि कांग्रेस नहीं शामिल होगी तो हरियाणा में पुराने दल और पुराने समीकरण ही रहेंगे। इसलिए तीसरे मोर्चे के गठन से हरियाणा की राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला।

मंदिरों पर सरकारों के अवैध कब्जे



विकास सारस्वत

केंद्र सरकार को चाहिए कि एक समावेशी मंदिर प्रबंधन कानून बना कर सभी मंदिरों को उनके संप्रदायों को वापस करे

हाल में विश्व हिंदू परिषद ने सरकार से हिंदू मठ और मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर हिंदू समाज को वापस करने की मांग की। विहिप के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने पूछा कि 'सरकार क्यों तय करे कि मंदिर का पुजारी कौन होगा और वहां पूजा कैसे होनी चाहिए?' यह भारतीय व्यवस्था में उत्पन्न विकृति का ही प्रमाण है कि शासन न तो सही मायने में पंथनिरपेक्ष है और न ही पंथसापेक्ष। अन्यथा ऐसा संभव नहीं था कि सरकारें अन्य मतों को छोड़ केवल हिंदू धार्मिक प्रतिष्ठानों को अपने कब्जे में लेने का साहस करतीं। 15 राज्यों में करीब चार लाख मंदिरों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष सरकारी नियंत्रण, संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा प्रदत्त उस मौलिक अधिकार का सीधा हनन है, जिसके तहत प्रत्येक समुदाय को अपनी धार्मिक संस्थाओं की स्थापना, प्रबंध और प्रशासन की स्वतंत्रता है। बाकी मतों को छोड़कर केवल हिंदू मंदिरों पर नियंत्रण अनुच्छेद 14 एवं 15 में दिए समानता के मूल अधिकार का भी अतिक्रमण है।

विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा मंदिर नियंत्रण हेतु प्रवर्तित कानून सामाजिक न्याय एवं कुप्रबंधन को बहाना बनाकर लाए गए, परंतु सरकारी नियंत्रण में मंदिरों की जमीनों पर अंधाधुंध कब्जे, बड़े पैमाने पर हुई मूर्ति एवं शिल्पों की चोरी और दान में आए चढ़ावे का दुरुपयोग दर्शाता है कि सरकारी नियंत्रण में कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार चरम पर है। श्रीपद्मनाभस्वामी मंदिर से लगभग दो सौ करोड़ रु मूल्य के सोने और हीरों की चोरी सुर्खियों में रही थी। तिरुपति के मुख्य पुजारी रमन्ना दीक्षितुलु ने आंध्र के बड़े नेताओं पर गर्भगृह से बेशकीमती हीरे-जवाहरात हड़पने का आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्हें हटा दिया गया था। तमिलनाडु में मात्र पांच वर्ष की अवधि में मंदिरों की लगभग 50,000 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जे की बात सामने आई। अव्यवस्था और भ्रष्टाचार के चलते यह कोई आश्चर्य नहीं कि मंदिरों की संपत्ति से हो रही आय नगण्य है। हिंदू धर्म आचार्य सभा के अनुसार तमिलनाडु में मंदिरों के पास कुल 5,00,000 एकड़ जमीन है और उससे होने वाली आय कम से कम एक हजार करोड़ रु प्रतिवर्ष होनी चाहिए, परंतु मात्र 70 करोड़ रु सालाना आय ही दिखाई जा रही है। मंदिरों की संपत्ति से अर्जित आय का दुरुपयोग भी चिंता का विषय है। महत्वपूर्ण बात यह है कि धर्म प्रचार, गौशाला, वेद पाठशाला चलाने जैसे प्रयोजनों के लिए मंदिरों के पास संसाधन ही नहीं बचते। कई जगह पुजारी और अर्चकों को मामूली वेतन मिल पाता है।

जहां तक मंदिरों के माध्यम से सामाजिक न्याय साधने की बात है तो दूसरे मतों के पूजास्थलों में भी कई समस्याएं देखने को मिलती हैं। मस्जिदों में महिलाओं के नमाज पढ़ने के अधिकार की मांग उठती रही है। दलित ईसाइयों द्वारा पादरियों की नियुक्ति में भेदभाव या फिर गिरजों में अलग बैठाने की शिकायतें आती रही हैं। इसके बावजूद किसी सरकार ने कभी किसी मस्जिद या चर्च को नियंत्रण में लेने की हिम्मत नहीं दिखाई। मंदिरों में दलितों के प्रवेश संबंधी शिकायतें बीते दिनों की बातें हो चुकी हैं।

मंदिरों के प्रति उपेक्षित रवैया 1925 के मद्रास रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडावमेंट एक्ट की देन है। मुस्लिम और ईसाई समुदायों के विरोध के बाद इसे मद्रास हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडावमेंट एक्ट में परिवर्तित कर हिंदू मठ और मंदिरों को नियंत्रण में ले लिया गया। यह एक्ट द्रविड़ कजगम का पूर्ववर्ती रूप जस्टिस पार्टी लाई थी, क्योंकि द्रविड़ आंदोलन ने चिदंबरम के मंदिर को तोप के गोले से उड़ाना अपनी मुहिम का उद्देश्य बताया था। स्वतंत्रता के बाद 1951 में मद्रास राज्य ने इसी नाम से एक और एक्ट पास कर दिया। उसी वर्ष मद्रास उच्च न्यायालय ने और फिर 1954 में सर्वोच्च न्यायालय की सात जजों की बेंच ने इस कानून के कई प्रविधानों को असंवैधानिक करार दिया था। इसी तरह रतीलाल बनाम स्टेट आफ बांबे में भी सर्वोच्च न्यायालय ने किसी कानून द्वारा धार्मिक संस्थाओं के नियंत्रण और हस्तक्षेप को अनुच्छेद 26(डी) का उल्लंघन बताया। न्यायालय ने माना कि धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन संप्रदायों का मौलिक अधिकार है और इसे कोई दूसरा कानून बनाकर छीना नहीं जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने ऐसे ही कई और निर्णय दिए हैं। बावजूद इसके कई राज्यों ने एचआरसीई एक्ट 1954 की तर्ज पर कानून बना लिए हैं और अब उत्तर भारत तक नित नए मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में लेने के प्रयास जारी हैं।



अवधेश राजपूत

मंदिरों के सरकारी नियंत्रण का एक परिणाम यह हुआ है कि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत ऐसे मंदिर 'राज्य' की परिभाषा में आ जाते हैं, क्योंकि इसके अनुसार राज्य द्वारा नियंत्रित या संचालित कोई भी संस्थान 'राज्य' ही माना जाता है। इससे इन मंदिरों के प्रबंधन से जुड़े पहलुओं, नौकरियों, रखरखाव आदि में गैर हिंदुओं या नास्तिकों के प्रतिभागी होने पर कोई रोक नहीं। सबरीमला मंदिर में भगवान अयप्पा की विशिष्टता और मूल चरित्र के विरुद्ध जाकर न्यायिक दखल की गुंजाइश भी इसी संवैधानिक जटिलता से उत्पन्न हुई थी।

हिंदू मठ-मंदिरों में सिर्फ गर्भगृह, मूर्ति या पूजा ही नहीं, बल्कि सभी क्रियाओं, कार्मिकों और प्रांगण की पवित्रता भी महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में श्रद्धा और संस्कृति के केंद्रों पर सरकारी नियंत्रण न सिर्फ इस क्षेत्र के महात्म्य को दूषित करता है, बल्कि पुजारियों तक की नियुक्ति को गैर धार्मिक क्रिया बताकर अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेता है। पुरी जगन्नाथ मंदिर में तो इस विकृति के अंतर्गत न्यायालय द्वारा सेवा और पूजा को भी धार्मिक के साथ-साथ लौकिक क्रिया बताया गया। सरकारों द्वारा मंदिरों को सार्वजनिक स्थल मानने की मानसिकता ने मंदिरों को स्मारक और संग्रहालयों की श्रेणी में ला दिया है। केंद्र सरकार को चाहिए कि एक समावेशी मंदिर प्रबंधन कानून बनाकर सभी मंदिरों को उनके मूल संप्रदायों को वापस करे। इससे सरकार का संविधान और पंथनिरपेक्षता अनुरूप आचरण भी बनेगा और हिंदुओं को बाकी मतों के समान अपने धार्मिक स्थलों के प्रबंधन का अधिकार भी मिलेगा। यदि किसी स्थिति में सरकार को किसी धर्मस्थल का नियंत्रण लेना भी पड़े तो वह तात्कालिक समस्या के निवारण के बाद संबंधित समाज को शीघ्र वापस मिलना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद चिदंबरम मंदिर को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने के बाद ऐसा वचन स्वयं तमिलनाडु सरकार ने दिया है।

(लेखक इंडिक अकादमी के सदस्य एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

दानिश सिद्दीकी की हत्या में छिपा संदेश

हाल में भारत के फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी की अफगानिस्तान में तालिबान ने हत्या कर दी। दानिश इस इस्लामी देश के पुनः तालिबानीकरण को अपने कैमरे में कैद करने अफगानिस्तान में थे। उनकी नृशंस हत्या इस्लाम के नाम पर जिहाद करने वाले दानवों के हाथों हुई। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले मुस्लिम समाज में व्याप्त विसंगति और विरोधाभास को रेखांकित किया। एक भारतीय चैनल से बात करते अफगान सैन्य अधिकारी ने बताया कि दानिश को गोली मारने के बाद तालिबान को जैसे ही पता चला कि वह भारतीय है, उन्होंने उसके शव पर वाहन चढ़ाकर उसका सिर कुचल दिया। विडंबना देखिए कि दानिश जिस मजहब का अनुयायी था, उसके पैरोकारों ने ही इस्लाम के नाम पर क्रूरता के साथ उसकी हत्या की। दानिश की निर्मम हत्या के बाद उनकी जीवनी, विचार और उनके पेशेवर काम पर चर्चा होना स्वाभाविक था। दानिश ने भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान हिंदुओं की जलती चिताओं की तस्वीरें खींची थीं, जिसे लेकर अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थानों सहित देशविरोधी शक्तियों ने वैश्विक अभियान चलाया और विपक्षी दल मोदी-विरोध के नाम पर दुनियाभर में देश की छवि पर कालिख पोतने में सहभागी बने। जब यह सब इंटरनेट मीडिया पर पुनः वायरल हुआ, तब तालिबान ने दानिश की हत्या पर खेद व्यक्त कर दिया। ऐसा करके तालिबान ने दुनिया को जो संदेश दिया, वह उतना ही स्पष्ट है, जितना उनका दानिश की मौत पर पछतावा।

आखिर तालिबान ने दानिश की राष्ट्रीयता जानने पर उसका शव गाड़ी से क्यों रौंदा? यह ठीक है कि दानिश एक मुस्लिम था, परंतु शायद तालिबान के लिए अधिक महत्वपूर्ण यह था कि वह 'काफिर' भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा था। भारतीय उपमहाद्वीप में मुसलमानों का बड़ा वर्ग जहां स्वयं को अंतरराष्ट्रीय मिल्लत का हिस्सा मानता है तो दूसरी ओर पश्चिम एशिया और अरब देशों के मुसलमान उन्हें दोयम दर्जे का मुस्लिम मानते हैं। यह अकाट्य तथ्य है। भारतीय उपमहाद्वीप में आज जितने भी मुस्लिम हैं, उनमें 90 प्रतिशत से अधिक मुसलमानों के पूर्वज हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध मत के अनुयायी थे, जिनका वर्तमान अरबी-फारसी संस्कृति से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। वैसे भी मिल्लत की कल्पना ही अव्यावहारिक है। यदि इस्लाम के नाम पर मुसलमान इकट्ठा ही होते तो न दुनिया के 56 मुस्लिम बहुल देश या फिर घोषित इस्लामी गणराज्य अलग-अलग बंटते और न ही शिया-सुन्नी संप्रदाय केंद्रित मुस्लिमों या संबंधित देशों के बीच मजहबी संघर्ष होता।



बलबीर पुंज

तालिबान के लिए अधिक महत्वपूर्ण यह था कि दानिश 'काफिर' भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा था



तालिबान की बर्बरता का शिकार दानिश। फाइल

भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश मुसलमान स्वयं को पश्चिम एशिया की अरबी-फारसी संस्कृति से जोड़कर विदेशी आक्रांताओं कासिम, गोरी, गजनी, बाबर, अब्दाली आदि में अपना नायक इसलिए खोजते है, क्योंकि वे सभी 'गजवा-ए-हिंद' के सूत्रधार थे। पाकिस्तान ने तो अपनी मिसाइलों और युद्धपोत का नामकरण क्रमशः बाबर, गोरी, गजनी, अब्दाली और टीपू सुल्तान आदि के नाम पर किया। भले ही अरब से भारत पर मजहबी आक्रमण के पश्चात कालांतर में भारतीय उपमहाद्वीप की वैदिक सांस्कृतिक सीमा सिकुड़ती गई हो और लोगों ने मजहबी तलवार के भय से इस्लाम स्वीकार कर लिया हो, किंतु उनकी मूल जड़ों में सनातन भारत के हिंदू-बौद्ध बहुलतावादी और पंथनिरपेक्षी रूपी जीवंत मूल्य आज भी शाश्वत हैं। इसी भारतीय पहचान से तालिबान और उसके वैश्विक मानसबंधु घृणा करते हैं। विश्व के इस भूखंड में पाकिस्तान उस विकृत चिंतन का सबसे बड़ा मूर्त रूप है। पाकिस्तान का वैचारिक अधिष्ठान जन्म से काफिर-कुफ्र की अवधारणा से प्रेरित है। इसी कारण 74 वर्षों से पाकिस्तान स्वयं को इस भू-भाग में उद्गमित और विकसित हिंदू-बौद्ध सांस्कृतिक जड़ों से काटने (इस्लाम-पूर्व सभ्यतागत प्रतीकों को जमींदोज करने सहित) और अरब-पश्चिम एशियाई संस्कृति से जोड़ने का असफल प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान की आधिकारिक राष्ट्रीय भाषा उर्दू और अंग्रेजी है, किंतु वहां केवल सात प्रतिशत लोग ही उर्दू बोलते हैं और लगभग आधी आबादी पंजाबी।

पाकिस्तान की तथाकथित पंथनिरपेक्ष छवि बनाने हेतु जिन्ना ने हिंदू शायर जगन्नाथ आजाद के एक उर्दू गीत को राष्ट्रगान बनाया, लेकिन उसका विरोध हुआ। परिणामस्वरूप उसे प्रतिबंधित कर एक फारसी गाने को राष्ट्रगान बना दिया, जिसमें उर्दू के नाम पर केवल 'का' शब्द का उपयोग हुआ है। ऐसा इसलिए, ताकि पाकिस्तान खंडित भारत की वैदिक सनातन संस्कृति से स्वयं को अलग कर सके। इसी मानसिकता से ग्रस्त पाकिस्तान ने जितने भवन निर्मित किए, जिनमें लाहौर स्थित मीनार-ए-पाकिस्तान, ग्रैंड जामिया मस्जिद, इस्लामाबाद की फैजल मस्जिद, मजलिस-ए-शूरा (संसद) और सुप्रीम कोर्ट आदि शामिल हैं, उनमें से किसी की वास्तुकला में न केवल भारतीय संस्कृति, अपितु मुगलकालीन ताजमहल, लाल किले जैसी बनावट की कोई झलक तक नहीं है। उन पर अरब और पश्चिम एशियाई देशों का अधिक प्रभाव है। इसी मानसिकता से प्रेरित होकर 12वीं शताब्दी तक भारतीय संस्कृति का अंग रहे अफगानिस्तान में भी हिंदू-बौद्ध संस्कृति के प्रतीक-चिन्हों को मिटा दिया गया। अपने इसी चिंतन के कारण पाकिस्तान और तालिबान मिलकर अब अफगानिस्तान में उन शैक्षणिक संस्थानों, इमारतों और बांध परियोजनाओं को तबाह करना चाह रहे हैं, जिनके निर्माण में 'काफिर' भारत की मुख्य भूमिका है।

जब दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया में दानिश का अंतिम संस्कार हुआ, तब वहां उपस्थित लोगों ने एक बार भी तालिबान मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाया। क्यों? क्या यह इस भू-भाग में रह रहे मुस्लिम समाज के एक वर्ग में विसंगति और विरोधाभास को प्रतिबिंबित नहीं करता?

(लेखक राज्यसभा के पूर्व सदस्य और स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

घमंड का दंड

घमंड एक नकारात्मक मानवीय स्वभाव है। वैसे तो व्यक्ति के घमंडी होने के कई कारण हैं, लेकिन वर्तमान में धन-संपदा और भौतिकता के प्रदर्शन का घमंड लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। विशेषकर अचानक से धनी बने लोगों का व्यवहार उनके दंभ को प्रायः उजागर ही कर देता है। दरअसल जब व्यक्ति के पास आवश्यकता से अधिक धन आ जाता है तो वह यही सोचने लगता है कि उसके पास सब कुछ है। वह दूसरों को अपने से हीन समझने लगता है। यदि वह व्यक्ति अज्ञानी और अशिक्षित हो तो यह प्रवृत्ति अधिक मुखर होकर दिखती है। अगर उस व्यक्ति ने अनैतिक कार्यों से धन अर्जन किया हो तो उसके घमंडी होने की आशंका और प्रबल हो जाती है। ऐसे व्यक्ति का सर्वनाश निश्चित होता है। अतः व्यक्ति को घमंडी होने से बचना चाहिए।

इस संबंध में महर्षि दयानंद जी ने कहा कि अहंकारी मनुष्य का पतन निश्चित है। जिसे घमंड करने की आदत होती है वह शायद ही कभी दूसरों के बारे में कोई अच्छी बात कहे। अगर कोई धन के प्रति घमंड करता है तो उसके बुरे दिनों में कोई भी उसकी सहायता करने से संकोच करता है। घमंड का एक और रूप होता है, जिसे यूनानी भाषा में ईब्रिस कहते हैं। यूनानी भाषा के विद्वान विलियम बार्कले के अनुसार ईब्रिस से आशय ऐसे घमंड से है, जिसमें क्रूरता भरी हुई हो। यह घमंड का ऐसा स्वरूप है, जिसमें लोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए बेरहमी से उनकी भावनाओं को रौंदते हैं। ऐसे सोच के लोगों में क्रूरता आ ही जाती है। इसके बाद उनका विनाश तय माना जाता है, क्योंकि धन या बल से सब कुछ खरीदा जा सकता है, परंतु मान-सम्मान और चरित्र नहीं। महात्मा गांधी ने भी कहा है कि 'ऐसा मानिए कि जो हम करते हैं, वह दूसरे भी कर सकते हैं। यदि हम ऐसा न मानें तो अहंकारी ठहराए जाएंगे।' स्मरण रहे कि इतिहास ऐसे प्रमाणों से भरा है, जहां बड़े से बड़े विद्वान और शूरवीरों को भी अपने घमंड का दंड भुगतना पड़ा था।

नृपेंद्र अभिषेक नृप

जल संरक्षण को बनाएं अभियान

देवेंद्रराज सुथार

जलवायु परिवर्तन और मौसम की विषम घटनाओं के चलते भी पानी की मात्रा और गुणवत्ता लगातार घटती जा रही है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में जनभागीदारी से जल संरक्षण की बात कही है। यह बहुत आवश्यक भी है, क्योंकि नदियों का देश होने के बावजूद आज भारत के तमाम इलाके शुद्ध पेयजल की किल्लत से जूझ रहे हैं। पर्यावरण असंतुलन और जल संसाधनों के क्षय के कारण पेयजल स्रोतों की संख्या घट रही है। वनों के विनाश और हिमनदों के सिकुड़ने आदि से जल की मात्रा और गुणवत्ता घटने लगी है। इस अंधी दौड़ में हम यह भूल रहे हैं कि जैसे-जैसे पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन समाप्त होते जा रहे हैं, वैसे-वैसे पर्यावरण असंतुलन बढ़ता जा रहा है।

जल एक प्राकृतिक और असीमित संसाधन अवश्य है, परंतु पेयजल की मात्रा सीमित है। पृथ्वी की सतह का 71 प्रतिशत जल से ढका हुआ है, जिसका 97 प्रतिशत भाग लवणीय जल के रूप में तथा शेष तीन प्रतिशत भाग अलवणीय जल के रूप में विद्यमान है। इस तीन प्रतिशत का का अधिकांश भाग भी ग्लेशियरों में बर्फ के रूप में जमा है। इसी कारण पीने योग्य पानी की मात्रा अत्याधिक सीमित है। भारतीय संदर्भ में बात करें तो यहां विश्व जनसंख्या का 17 से 18 प्रतिशत भाग रहता है तथा जल संसाधनों की मात्रा केवल 4 प्रतिशत है। उसमें भी अधिकांश भाग मानव के अविवेकपूर्ण क्रियाकलापों के कारण सीमित होता जा रहा है। भारत में करीब 9.14 करोड़ बच्चे गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं। आबादी और जरूरतों के बढ़ने के साथ-साथ पानी की मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि संसाधन कम होते जा रहे हैं। तेजी से बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, पानी की बर्बादी और कुप्रबंधन के अलावा जलवायु परिवर्तन और मौसम की चरम घटनाओं के चलते भी पानी की मात्रा और गुणवत्ता गिरती जा रही है। इससे जल संकट और उससे उपजा तनाव भी बढ़ता जा रहा है। यूनिसेफ के अनुसार वर्ष 2040 तक दुनिया भर में हर चार में से एक बच्चा उन क्षेत्रों में रहने को मजबूर होगा जो जल संकट के कारण उच्च तनाव में होंगे।

इसलिए आज जल संरक्षण की दिशा में प्रत्येक मानव को आगे आना होगा। जल संरक्षण एवं विकास वर्षा की बूंद का पृथ्वी पर गिरने के साथ ही करना चाहिए। इसके लिए नदी मार्गों पर बांधों एवं जलाशयों का निर्माण करना होगा ताकि भविष्य में हमें पीने को शुद्ध पेयजल, सिंचाई, मत्स्य पालन एवं औद्योगिक कार्यों हेतु जल सुगमता से उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही बाढ़ से मुक्ति मिले एवं कम वर्षा, निचले जल स्तर, सूखा ग्रस्त एवं अकालग्रस्त क्षेत्रों में नहरों आदि में जल की पूर्ति हो सके। साथ ही जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सीमित करने के प्रयास भी करने होंगे। इस समस्या को दूर करने के लिए न केवल हमें प्रयास करने हैं, बल्कि स्थिति को बिगड़ने से भी रोकना है और यह तभी हो सकता है जब हम सब मिलकर इस दिशा में काम करें।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

दूर होने चाहिए पुराने अवरोध

'साझा चिंता और तात्कालिक चुनौती' शीर्षक से लिखे आलेख में श्रीराम चौलिया ने भारत-अमेरिका को एक स्वाभाविक साझेदार बताते हुए बीते कुछ वर्षों के दौरान उनके संबंधों में उत्तरोत्तर सुधार के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डाला। इसमें कोई संदेह नहीं कि चाहे कारोबारी परिदृश्य हो या फिर हिंद-प्रशांत जैसा भू-राजनीतिक अखाड़ा या अंतरराष्ट्रीय महत्व का कोई और महत्वपूर्ण मंच, उसमें इन दोनों देशों के साझा हित जुड़े हुए हैं। जहां अमेरिका विश्व की एक स्थापित महाशक्ति है, वहीं भारत नए आकार लेते वैश्विक ढांचे के अनुक्रम में स्वयं को ऊपरी पायदान पर स्थापित करने की प्रक्रिया में लगा है। मोदी सरकार की सक्रिय एवं सार्थक विदेश नीति के कारण एक बड़ी हद तक यह संभव भी होता दिख रहा है। लेखक ने साझा हितों के ऐसे कई बिंदुओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराया, परंतु दोनों देशों के बीच मतभेद के बिंदुओं पर वह मौन रहे। विशेषकर बौद्धिक संपदा से लेकर द्विपक्षीय व्यापार के मोर्चे पर कायम गतिरोध की चर्चा तक नहीं की। इतना ही नहीं बाइडन प्रशासन के दौर में भारत को लेकर अमेरिकी आग्रहों का भी उल्लेख नहीं किया। आखिर इन पहलुओं पर स्पष्टता के अभाव में भारत-अमेरिकी साझेदारी अपेक्षित रूप से कैसे गति पकड़ेगी। निःसंदेह अभी अफगानिस्तान दोनों देशों की एक साझा चिंता है, लेकिन अतीत की बाधाओं को भला कैसे भुलाया जा सकता है।

राहुल शर्मा, फरीदाबाद

उचित नहीं संसद की कार्यवाही में बाधा

'खुद को कमजोर साबित करता विपक्ष' आलेख में मानसून सत्र को चलने न देने की विपक्ष की मंशा पर लेखक राजीव सचान ने एकदम सही प्रकाश डाला है। सदन में अध्यक्ष कुर्सी पर बैठते हैं, कार्यवाही शुरू होती है, सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी कुर्सियों पर कुछ देर टेक लगाते हैं। इसके बाद जल्द ही विपक्ष को याद आ जाता है कि सदन नहीं चलने देना है। हंगामा शुरू। सदन की कार्यवाही रोकनी पड़ती है। प्रश्नोत्तर काल में जनता की समस्या से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उनके उत्तर विभागीय मंत्रियों से मांगे जाते हैं, वह भी आधा अधूरा रह जाता है। लोकसभा के चुनाव अभी दूर हैं। पेगासस जासूसी मामला और तीन नए कृषि कानून को मुद्दा बनाकर विपक्ष क्या 2024 के चुनावों की तैयारी कर रहा है या संसद के दोनों सदनों को ठप कर राज्य विधानसभा के चुनावों में जीतने की जमीन तैयार कर रहा है। सांसदों को जनता चुनकर भेजती है। क्या जरूरी नहीं कि वे संसद चलने दें, देश की समस्याओं पर अपने विचार रखें, कार्यवाही के बाद सदन से बाहर आकर संसद के बाहर गांधीजी की मूर्ति के सामने धरना-प्रदर्शन कुछ समय तक करें। जब देश आजाद हुआ था तो सांसदों में भी उत्साह हुआ करता था। वे अपनी पूरी तैयारी के साथ सदन में आते थे। अपने विचार रखता विपक्ष सरकार को कठघरे में खड़ा करता और सत्तापक्ष सफाई पेश करता। विधेयकों पर वाचन एवं वोटिंग होती थी। अब अक्सर सांसद सदन से गायब, ऊंघते या हंगामा करते नजर आते हैं। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है।

डा. शोभा भारद्वाज, दिल्ली

लिंगायत वोट बैंक की चुंबकीय शक्ति

कर्नाटक के लिंगायत वोट पर चित भी मेरी, पट भी मेरी का दांव खेलते हुए भाजपा आलाकमान राज्य विधायक दल के सुर में सुर मिलाते हुए बसवराज एस बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाने में सफल हो गया। येदियुरप्पा के शासन की दूसरी वर्षगांठ पर भाजपा ने राज्य में उपजे अंतर्विरोध को शांत करने की जो राजनीतिक चाल चली है, उसका दूरगामी परिणाम तो भविष्य में ही पता चलेगा। शह-मात के इस राजनीतिक खेल में भाजपा को दिख गया है कि क्षत्रपों से अपेक्षा एवं दूसरे गुट की उपेक्षा, देश-प्रदेश की राजनीति में उफान ला सकती है। कर्नाटक में कांग्रेस या जद (एस) के पास लिंगायत वोट बैंक बटोरने की चुंबकीय शक्ति वाला नेता नहीं होना, उन्हें विपक्ष में रहने को विवश कर रहा है। लिंगायत मठों का समर्थन बनाए रखना एवं बढ़ाना भाजपा क्षत्रपों को कर्नाटक की राजनीति में तुरुप के इक्के की तरह काम आता रहेगा। इससे भाजपा की सियासी बढ़त कायम रहने की उम्मीद है।

युगल किशोर शर्मा, फरीदाबाद

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय: 011-43166300, नोएडा कार्यालय: 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।

104 राष्ट्रीय उद्यान तथा 566 वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना की जा चुकी थी वर्ष 2020 तक भारत में।

नई शिक्षा नीति का एक वर्ष

कक्षा संग आनलाइन शिक्षा को मिले महत्ता



आचार्य राघवेंद्र प्रसाद तिवारी
कुलपति, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा

शिक्षा ऐसा विषय है, जिसमें रातोंरात परिवर्तन होना मुश्किल है, पर यह भी सच है कि अगर लागू करने वाले प्राधिकारियों में इच्छाशक्ति हो तो बदलाव की राह पर चल पड़ना बहुत कठिन भी नहीं होता। कहा जा सकता है कि बीते बारह महीनों में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के हिसाब से देश की शिक्षा में कई परिवर्तनों की आधारशिला रखी गई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि बदलाव की यह बयार आने वाले दिनों में भारत में उस सोच को रूपायित करेगी, जिसकी कल्पना नई शिक्षा नीति में की गई है



अवधेश राजपूत

आज ही के दिन एक साल पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश की नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 एक दस्तावेज मात्र नहीं है, अपितु शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता का परिचायक भी है। निःसंदेह यह एक विद्यार्थी केंद्रित नीति है, जो इस बात की पुष्टि करती है कि विद्यार्थी वर्ग ही शिक्षा व्यवस्था के प्रमुख हितधारक हैं तथा शिक्षकों का नैतिक दायित्व है कि वे विद्यार्थियों के सपनों और आकांक्षाओं के अनुरूप उन्हें शिक्षित एवं प्रशिक्षित करें। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सीखने के बहु-आयामी दृष्टिकोणों को बढ़ावा दिया गया है, इसमें औपचारिक, आनलाइन तथा दूरस्थ अथवा वर्चुअल माध्यम द्वारा बहु-विषयक, व्यावसायिक एवं कौशल-विकास को पोषित करने वाले पाठ्यक्रमों के निर्माण की बात कही गई है। इसके क्रियान्वयन के उपरांत शिक्षा जगत में विद्यार्थियों की पहुंच में वृद्धि, गुणवत्ता और रुचियां सुनिश्चित हो सकेंगी। विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम रुचिकर होगा एवं शिक्षण प्रणाली लोकतांत्रिक बन सकेगी। शिक्षा में तकनीक के उपयोग एवं एकीकरण द्वारा विविध शिक्षण मार्गों को अपनाने से ही इसका सफल क्रियान्वयन संभव है।

दरअसल राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षण में व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों द्वारा विद्यार्थियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करती है। औपचारिक शिक्षण पद्धति में यदि शिक्षक शिक्षा को व्यक्तिगत एवं सामूहिक दृष्टि से अधिक सक्रिय बनाना चाहे तब भी उसके पास पर्याप्त समय नहीं होता है। परिणामस्वरूप विद्यार्थियों में वांछित स्तर, चिंतन क्षमता, वैश्विक दक्षता और रचनात्मकता को प्रोत्साहन नहीं मिलता, जिससे कौशलहीनता तथा बेरोजगारी को बढ़ावा मिलता है। अतः हमें औपचारिक शिक्षा के पूरक एवं सहयोगी विकल्पों पर विचार करना होगा। इस संदर्भ में मिश्रित शिक्षा प्रणाली एक अनुकूल एवं सहयोगी विकल्प हो सकती है। मिश्रित शिक्षा प्रणाली में आनलाइन और क्लासरूम शिक्षा के सर्वोत्तम पक्षों को संयोजित किया जाता है, जिससे छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सुगमता होती है। मिश्रित शिक्षा प्रणाली एक निर्देशात्मक पद्धति है, जिसमें शिक्षा को आनंदप्रद बनाने वाली गतिविधियां सम्मिलित होती हैं। यह औपचारिक तथा आनलाइन माध्यम का मात्र भौतिक मिश्रण नहीं, अपितु दोनों का सुनियोजित संयोजन है। हालांकि इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षक और छात्र दोनों भौतिक रूप से एक ही मंच पर हों। फ्लिप्ड क्लासरूम इसी प्रकार की तकनीक है, जिसमें क्लासरूम में प्रौद्योगिकी द्वारा पारंपरिक औपचारिक शिक्षा की प्रभावशीलता को सुदृढ़ता मिलती है। इसमें विडियो व्याख्यान, पाडकास्ट, रिकार्डिंग तथा आलेख आदि शैक्षिक सामग्री विद्यार्थियों को पूर्व में ही उपलब्ध कराई जाती हैं, जिसके फलस्वरूप कक्षाओं में छात्रों को गतिविधि आधारित शिक्षण एवं विमर्श के अवसर तथा सक्रिय भागीदारी के लिए पर्याप्त समय मिलता है।

मिश्रित शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत शिक्षकों की वर्तमान भूमिका के साथ-साथ उन्हें परामर्श और प्रशिक्षण रूपी अतिरिक्त भूमिकाएं भी निभानी होती हैं। इसके लिए अधिक शिक्षकों की आवश्यकता होगी। इस प्रणाली के अंतर्गत शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षकों को अधिक प्रशिक्षित होने की भी आवश्यकता होगी। परंपरागत क्लासरूम शिक्षण एकालाप प्रणाली है, जो विद्यार्थियों को केवल सूचना संग्रही बनाती है। मिश्रित शिक्षा प्रणाली छात्र केंद्रित है, जिसमें चिंतनशील, विचार-मंथन, अभ्यास, अवधारणा, रचनात्मक प्रस्तुति, वास्तविक जगत से संपर्क, केस स्टडी एवं व्यक्तिगत तथा समूह में प्राप्त ज्ञान को आत्मसात करने से छात्रों में तार्किक क्षमता का विकास होता है। यह प्रणाली विद्यार्थियों को वाद-विवाद तथा विवादों के सहज समाधान के लिए व्यापक अवसर प्रदान करती है। इस प्रक्रिया में शिक्षक अप्रासंगिक नहीं होंगे, अपितु यह शिक्षकों और विद्यार्थियों को समान रूप से अधिक संतुष्टि प्रदान करने वाली होगी। इसे अपनाकर शिक्षक अतिरिक्त दायित्व बोध के साथ कक्षा में अधिक प्रभावशाली होंगे।

मिश्रित शिक्षा में प्रयोग संभव हैं, क्योंकि आभासी प्रयोगशालाओं के द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों में भी प्रयोग कराए जा सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय की फोसी परियोजना का उद्देश्य सूचना और प्रौद्योगिकी के माध्यम से अकादमिक और शोध के क्षेत्रों में शैक्षणिक उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देना है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक विद्यार्थियों के ध्यान स्तर, सीखने के पसंदीदा ढंग, गति तथा सीखने के स्तर आदि को जानने में सहयोगी सिद्ध होगी। मुक्त शिक्षण संसाधन, ई-पीजी पाठशाला, स्वयंप्रभा, स्नातक विषयों में ई-सामग्री, यूजीसी यूट्यूब चैनल, एक राष्ट्र एक डिजिटल मंच परियोजना आदि से ई-शिक्षा संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

वस्तुतः मिश्रित शिक्षा प्रणाली 21वीं सदी के विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित हो सकती है, परंतु डिजिटल डिवाइड एवं इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से इसको एकाएक लागू नहीं किया जा सकता। अतः विश्वविद्यालयों को इस प्रणाली को लागू करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, विश्वविद्यालयों/शिक्षकों को परंपरागत तथा आनलाइन शिक्षा के मिश्रण के अनुपात निर्धारित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। विश्वविद्यालयों द्वारा इस प्रणाली को आत्मसात करने से पूर्व आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके कार्यान्वयन में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि इससे औपचारिक शिक्षण उपेक्षित न हो। कुल मिलाकर देश के युवाओं में वैश्विक क्षमता विकसित कर उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रासंगिक बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए हमें स्वयं को तैयार करना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रथम वर्षगांठ पर हमारा यही संकल्प हो।

भारतीय भाषाओं के मोर्चे पर सकारात्मक पहल



उमेश चतुर्वेदी
वरिष्ठ पत्रकार

शिक्षा ऐसा विषय है, जिसमें रातोंरात परिवर्तन होना मुश्किल है, लेकिन यह भी सच है कि अगर लागू करने वाले प्राधिकारियों में इच्छा शक्ति हो तो बदलाव की डगर पर चल पड़ना बहुत कठिन भी नहीं होता। कहा जा सकता है कि बीते बारह महीनों में नई शिक्षा नीति के हिसाब से कई परिवर्तनों की आधारशिला रखी गई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि बदलाव की यह बयार आने वाले दिनों में भारत में उस सोच को रूपायित करेगी, जिसकी कल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में शिद्दत से भारतीय भाषाओं की अहमियत को स्वीकार किया गया है। भारतीय शिक्षण और सोच के स्तर पर मातृभाषाओं की कमी को न सिर्फ गहराई से महसूस किया गया, बल्कि भाषा की सामर्थ्य को समझते हुए भारत को अपनी जुबान और इस बहाने अपने सोच देने की जो कवायद शुरू की गई, उसके हिसाब से बीते बारह महीनों में कई कदम उठाए गए हैं।

नई शिक्षा नीति के तहत अब भारत में इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी समेत कई अन्य भारतीय भाषाओं में शुरू करने की तैयारी हो चुकी है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी एआइसीटीई ने हिंदी, बांग्ला, मराठी, मलयालम समेत 11 भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराए जाने की मंजूरी दे दी है। इसी तरह मेडिकल में दाखिले के लिए होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट भी 13 भारतीय भाषाओं में कराए जाने का फैसला लिया गया है।

नई शिक्षा नीति में अनुसंधान और उच्च शिक्षा में भी भारतीय भाषाओं पर जोर देने की बात की गई है। लिहाजा इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पिछले एक साल में कई विश्वविद्यालयों ने कदम उठाए हैं। कई विश्वविद्यालयों ने पाठ्यक्रमों के भाषायी विस्तार के लिए अनुवाद के लिए अलग से विभाग बनाने शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ही कई विश्वविद्यालयों ने भले ही पढ़ाई का माध्यम मातृभाषाओं में शुरू नहीं किया है, लेकिन छात्रों को परीक्षाओं में दो भाषाओं में उत्तर लिखने की अनुमति दे दी है। छात्र जिस भाषा में सहज है, वह परीक्षा में उसी भाषा में जवाब लिख सकता है। इसी तरह से कई विश्वविद्यालयों ने अपने स्तर पर ऐसे कई पाठ्यक्रम विकसित कर लिए हैं, जिनकी पढ़ाई दो या दो से अधिक भाषाओं के माध्यम से हो सकती है। भोपाल के अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय संभवतः देश का पहला विश्वविद्यालय है, जिसने हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू भी कर दी है।

नई शिक्षा नीति में भारतीयता की अवधारणा के साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा पर भी जोर दिया गया है। इस लिहाज से भी पाठ्यक्रम बनने शुरू हो गए हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और सयाजीराव विश्वविद्यालय, बड़ौदा ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। यहां भारतीय ज्ञान परंपरा की पढ़ाई भी शुरू हो गई है। देर-सवेर इसका फल मिलेगा।

हालांकि भाषायी शिक्षण में हीला-हवाली करने की भी जानकारियां हैं। एनसीईआरटी जैसे संस्थानों से ऐसी भी खबरें छन कर आई हैं, जहां नई शिक्षा नीति के हिसाब से पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में सक्रिय कोशिश के बजाय ढुलमुल रणनीति अख्तियार की जा रही है। कुछ संस्थान अपनी स्वायत्त हैसियत का दुरुपयोग करते हुए इस नीति को लागू करने के बजाय ऐसी रणनीति बना रखे हैं, जिसमें काम होता हुआ नजर तो आए, लेकिन वास्तव में लागू न हो पाए। जाहिर है कि नौकरशाही और मानसिकता की यह बाधा बनी रहेगी, लेकिन यह भी सच है कि अगर इन पर काबू नहीं पाया गया, शैक्षिक तंत्र में विचारधारा और दूसरे नाम पर जमी ताकतों को मर्यादित नहीं किया गया तो नई शिक्षा नीति का पूरा फायदा नहीं उठाया जा सकता। इसकी तरफ सरकारों को ध्यान देना ही होगा।

खरी-खरी

पति, पत्नी और जासूसी

सुधीर कुमार चौधरी

सामान्यतः उम्र के अलावा पत्नी का सबकुछ सदैव परिवर्तनशील होता है। सोच, समझ, रवैया, दृष्टिकोण, प्रेम का तरीका...आदि सबकुछ। उसके मिजाज में समुद्र की लहरों की भांति सतत उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। इन ज्वार-भाटों में गृहस्थी की नैया डगमगाती रहती है। श्रीमती जी की आंखें इन दिनों सूक्ष्मदर्शी में तब्दील हो गई हैं। वो हमारे मोबाइल को भिन्न-भिन्न कोणों से घूरती रहती हैं। कभी हमारी नजर बचाकर, मोबाइल को उठाकर उसे अनलाक करने का प्रयास करती हैं तो कभी हमें उस पर व्यस्त देख बिजली की गति से स्क्रीन में झांकने का प्रयास करती हैं।

उस दिन वो अपने मोबाइल पर अमेजन का चप्पा-चप्पा छान रही थीं। हमने पूछा, इतनी तल्लीनता से क्या सर्च कर रही हो। आखिर क्या आर्डर करना है? उन्होंने बगैर निगाहें उठाए उत्तर दिया-पेगासस स्पायवेयर आर्डर करना है। खोज-खोज कर थक गई, लेकिन कहीं मिल नहीं रहा है। जरा आप ही खोज दीजिए न। हमने उन्हें समझाने का प्रयास करते हुए कहा-इसे केवल सरकार ही आर्डर कर सकती है, लेकिन तुम्हें इसकी अवश्यकता क्या है। क्या किटी पार्टी वाली सहेलियों के फोन टेप करना है? उन्होंने कहा-हमें आपके फोन की जासूसी करना है। हमने कहा-अरे फोन की जासूसी तो सरकार करती है। उन्होंने तपाक से उत्तर दिया-आखिर इस घर में तो हमारी ही सरकार है। हम आपके मोबाइल की खबर क्यों नहीं रख सकते? हमने कहा-क्यों बेवजह घर को संसद बनाने पर तुली हो। हमारी जासूसी क्यों करना चाहती हो? उन्होंने कहा-जिस तरह देश की सुरक्षा के लिए जासूसी करना सरकार का धर्म है, उसी तरह गृहस्थी की सुरक्षा का दायित्व हमारा है। इसमें विपक्ष की भांति टांग अड़ाने वाले आप कौन होते हो?

यह सुन हमने उन्हें धमकाने के अंदाज में कहा-घर में हंगामा क्या अच्छा लगेगा? हमारी चौधरी-भभकी को खारिज करते हुए कहा-गले तक भरे हुए पेट वाले ही हंगामा करते हैं। घर में जब खाना नहीं बनेगा तो आपकी आवाज निकलनी बंद हो जाएगी। संभव है पेगासस का कोई तोड़ निकल आए, पर यह पत्नी नामक स्पायवेयर तो बिल्कुल ही अभेद्य है।

ट्वीट-ट्वीट

अपने ही कांग्रेस की लुटिया डुबोते हैं। आपसी खींचतान के चलते पार्टी ने मध्य प्रदेश की सत्ता गंवाई। उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब हर जगह खेमेबाजी चरम पर है। अब छत्तीसगढ़ में झगड़ा सामने आ गया है। राहुल गांधी स्थिति को संभाल लेंगे? मीनाक्षी जोशी@IMinakshiJoshi

चीन द्वारा तालिबान के एक प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी ने भारत के लिए चुनौतियों को नए सिरे से रेखांकित किया है, जो अफगानिस्तान में अपनी कूटनीतिक सक्रियता को तेज करना चाहता है। भारत का एक मुख्य प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान पहले से ही इस कहानी में अहम किरदार बना हुआ है वहीं अब दूसरा प्रतिद्वंद्वी चीन भी अफगानिस्तान में अपनी पैठ बढ़ा रहा है। माइकल कुगेलमैन@MichaelKugelman



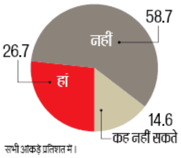
नोटबंदी के विपरीत रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल मुद्रा की पहल नकदी पर निर्भरता घटाने की राह प्रशस्त करने के साथ ही देश में क्रिप्टोकरेंसी के अभाव को भी दूर करेगी। वैसे भी इस मामले में हम चीन से कई महीने पीछे हैं, लेकिन अच्छी बात है कि आखिर आरबीआइ ने इस दिशा में कदम तो बढ़ाए। मिलिंद देवरा@milinddeora

जगन्नाथ पुरी देश का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां आप सीधे नल का पानी पी सकते हैं। यह शुद्ध जल 24 घंटे उपलब्ध होगा। पर्यावरण के लिए भी यह बहुत अच्छा कदम है। इससे न केवल प्लास्टिक बोतलों की खपत घटेगी, बल्कि आरओ के नाम पर पानी की बर्बादी भी रुक जाएगी। अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या ममता बनर्जी विपक्षी एकता की धुरी बनने में सफल हो पाएंगी?



सभी आकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या पेगासस जासूसी मामले में जांच की जरूरत है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

ममता दी उभरीं अगर हो करके मजबूत,
तो ट्रैक्टर ले जायंगे कहां सोनिया पूत।
कहां सोनिया पूत करेंगे क्या वह खेती,
फिर सोने की खेप जायगी कहां समेटी!
कहीं न बनकर आप घूमिए जोगी रमता,
अरु दिल्ली का राज हड़प लें जाएं ममता!!

– ओमप्रकाश तिवारी



संजय मिश्र
स्थानीय संपादक, नवदुनिया, भोपाल

मध्य प्रदेश डायरी

ताकत की नई कसौटी होंगे उपचुनाव

मध्य प्रदेश की सियासत एक बार फिर उपचुनाव की कसौटी पर उतरने वाली है। इस बार तीन विधानसभा क्षेत्रों और लोकसभा की एक सीट के लिए उपचुनाव होने वाले हैं। हालांकि अभी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन रजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। क्षेत्रवार सामाजिक समीकरणों को सहेजने के साथ प्रत्याशी चयन की कवायद शुरू की जा चुकी है। यद्यपि इन उपचुनावों के परिणाम से न तो भाजपा की केंद्र सरकार पर कोई असर पड़ने वाला है और न राज्य सरकार पर, लेकिन हैं ये महत्वपूर्ण। दरअसल वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए माहौल बनाने की ध्वनि इन उपचुनावों से निकलेगी। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी स्वीकार कर चुके हैं कि सरकार पर असर न डालने वाले उपचुनाव ज्यादा तनाव देने वाले होते हैं। इसलिए कार्यकर्ता इन उपचुनावों को गंभीरता से लें और जीत सुनिश्चित करने के लिए जुट जाएं। कांग्रेस भी इन उपचुनावों को अपने लिए एक अवसर के रूप में देख रही है। उसे उम्मीद है कि कोरोना काल के दौरान पैदा हुई विषम स्थितियों के कारण शायद उसके हिस्से कोई करिश्मा हो जाए। हालांकि यह सच्चाई है कि 2018 में सरकार बनाने के बाद अंतर्कलह के कारण विपक्ष में आ बैठी कांग्रेस को भी इन उपचुनावों के परिणाम से कोई बड़ा फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन वह यह जानती है कि इन उपचुनावों में यदि जीत मिलती है तो इससे भविष्य की राजनीति के लिए माहौल बनाने में उसे मदद मिल सकती है। इसीलिए वह पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है।

कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया के निधन से रिक्त हुई जोबट सीट आदिवासी बहुल है। 2018 के विधानसभा चुनाव में यहां के आदिवासी भाजपा से नाराज थे, जिसके कारण त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली थी। इस वर्ग का विश्वास जीतना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। इसको स्वीकार करते हुए भाजपा आदिवासियों के बीच पकड़ मजबूत करने के लिए काम शुरू कर चुकी है। विश्वास जीतने के लिए ही भाजपा ने संगठन में वरिष्ठ पदों पर आदिवासी वर्ग से कई नियुक्तियां की हैं। दूसरी ओर कांग्रेस इसे अपनी परंपरागत सीट मानकर चल रही है, लेकिन पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने हाल ही में बाहरी और बागी प्रत्याशी को नामंजूर करने का एलान करके अपना रुख साफ कर दिया है।



लोकसभा की एक और विधानसभा की तीन सीटों के उपचुनाव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (बाएं) और केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कड़ी चुनौती हैं। फाइल

भाजपा विधायक जुगल किशोर बागरी के निधन से खाली हुई विंध्य की रैगांव सीट अनुसूचित जाति बाहुल्य है। इस सीट पर कब्जा बरकरार रखना आसान नहीं है। इसी तरह बुंदेलखंड की पृथ्वीपुर सीट का अपना अलग मिजाज है। यहां 2018 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों ने जबरदस्त टक्कर दी थी और क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे थे। भाजपा का प्रत्याशी चौथे नंबर पर रहा था। कांग्रेस के बृजेंद्र सिंह राठौर ने जीत हासिल की थी। राठौर के निधन के बाद रिक्त हुई इस सीट पर फिर घमासान होने की उम्मीद है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार सिंह चौहान के निधन से रिक्त पूर्वी निमाड़ की खंडवा लोकसभा सीट का उपचुनाव भी कम दिलचस्प नहीं होगा। कांग्रेस की ओर से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव की दावेदारी लगभग तय मानी जा रही है। पार्टी की ओर से घोषणा होने के पूर्व ही वह प्रचार में जुट गए हैं। हालांकि यादव को पिछले चुनाव में यहां से हार का सामना करना पड़ा था। इस सीट पर भाजपा किसे उम्मीदवार बनाएगी यह अभी तय नहीं है। हालांकि प्रत्याशी तय करने के लिए वह मशक्कत कर रही है।

भाजपा से जुड़े लोग मानते हैं कि 27 सीटों पर हुए उपचुनाव की तरह ही इस बार भी करो या मरो की तर्ज पर पार्टी लड़ेगी और जीतेगी। वे कहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के बाद उनके समर्थक कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के बाद 27 सीटों पर हुए उपचुनाव में पार्टी ने जिस तरह सर्वाधिक सीटें जीतकर अपनी सरकार को सुरक्षित कर लिया उसी तरह इस बार भी पार्टी विजय पताका फहराएगी। हालांकि कुछ माह पूर्व विधानसभा की दमोह सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा को बड़ी पराजय मिली थी। इस हार का संदेश यही है कि लोकसभा की एक और विधानसभा की तीन सीटों के उपचुनाव कांग्रेस से अधिक भाजपा के लिए चुनौती हैं।

विश्व बाघ दिवस

वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण





डा. मुदित गुप्ता
वरिष्ठ समन्वयक, उत्तर प्रदेश, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया

आशीष बिस्टा
वरिष्ठ परियोजना अधिकारी, उप्र, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया

विश्व बाघ दिवस एक महत्वपूर्ण अवसर है जब हम वन क्षेत्रों के समीप रहने वाले समुदायों तक यह अपील पहुंचा सकते हैं कि वन तथा वन्यजीवों का संरक्षण संपूर्ण मानव जाति के हित में है

वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण भारतीय सभ्यता का एक अभिन्न अंग रहा है, परंतु बढ़ती जनसंख्या एवं इसके कारण बढ़ते जैविक दबाव को पूरा करने के लिए पिछले दशकों में वनों का दोहन भी खूब हुआ है। भारत में वन तथा वन्यजीवों को बचाने तथा इनके संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की गई है। वर्ष 2020 तक भारत में कुल 104 राष्ट्रीय उद्यान तथा 566 वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना की जा चुकी थी। भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान 'हेली राष्ट्रीय उद्यान' (इसे आज कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है) की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी, परंतु सही मायने में वर्ष 1973 में भारत सरकार की 'बाघ परियोजना' लागू होने के बाद संरक्षित क्षेत्रों के तंत्र में अधिक मजबूती आई। 1972 में भारत में वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम लागू किया गया जिसमें देश के संरक्षित क्षेत्रों एवं वन्यजीवों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की गई है। देश के संरक्षित क्षेत्र जैविक संसाधनों के भंडार हैं। ये संपूर्ण मानव जाति के लिए आवश्यक प्राकृतिक सेवाएं जैसे-हवा तथा जल का शुद्धीकरण, वर्षा, बाढ़ तथा तापमान नियंत्रण और फसलों का परागण इत्यादि करते हैं।

भारत में अधिकांश संरक्षित क्षेत्रों का क्षेत्रफल लगभग 400 से 500 वर्ग किलोमीटर ही है। संरक्षित क्षेत्रों का आकार में कम होना कुछ वन्यजीवों जैसे-बाघ तथा हाथी के संरक्षण के दृष्टिगत चिंता का विषय है, क्योंकि इन जीवों को अपने जीवन चक्र की पूर्ति के लिए बड़े क्षेत्रों की आवश्यकता होती है। वन क्षेत्र में एक वयस्क नर बाघ के रहने के लिए आवश्यक क्षेत्र की सीमा लगभग 200 वर्ग किमी तथा एक वयस्क नर हाथी के लिए यह सीमा क्षेत्र 400 वर्ग किमी तक हो सकती है। अर्थात इन वन्यजीवों को अपने देश में संरक्षित करने के लिए हमें और अधिक तथा बड़े वन क्षेत्रों की आवश्यकता है। अपने छोटे आकार के अतिरिक्त कुछ संरक्षित क्षेत्र अन्य संरक्षित क्षेत्रों से आंशिक अथवा पूर्ण रूप से पृथक हैं जिससे इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले जीवों का दीर्घकालीन संरक्षण चुनौतीपूर्ण प्रतीत होता है।

विभिन्न विखंडित संरक्षित क्षेत्रों के मध्य वन्यजीवों के आवागमन को सुगम एवं सुरक्षित बनाने के लिए इन क्षेत्रों को 'जैविक गलियारों' के माध्यम से जोड़े जाने की आवश्यकता है। जैविक गलियारे दो अथवा अधिक वन प्रखंडों के मध्य वन्यजीवों के आवागमन तथा विचरण के लिए प्राकृतिक मार्ग हैं। ये मार्ग विभिन्न स्वरूपों में हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर-कृषि भूमि, नदी और बहुउद्देशीय वन। विभिन्न क्षेत्रों के मध्य वन्यजीवों का आवागमन कई कारणों से होता है। पहला, इससे प्रजातियों में अंतः प्रजनन की संभावना कम होती है। अंतः प्रजनन से वह प्रजाति हमेशा के लिए विलुप्त भी हो सकती है। दूसरा, वन्यजीव प्राकृतिक आपदाओं जैसे-बीमारी का फैलाव, बाढ़, अग्नि इत्यादि से अपना बचाव कर सकते हैं। जाहिर है ये जैविक गलियारे महत्वपूर्ण पारिस्थितिकीय क्षेत्र हैं, परंतु कभी-कभी इनका संरक्षण एक अत्यधिक दुरूह कार्य भी होता है, क्योंकि सामान्य तौर पर जैविक गलियारे वन तथा संरक्षित क्षेत्रों के बाहर पाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में वन अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा इनका संरक्षण दुष्कर हो जाता है।

उत्तर प्रदेश में भारत सरकार के राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एवं भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा संचालित अखिल भारतीय बाघ गणना वर्ष 2018 के अनुसार कुल 173 बाघ हैं। इनमें से बाघों की अधिकांश आबादी पीलीभीत तथा दुधवा टाइगर रिजर्व में विचरण करती है। जैसे एक अवयस्क बाघ जिसको सर्वप्रथम किशनपुर वन्य जीव विहार में पाया गया था। यह बाघ कुछ समय बाद दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया। किशनपुर वन्य जीव विहार तथा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपस में 30 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इसी तरह दुधवा-कतर्नियाघाट जैविक गलियारा विगत वर्षों में कई बार गैंडों के द्वारा प्रयोग किया गया है। उत्तर प्रदेश में कृषि भूमि से होकर वन्यजीवों का यह आवागमन दीर्घकालीन वन्य जीव संरक्षण की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है।



बाघ जैसे वन्य जीव हमारी संस्कृति तथा जीवन का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। फाइल

संरक्षण की प्रक्रिया में स्थानीय समुदाय भी एक महत्वपूर्ण साझीदार है। विश्व बाघ दिवस एक महत्वपूर्ण अवसर है जब हम वन क्षेत्रों के समीप रहने वाले समुदायों तक यह अपील पहुंचा सकते हैं कि वन तथा वन्यजीवों का संरक्षण संपूर्ण मानव जाति के हित में है। पृथ्वी का प्रत्येक जीवित प्राणी एक विशाल जीवन चक्र का हिस्सा मात्र है तथा सभी प्रजातियों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर है। जैविक गलियारों के संरक्षण के लिए स्थानीय समुदाय को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी तथा सरकार एवं वन विभाग के साथ मिलकर सभी प्राकृतिक संरचनाएं जैसे नदी, तालाब तथा कृषि भूमि को इसके वर्तमान स्वरूप में बनाए रखना होगा। वन्य जीव हमारी संस्कृति तथा जीवन का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। इस तंत्र को संरक्षित करने की जिम्मेदारी हम सभी की है।

300 से अधिक प्रजाति के फूल खिले है उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित फूलों की घाटी में। कोरोना संक्रमण के बावजूद फूलों की घाटी का दीदार करने को हर दिन सैकड़ों पर्यटक पहुंच रहे है।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 29 जुलाई, 2021

उत्तराखंड

कर्मचारियों की हड़ताल

कोरोना के साथ ही मानसून की चुनौतियों से जूझ रहे उत्तराखंड में कर्मचारियों के आंदोलन ने आम जन की दिक्कतों में इजाफा ही किया है। इन दिनों ऊर्जा से जुड़े तीनों निगमों के कार्मिकों के साथ ही सफाई कर्मचारी भी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुखर हैं। हालांकि सुकून इस बात का है कि ऐन वक्त पर सरकार सक्रिय हुई और कर्मचारी संगठनों से वार्ता की। इसके परिणाम सकारात्मक नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, वेतन विसंगतियों के मसले पर सरकार ने पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडे की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति का गठन कर कर्मचारियों के आक्रोश को शांत करने का प्रयास किया है। विडंबना ही है कि वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद से ही उत्तराखंड में कर्मचारियों का असंतोष दिखता रहा है। फलस्वरूप यह असंतोष हड़ताल के रूप में सामने आता रहा है। पांच वर्ष पूर्व कराए गए एक सर्वे में विभिन्न आंदोलनों के कारण काम ठप रहने के मामले में उत्तराखंड शीर्ष पर था। फिर चाहे बात कर्मचारियों की हड़ताल की हो अथवा छात्रों, शिक्षकों या किसी अन्य आंदोलन की।

सरकार और कर्मचारी संगठनों को चाहिए कि समस्या को इतना न बढ़ने दिया जाए कि आम जनजीवन प्रभावित होने लगे

साफ है कि इन आंदोलनों का प्रभाव प्रदेश के विकास पर पड़ता है। सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर यह नौबत क्यों आती है कि कर्मचारियों को हड़ताल करनी पड़े। इसमें कोई दो राय नहीं कि अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करना हर किसी का लोकतांत्रिक अधिकार है। जब कर्मचारियों या किसी संगठन की जायज मांग को तंत्र के स्तर पर लगातार अनसुना किया जाता है तो लोग अपने इस अधिकार का उपयोग करते हैं। सिस्टम की हीला-हवाली आग में घी का काम करती है। ऐसे में कई बार हालात बेहद गंभीर हो जाते हैं। मसलन ऊर्जा से जुड़े निगमों के कार्मिकों के आंदोलन को ही लें। एसीपी और समान काम समान वेतन की मांग को लेकर इनके संगठन पहले ही हड़ताल का एलान कर चुके थे, लेकिन सरकार ने इनसे वार्ता तब शुरू की जिस दिन उन्हें हड़ताल पर जाना था। अब सवाल यह है कि वार्ता के लिए इतना विलंब क्यों किया गया। यह सर्वविदित सत्य है कि किसी भी आंदोलन का समाधान बातचीत की मेज पर ही होता है। ऐसे में शासन और सरकार मामले को क्यों खींचते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि यदि कर्मचारियों की मांगें जायज हैं और सरकार ने उन्हें पूरा करना ही है तो आंदोलन का इंतजार क्यों किया जाता है। इसके अलावा कर्मचारी संगठनों को भी विचार करना चाहिए कि लोकतंत्र में यदि अधिकार दिए गए हैं तो कर्तव्य भी परिभाषित किए गए हैं। अधिकारों के लिए जागरूकता के साथ ही जरूरी है कि कर्तव्य का भी बोध हो। राज्य व जनता के प्रति भी कर्मचारियों की जवाबदेही है।

पंजाब

तालमेल या दबाव!

पंजाब कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ बैठक हुई तो थी तालमेल बिठाकर काम करने को लेकर, लेकिन दोनों के बीच खिंचाव जगजाहिर हो गया। सिद्धू ने बैठक करके एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की मगर फिर अपनी आदत के मुताबिक बैठक के एकदम बाद ट्विटर पर वह पत्र जारी कर दिया जो उन्होंने कैप्टन को दिया है। चारों कार्यकारी अध्यक्षों के साथ मुख्यमंत्री के कार्यालय में जाकर बैठक करके उन्होंने हाईकमान को यह संदेश तो दे दिया कि वह सरकार से सामंजस्य बिठाने का प्रयत्न कर रहे हैं, साथ ही कैप्टन पर दबाव बनाने की कोशिश भी कर डाली।

चूंकि आम तौर पर ऐसी बैठकों के एजेंडे सरकार व पार्टी की ओर से गोपनीय रखे जाते हैं, फिर भी सिद्धू का इसे सार्वजनिक कर देने का कदम तालमेल से काम करने वाला तो नहीं कहा जा सकता। वैसे तो सिद्धू ने अध्यक्ष बनने से पहले ही विधायकों, मंत्रियों व अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकातें शुरू कर दी थीं, लेकिन विधिवत पद संभालने के बाद मुख्यमंत्री से बैठक करना कहीं न कहीं यह संकेत भी देता है

सिद्धू और कैप्टन की बैठक संगठन व सरकार में तालमेल बिठाने को लेकर थी, लेकिन कोशिश इसमें दबाव बनाने की हुई



सीएम कार्यालय में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से बात करते पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू (बाएं)। फाइल

कि नए अध्यक्ष को यह अहसास है कि अगर साथ मिलकर नहीं चले तो पार्टी हाईकमान ने उनसे जो उम्मीदें लगा रखी हैं, वह पूरी होना मुश्किल होगा।

सिद्धू ने पद संभालते ही यह एलान किया था कि वह हाईकमान की ओर से दिए गए 18 सूत्रीय एजेंडे पर काम करेंगे। एजेंडे में वही वादे हैं जो कांग्रेस ने पिछले चुनाव के वक्त किए थे। सिद्धू ने बेअदबी, नशा, बिजली समझौतों के जो मामले पत्र में बताए हैं, वह सरकार को ही हल करने हैं। इसलिए मुख्यमंत्री ने भी जवाब दे डाला कि जो मुद्दे सिद्धू ने उनके समक्ष रखे हैं, उनके हल के लिए सरकार पहले ही कदम बढ़ा चुकी है।

उन्होंने भी सिद्धू से कहा है कि सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाएं, यानी केवल सरकार की कमियों को उजागर न करें। हालांकि उन्होंने एक बार फिर लंबी लकीर खींचते हुए यह कहा कि राज्य व पार्टी के हित में उन्हें मिलकर काम करना होगा। इस तरह बैठक करने के लिए दोनों ओर से रुख में दिखाया गया लचीलापन पहले कांग्रेस हाईकमान के लिए बेशक कुछ सुकून देने वाला रहा हो, लेकिन बैठक के बाद जो हो रहा है उसे देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि दोनों के बीच वास्तव में कितना समन्वय हो पाता है, यह वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो इसके आसार कम ही नजर आते हैं।

उत्तर प्रदेश

कड़ी निगरानी जरूरी

उत्तर प्रदेश में साइबर थानों की ओर से अपराधियों पर शुरू हुई चौबीसों घंटे की निगरानी धोखाधड़ी और साइबर ठगी से जुड़े अपराधों पर लगाम लगाने में अहम साबित हो सकती है। साइबर अपराधियों का कुछ ही वर्षों में जंजाल कितना फल-फूल चुका है, इसकी झलक सरकारी पोर्टल पर दर्ज कराई जा चुकीं करीब 50 हजार शिकायतें ही दिखा रही हैं। इनकी रोकथाम के लिए ही अगस्त 2020 में प्रदेश के सभी 18 परिक्षेत्रों में साइबर थाने खोले गए थे। इन्हीं की बदौलत पिछले दिनों लखनऊ की साइबर क्राइम टीम ने देश के चर्चित साइबर ठग प्रमोद मंडल को उसके चार साथियों संग गिरफ्तार करने में सफलता पाई थी। लोगों के बैंक खातों से करोड़ों रुपये उड़ा चुके इस गैंग के सरगना की यूपी समेत देश के 10 राज्यों में तलाश हो रही थी। इनके अलावा भी प्रदेश के 385 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके ठगी के साढ़े पांच करोड़ रुपये बरामद किए जा चुके हैं।

बीते कुछ वर्षों में जैसे-जैसे आनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन और सोशल मीडिया का चलन बढ़ा है,



साइबर अपराध पर लगाम लगाने में तत्परता दिखाए पुलिस। प्रतीकात्मक

पुलिस अधिकारियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि साइबर अपराधियों के खिलाफ अदालती पैरोकारी ठीक से हो, ताकि वे साक्ष्य की कमजोरियों का तनिक भी फायदा न उठा सकें

वैसे वैसे प्रदेश में साइबर अपराध का ग्राफ भी उछाल मारता जा रहा है। हाल यह है कि वर्ष 2018 में साइबर क्राइम से जुड़ी 6280 शिकायतें पुलिस तक पहुंची थीं, जो अब आठ गुना पार हो चुकी हैं।

साइबर अपराधी अब बैंकिंग धोखाधड़ी ही नहीं कर रहे, बल्कि नौकरी देने, आनलाइन सामान मंगवाने, सरकारी विभागों के दस्तावेज देने जैसे फ्राड भी कर रहे हैं। इसी पर नियंत्रण की अपेक्षा के साथ साइबर थाने खोले गए हैं। इन्हें एक लाख रुपये या इससे अधिक रकम की साइबर ठगी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बाल यौन उत्पीड़न, हैकिंग, क्रिप्टो करेंसी, अंतरराज्यीय या अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध के सभी मामलों को अपने थानों में दर्ज करके उसकी विवेचना का अधिकार भी है। अब पुलिस अधिकारियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि साइबर अपराधियों के खिलाफ अदालती पैरोकारी ठीक से हो, ताकि वे साक्ष्य की कमजोरियों का तनिक भी फायदा न उठा सकें।

बंगाल

ममता के आयोग पर सवाल

कथित पेगासस फोन टैपिंग प्रकरण की जांच के लिए दिल्ली रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दो सदस्यीय जांच आयोग गठित किया। जिसके सदस्य सुप्रीम कोर्ट एवं कलकत्ता हाई कोर्ट के दो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। परंतु उनके इस आयोग गठन को लेकर भाजपा ने तो सवाल उठाया ही है, साथ में माकपा ने भी हमला बोला है। पोलित ब्यूरो के सदस्य और माकपा के राज्य सचिव सूर्यकांत मिश्र के बाद बंगाल विधानसभा के वाम विधायक दल के नेता रहे सुजन चक्रवर्ती ने सवाल किया है कि मुकुल राय ने भाजपा में रहते हुए ममता पर उनका फोन टैप कराने का आरोप लगाया था। मुख्यमंत्री को पहले इसका जवाब देना चाहिए। सुजन ने यह जरूर कहा कि फोन टैप कराए जाने का पूरे देश में विरोध होना चाहिए। परंतु फोन टैपिंग को लेकर ऐसे ही सवाल भाजपा में रहते हुए मुकुल राय ने ममता सरकार पर भी उठाए थे।

उन्होंने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया था कि वे विरोधी दल के नेताओं के फोन टैप करवाती हैं। माकपा नेता ने कहा कि इस मुद्दे पर ममता क्यों नहीं कुछ कह रहीं? उन्हें मुकुल के उन ओरोपों का जवाब देना चाहिए, क्योंकि राय ने सिर्फ आरोप ही नहीं लगाये थे। वे इस मुद्दे को कोर्ट तक ले गए थे। मुकुल ने तब कहा था कि ममता सरकार इजरायल की तकनीक की मदद से उनका और विरोधी दल के अन्य नेताओं के फोन टैप करवा रही है। चक्रवर्ती ने कहा कि अब ऐसे में सवाल उठता है कि मुकुल ने उस वक्त जो आरोप लगाए थे, क्या यह वही पेगासस है? इस बारे में मुख्यमंत्री पहले स्पष्टीकरण दें। बंगाल की जनता को इस बारे में जानने का पूरा हक है। पिछले दिनों माकपा राज्य सचिव ने भी कहा था कि पेगासस के जरिये किसी की भी जासूसी का उनकी पार्टी विरोध करती है। साथ ही उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी भी अपने विरोधियों की जासूसी करवाती हैं।

वाम विधायक दल के नेता रहे सुजन चक्रवर्ती ने सवाल किया है कि मुकुल राय ने भाजपा में रहते हुए ममता पर उनका फोन टैप कराने का आरोप लगाया था। मुख्यमंत्री को पहले इसका जवाब देना चाहिए

वहीं भाजपा की बंगाल इकाई के नेताओं ने भी ममता बनर्जी द्वारा जांच आयोग गठित करने के निर्णय पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो खुद ही इजरायली तकनीकी का इस्तेमाल अपने विरोधियों, पत्रकारों, सरकारी अधिकारियों और यहां तक अपनी ही पार्टी के नेताओं की निगरानी के लिए कर रही हैं, वे जांच आयोग बना रही हैं। भाजपा ने सवाल किया है कि क्या पिछले 10 वर्षों में कोलकाता पुलिस का कोई कमिश्नर इस स्पाइवेयर के लिए इजरायल गया था? इस सवाल का पहले ममता जवाब दें। अगर एक आरोप के जांच के लिए आयोग गठित हो सकता है तो दूसरे के लिए क्यों नहीं?

गंगा छोर पर होगा गेटवे आफ कारिडोर

90 फीट चौड़े व 32 फीट ऊंचे गेट के लिए जलासेन घाट पर शुरू हो गई पाइलिंग

बाबा दरबार से गंगधार को एकाकार कर रहे श्रीकाशी विश्वनाथ धाम का गंगा छोर पर बन रहा द्वार गेटवे आफ कारिडोर होगा। सड़क से गंगा तट मणिकर्णिका घाट-जलासेन व ललिता घाट तक 50,200 वर्ग मीटर में विस्तारित कारिडोर के तीनों द्वारों में सबसे आकर्षक तो होगा ही, धर्मशास्त्रीय विधान अनुसार भी इसका सर्वाधिक मान होगा। वास्तव में काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन से पहले गंगा स्नान या आचमन की मान्यता है। काशी-विश्वनाथ-गंगे का धर्म दर्शन भी इससे ही मूर्त रूप ले पाएगा। इस लिहाज से जलासेन घाट पर बनाए जा रहे गेट को खास रूप दिया जाएगा। वाराणसी से प्रमोद यादव की रिपोर्ट...



ललिता घाट पर निर्माणाधीन जेटी •जागरण



मणिकर्णिका घाट पर चल रहा कार्य •जागरण

द्वार के एक ओर रैंप, दूसरी ओर कैफेटेरिया

गंगा द्वार के एक ओर रैंप भवन होगा, ताकि वृद्धजन व असहायों को व्हील चेयर से कारिडोर में ले जाया जा सके। रैंप का यह हिस्सा मणिकर्णिकाघाट से लगा होगा। इस घाट पर सीढ़ियों के साथ ही गंगधार तक जाने के लिए भी रैंप बनाया जाएगा। दूसरी ओर बन रहे कैफेटेरिया से गंगा की छटा निहारी जा सकेगी।

10 से 20 मीटर तक चौड़े होंगे तीनों घाट

कारिडोर के गंगा छोर के तीनों घाटों की चौड़ाई कार्य अनुसार 10 से 20 मीटर तक बढ़ाई जा रही है। इसके लिए लगभग 200 मीटर लंबाई में डायाफ्राम वाल पहले ही तैयार की जा चुकी है। अब इस पर टाइल्स लगाने की तैयारी हो रही है। मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एसके वर्मा के अनुसार बाढ़ से पहले घाट के निचले हिस्से का कार्य पूरा कर लेने का लक्ष्य है।



जलासेन घाट जहां बनेगा कारिडोर गेट व रैंप

नक्काशीदार पत्थर, लकड़ियां

कारिडोर के अन्य तीन द्वार गिट्टी से ढाले जा रहे तो गंगा द्वार को चुनार के पत्थरों से आकार दिया जाएगा। ऊंचाई 32 फीट व चौड़ाई 90 फीट होगी। दरवाजे नक्काशीदार लकड़ी के होंगे, पीतल से सज्जा भी होगी।

55 मीटर अंदर तक जेटी

गंगा प्रवेश द्वार तक श्रद्धालु नाव-बजड़ों या रो पैक्स व जलयान से आ सकेंगे। इसके लिए ललिता घाट पर गंगा में 55 मीटर लंबी व सात मीटर चौड़ी जेटी ढाल दी गई है। इसके दोनों ओर नाव-बजड़े लग सकेंगे।

जागरण इन्फो चित्र • उत्तम राय चौधरी | डिजाइनर • विकास चौधरी

श्रद्धा का महासावन

भाव के भूखे हैं भगवान शिव

शिव भाव के भूखे हैं, उनको सावन मास सबसे प्रिय है। इस महीने में जब ओम नमः शिवाय का जप करते हुए भक्त शिवलिंग पर भाव से जल अर्पित करते हैं तो उन्हें प्रसन्नता मिल जाती है। भगवान शिव पतित पावनी मोक्षदायिनी मां गंगा को अपनी जटाओं में धारण किए हैं। ऐसा सामर्थ्य केवल उनमें ही है। सिर पर चंद्रमा धारण कर वह शीतलता के प्रतीक हैं। सर्प की माला, सिंह की खाल का आसन और नंदी की सवारी अर्थात जो अहितकारी है, उस पर शिव का नियंत्रण है। शिव नृत्य, संगीत आदि कलाओं के जनक हैं। अमंगलकारी शक्तियों की क्षति के लिए शिवोपासना जरूरी है। शिव की उपासना समग्र सृष्टि के कल्याण, सुख और निरोगी होने की कामना पूर्ण करती है। शिव की भाव से की गई स्तुति से सृष्टि का संरक्षण होता है। सृष्टि संरक्षित होगी तो मानव जीवन भी बचेगा। अमृत का पान तो सभी करना चाहते हैं, लेकिन भगवान शिव जनकल्याण के लिए विष पीते हैं। यही कारण है कि शिव की पूजा देव, दैत्य व मनुष्य तीनों ही करते हैं। कल्याणकारी होने के साथ शिव संहारकर्ता भी हैं। वास्तव में यह संहार नवजीवन के लिए है जैसे सृजन के लिए विध्वंस होता है। शिव भक्तों का कल्याण करते हैं तो मृत्यु प्रदाता भी हैं। इसके जरिए वह प्रकृति का संतुलन बनाते हैं। सावन के महीने में शिव ही जागृत अवस्था में रहते हैं। शिव का एक स्वरूप प्रकृति के संरक्षक का भी है।



जगद्गुरु स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती
सदस्य, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट

स्कैन करें और पढ़ें 'श्रावण मास' से संबंधित सभी सामग्री

पेंशन खैरात नहीं, है सेवा अधिकार : हाई कोर्ट

विधि संवाददाता, प्रयागराज

- सेवानिवृत्ति के बाद राज्यपाल की अनुमति बगैर नहीं की जा सकती विभागीय जांच
- नौ फीसद ब्याज सहित दो माह में पेंशन आदि का भुगतान करे विभाग

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि सिविल सर्विस रेग्यूलेशन 351(ए) के अंतर्गत वित्तीय क्षति की भरपाई के लिए कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने से पहले विभागीय कार्यवाही शुरू करनी चाहिए। पेंशन खैरात नहीं है, सेवा अधिकार है। सेवानिवृत्ति के बाद बिना राज्यपाल से अनुमोदन लिए विभागीय कार्यवाही संविधान के अनुच्छेद 300(ए) के विपरीत है।

इस टिप्पणी के साथ न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने बिजली विभाग में कनिष्ठ अभियंता पद से सेवानिवृत्त अनिल कुमार शर्मा को पेंशन आदि पाने का हकदार मानते हुए विभाग को नौ फीसद ब्याज सहित सेवानिवृत्ति परिलाभों का दो माह में भुगतान करने का निर्देश दिया है। कहा, आदेश का पालन नहीं किया गया तो छह फीसद अतिरिक्त ब्याज सहित कुल 15 फीसद ब्याज का भुगतान करना होगा। कोर्ट ने पेंशन का भुगतान न कर तीन साल परेशान करने पर दो माह में याची को 25 हजार रुपये हर्जाना भी देने का निर्देश दिया है।

अनिल कुमार शर्मा चार जून, 1974 को मृतक आश्रित कोटे से बिजली विभाग में पेट्रोलमैन पद पर नियुक्त हुए और 31 दिसंबर, 2018 को अमरोहा में बिजली विभाग से फिर बतौर कनिष्ठ अभियंता सेवानिवृत्त हुए। 14 नवंबर, 2018 को शिकायत हुई तो 22 नवंबर, 2018 को निलंबित कर दिया गया। 28 दिसंबर, 2018 को निलंबन खत्म हो गया। विभाग का कहना था कि मृतक आश्रित कोटे में परिवार के एक व्यक्ति को

कानूनी कार्यवाही के बगैर किसी को संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। पेंशन खैरात नहीं है, यह कर्मचारी की सेवा का अधिकार है, जिसे बिना कानूनी प्रक्रिया के रोका नहीं जा सकता।
-इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी

नौकरी मिल सकती है, यहां याची और उनके भाई दोनों ने नियुक्ति पा ली है। उनके खिलाफ बिजली चोरी की भी शिकायत है। विभाग को आर्थिक नुकसान वसूलने का अधिकार है। प्रबंध निदेशक के अनुमोदन पर विभागीय कार्यवाही शुरू की गई है। निगम के प्रस्ताव पर जारी सर्कुलर से प्रबंध निदेशक को अनुमोदन का अधिकार है। कोर्ट ने इसे विधिसम्मत नहीं माना और कहा कि राज्यपाल के अनुमोदन का अधिकार प्रबंध निदेशक को सौंपने की कानूनी घोषणा नहीं की गई है। सेवानिवृत्त होने के समय याची निलंबित नहीं था। कोई विभागीय जांच कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी। ऐसे में पेंशन आदि न देना अधिकार का अतिलंघन है।

कोर्ट ने कहा है कि विभागीय नुकसान की वसूली के लिए सेवानिवृत्ति से पहले आरोपपत्र देना जरूरी है। इसके बाद शुरू की गई कार्यवाही मनमानी मानी जाएगी। निगम के प्रस्ताव और सर्कुलर से राज्यपाल के अधिकार राज्य विद्युत निगम के प्रबंध निदेशक को नहीं दिए जा सकते।

ओबीसी आरक्षण के वर्गीकरण पर राज्यों के साथ चर्चा फिलहाल टली

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन करने के बाद रोहिणी कमीशन ने उठाया कदम
- कोर्ट ने राज्यों की सूची गलत बता कहा था कि राज्य को सूची बनाने का अधिकार नहीं
- कोर्ट के फैसले पर असहमति जता केंद्र ने पुरानी व्यवस्था बहाल करने का भरोसा दिया

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उप-वर्गीकरण की राह में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फिलहाल एक बड़ा रोड़ा आ गया है। जिसके चलते रोहणी कमीशन ने राज्यों के साथ चर्चा की अपनी पूरी योजना टाल दी है। अब केंद्र सरकार के अगले कदम के इंतजार में है। कमीशन ने यह कदम तब उठाया, जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में राज्यों की ओबीसी सूची को ही गलत बता दिया और कहा है कि राज्यों को इस तरह की कोई सूची बनाने का अधिकार नहीं है।

कमीशन से जुड़े एक वरिष्ठ सदस्य के मुताबिक राज्यों के साथ चर्चा टालने का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से मराठा आरक्षण पर सुनवाई के दौरान दिए गए फैसले का अध्ययन करने के बाद लिया गया। वैसे भी राज्यों के साथ यह चर्चा उनकी ओबीसी सूची को लेकर की जानी थी, लेकिन कोर्ट ने ही जब सूची को गलत बता दिया, तो राज्यों के साथ चर्चा का कोई औचित्य नहीं बनता है।

हालांकि इस फैसले से केंद्र ने असहमति जताई है और कहा कि वह राज्यों को उनके अधिकार वापस देगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने इसे लेकर संसद में विधेयक भी लाने के संकेत दिए हैं।

कमीशन से जुड़े सदस्य के मुताबिक ओबीसी की केंद्रीय सूची के आधार पर वैसे तो आयोग ने अपना काम पूरा कर लिया है। जिसमें शामिल करीब 26 सौ जातियों का ब्योरा और कब उन्हें इस सूची में शामिल किया गया है इससे जुड़ी पूरी जानकारी जुटा ली गई है। साथ ही ओबीसी को मिले 27 फीसद आरक्षण से किसी जाति को अब तक कितना लाभ मिला है, इसकी भी पूरी जानकारी तैयार कर ली गई है। इस बीच वर्गीकरण का जो प्लान भी बनाया गया है, उनमें ओबीसी की बड़ी जातियों को ज्यादा आरक्षण भी दिया जाएगा। जो करीब दस फीसद तक होगा। इन जातियों की संख्या करीब सौ है। हालांकि अब तक ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण का सबसे ज्यादा लाभ यही अगड़ी जातियां ही लेती रही हैं। वहीं ओबीसी की करीब 16 सौ ऐसी जातियां भी चिह्नित की गई हैं, जिन्हें अब तक आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला है। हालांकि इनकी संख्या बेहद कम है। ऐसे में इन जातियों को भी अब दो से तीन फीसद आरक्षण देने की योजना बनाई गई है। बाकी करीब 14 फीसद आरक्षण को ओबीसी की बाकी जातियों के बीच दो से तीन श्रेणियों में बांटने की योजना है। हालांकि उनका मानना है कि केंद्र ने राज्यों की सूची को बहाल किया तो नए सिरे से वर्गीकरण पर विचार करना होगा। फिलहाल कमीशन का कार्यकाल अभी दिसंबर 2021 तक है।

11 राज्यों के साथ होनी थी चर्चा

कमीशन ने ओबीसी आरक्षण का वर्गीकरण कर चुके जिन 11 राज्यों के साथ चर्चा की योजना बनाई थी, उनमें आंध्र प्रदेश, बंगाल, झारखंड, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, जम्मू-कश्मीर और पुडुचेरी शामिल हैं।

2001 में चीन के शंघाई शहर में आयोजित शिखर सम्मेलन में रूस, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की स्थापना की थी।

तालिबान वार्ताकार के बेटे समेत कई आतंकी ढेर

अफगान समस्या ▸ सेना ने जंग में आतंकी मुल्ला शफीक को भी मार गिराया

अशरफ गनी बोले, हम शांति के लिए तालिबान से सीधे वार्ता को तैयार


आतंकियों के खिलाफ मोर्चा संभाले जवान। (फाइल फोटो)

काबुल, आइएएनएस : अफगानिस्तान में चल रही जंग में पिछले 24 घंटे के दौरान सेना ने पकतिया प्रांत में तालिबान के डिप्टी चीफ अब्दुल हक उमरी को मार गिराया। अब्दुल हक दोहा में अफगान सरकार से वार्ता में भाग ले रहे तालिबान के एक नेता का बेटा है। इसके अलावा तालिबान का शीर्ष आतंकी मुल्ला शफीक भी लड़ाई में ढेर हो गया। इधर अफगान राष्ट्रपति ने कहा है कि अफगान समस्या का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। हम तालिबान से सीधे वार्ता को तैयार हैं।

अफगान सेना और तालिबान के बीच चल रहे युद्ध में सेना को दो सफलता मिलीं। पकतिया प्रांत में तालिबान का डिप्टी कमांडर अब्दुल हक उमरी मारा गया। दोहा में चल रही वार्ता में भाग ले रहे तालिबान के सबसे कम उम्र नेता अनस हक्कानी ने ट्वीट कर पुष्टि की है कि अब्दुल हक वार्ता में शामिल मोहम्मद नबी उमरी का पुत्र है, जिसकी अफगान सेना के हाथों मौत हो गई है। मोहम्मद नबी उमरी ग्वांतानामो जेल में बंद था, जिसे 2015 में छोड़ा गया था। उसके साथ छोड़े गए चार अन्य कैदी भी इस समय अफगान सरकार से दोहा में चल रही वार्ता में शामिल हैं।

एएनआइ के अनुसार, जौजान प्रांत में चल रहे युद्ध के दौरान तालिबान के शीर्ष आतंकी मुल्ला शफीक को भी मार दिया गया है। प्रांतीय गवर्नर के प्रवक्ता मोहम्मद रेजा गफूरी ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि शबरगान-मजार हाईवे पर सिक्योरिटी चेकपोस्ट पर संघर्ष में मुल्ला शफीक मारा गया है। तालिबान ने उसके मारे जाने पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा है कि सैन्य तरीके से अफगान समस्या का हल नहीं किया जा सकता है। हमारी सरकार तालिबान से शांति और युद्ध विराम के मसले पर सीधे वार्ता को तैयार है। हमने पांच हजार तालिबान को छोड़कर शांति का संदेश पहले ही दे दिया है।

मुल्ला बरादर के नेतृत्व में तालिबान का दल मिला चीनी विदेश मंत्री से

रायटर के अनुसार, तालिबान के डिप्टी लीडर मुल्ला बरादर अखुंद के नेतृत्व में नौ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। तालिबान ने चीन को एक बार फिर आश्वस्त किया है कि अफगानिस्तान की जमीन चीन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जाएगी। चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि तालिबान अफगानिस्तान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।


विदेश मंत्री वांग यी के साथ मुल्ला बरादर। एपी

सीरिया- लीबिया से पहुंच रहे आइएस आतंकी : रूसी रक्षा मंत्री

रायटर के अनुसार, रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोयगु ने कहा है कि इस्लामिक स्टेट (आइएस) के आतंकी सीरिया, लीबिया और अन्य देशों से अफगानिस्तान पहुंच रहे हैं। एएनआइ के अनुसार, रूस के रक्षा मंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिका का मिशन पूरी तरह फेल रहा। यहां के राष्ट्रपति अशरफ गनी के हाथ से भी स्थिति निकल चुकी है। सर्गेई ने यह बात दुशांबे में शंघाई कोआपरेशन आर्गनाइजेशन की बैठक में कही।



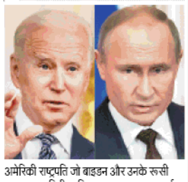
अमेरिका ने अफगान समस्या को उलझाया : इमरान

प्रेट्र के अनुसार, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमेरिका की आलोचना करते हुए कहा है कि उसी के कारण ही अफगान समस्या पूरी तरह उलझ गई है। उन्होंने कहा कि इस समस्या का हल सभी पक्षों के राजनीतिक समाधान से ही हो सकेगा। इधर पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान ने कहा है कि अफगानिस्तान में सेना के खिलाफ तालिबान लड़ाकों की जीत पूरे विश्व के मुस्लिमों की जीत है।



अमेरिकी संसदीय व सूबाई चुनावों में खलल डाल रहे हैं पुतिन : बाइडन

- अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूसी समकक्ष पर लगाए गंभीर आरोप
- साइबर हमलों के लिए भी पुतिन को सीधे-सीधे जिम्मेदार ठहराया


अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन। जागरण आर्काइव

वाशिंगटन, एएनआइ : अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बाइडन ने कहा है कि पुतिन भ्रामक सूचनाएं फैलाकर 2022 में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा और राज्यों के होने जा रहे चुनावों में खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पुतिन ही वास्तविक समस्याओं की जड़ में हैं। वह एक ऐसी अर्थव्यवस्था के सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, जिनके पास परमाणु शक्ति के अलावा कुछ भी नहीं है। पुतिन जानते हैं कि वह गंभीर समस्याओं से घिरे हुए हैं। यही स्थिति उनको और खतरनाक बना रही है। बाइडन ने हाल ही में रैंसमवेयर के हमलों पर भी चिंता जताई। इन हमलों में साइबर अपराधियों ने डाटा चुराए और उनके लिए मोटी रकम फिरौती में मांगी।

बाइडन ने ये बात आफिस आफ अमेरिकी डायरेक्टर आफ नेशनल इंटेलीजेंस (ओडीएनआइ) के कार्यालय में नियमित ब्रीफिंग के दौरान कही। उन्होंने कहा कि देखिए, रूस किस तरह से मध्यावधि चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। वह गलत और भ्रामक सूचनाओं का प्रसारण कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि यह मास्को का सीधे तौर पर हमारी संप्रभुता पर हमला है।

उत्तरी वर्जीनिया के ओडीएनआइ के मुख्यालय में हुई इस बैठक में यूएस इंटेलीजेंस कमेटी के 120 प्रतिनिधि मौजूद थे। ध्यान रहे, 2022 में प्रतिनिधि सभा की सभी 435 सीटों, सीनेट की खाली होने जा रही 34 सीटों और 36 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि अमेरिका रूस पर पहले भी उसके चुनावों को प्रभावित करने का आरोप लगा चुका है।

पाकिस्तान में चीनी नागरिक पर फिर किया गया हमला


- बाइक सवार बंदूकधारियों ने चीनी नागरिकों की कार पर चलाई गोलियां

पाकिस्तान के शहर कराची में बुधवार को चीनी नागरिकों पर हमले की घटना के बाद छानबीन करते पुलिस अधिकारी। एएफपी

कराची, एपी : पाकिस्तान में एक बार फिर चीनी नागरिकों पर हमला हुआ है। तटीय शहर कराची में एक फैक्ट्री में काम करने वाले दो चीनी नागरिक जब रास्ते में थे, तो मोटर साइकिल पर सवार दो बंदूकधारियों ने उनकी कार पर फायरिंग की। इस हमले में एक चीनी नागरिक भागने में कामयाब रहा जबकि दूसरा गोली लगने से घायल हो गया। वहीं, चीन ने भी इस हमले को अकेली ऐसी घटना बताकर तूल नहीं दिया है।

पाकिस्तान के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जावेद अकबर ने बुधवार को बताया कि इस मामले की जांच हो रही है। हमले का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। राहत कर्मी अहमद शाह ने बताया कि जिन पर हमला हुआ वह दोनों चीनी नागरिक थे। इनमें से केवल एक घायल हुआ है। कराची पाकिस्तान के दक्षिणी सिंध प्रांत में स्थित है और वहां पर चीनी सहायता से कई निर्माण परियोजनाएं चल रही हैं। वहीं, चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा, कराची में एक चीनी नागरिक का हमले में घायल होना अपनी तरह की अकेली घटना है। हमें यकीन है कि पाकिस्तान इस मामले की अच्छी तरह तफ्तीश करेगा। ज्ञात हो, पिछले दिनों एक बस में विस्फोट के बाद उसमें सवार नौ चीनी नागरिक और चार पाकिस्तानी मारे गए थे। पहले पाकिस्तान ने इसे हादसा माना था, लेकिन चीन के दबाव के बाद इसे बम विस्फोट माना गया।

पाक में हिंदुओं को प्रताड़ित कर रही सेना

लंदन, एएनआइ : पाकिस्तान में हिंदुओं को प्रताड़ित करने में सेना ने सभी हदें पार कर दी हैं। मुताहिदा कौमी मूवमेंट के नेता और संस्थापक अल्ताफ हुसैन ने सिंध के थार जिले का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में सेना एक हिंदू युवक का उत्पीड़न कर रही है और उसको भगवान के प्रति अपशब्द कहने के लिए मजबूर कर रही है। यहां नहीं युवक जब कुछ बोलता नहीं है, तो उसको यातना दी जा रही है।

मुताहिदा कौमी मूवमेंट के नेता अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि ऐसी तमाम घटनाएं सामने आ रही हैं। विशेषतौर पर सिंध प्रांत में धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा है। एमक्यूएम नेता ने एक अन्य वीडियो साझा किया है, यह सिंध प्रांत के सुक्कुर जिले का है। जिसमें हिंदू लड़की रोते हुए कह रही है कि वह पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराएगी, क्योंकि वह मुसलमान नहीं है। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की तो वो मुझे जेल भेज देंगे। इस लड़की का शादी के लिए अपहरण किया गया और धर्म परिवर्तन के लिए प्रताड़ित किया गया। इस लड़की को बाद में मुक्त करा लिया गया था। ज्ञात हो हिंदुओं को प्रताड़ित किए जाने के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं।

'आतंकवाद का समर्थन करना मानवता से अपराध'

नई दिल्ली, प्रेट्र : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुशांबे में हुए शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की अहम बैठक में कहा कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए आतंकवाद सबसे गंभीर खतरा है। आतंकवाद का किसी भी रूप में समर्थन करना मानवता के प्रति अपराध है। उन्होंने पाकिस्तान की ओर इशारा करते हुए कहा कि भारत आतंकवाद के सभी स्वरूपों के खिलाफ युद्ध के लिए प्रतिबद्ध है। आतंकवाद के साथ शांति और समृद्धि नहीं आ सकती है।

रक्षा मंत्री सिंह ने बुधवार को चीन, रूस, और एससीओ के अन्य सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की मौजूदगी में कहा कि सीमा पार से आतंकवाद समेत दहशतगर्दी के किसी भी स्वरूप को अंजाम और समर्थन देना मानवता के खिलाफ अपराध है। फिर इसके पीछे चाहे कोई भी मकसद क्यों न हो। भारत इस बात का आश्वासन देता है कि वह हमेशा आतंकवाद के सभी रूपों और साजिशों के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को लेकर भारत विश्वास बहाली को सर्वोच्च वरीयता देता है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद से निपटने में बड़े देशों को हर स्तर पर अपनी उचित भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत का मकसद क्षेत्र को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और स्थिर बनाना है। राजनाथ ने कहा कि भारत की भूमिका अफगानिस्तान का विकास करने में रही है तो पाकिस्तान और चीन की भूमिका तालिबान को बढ़ावा देने और दक्षिण चीन सागर का विवाद बढ़ाने में रही है।

एससीओ सम्मेलन
- दुशांबे में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शामिल हुए रक्षा मंत्री
- कहा, पाक-चीन की भूमिका तालिबान व दक्षिण चीन सागर विवाद बढ़ाने में
- बेलारूस और रूस के रक्षा मंत्रियों से की द्विपक्षीय वार्ता


रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में हिस्सा लिया। प्रेट्र

राजनाथ सिंह आठ देशों के प्रभावशाली संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल होने मंगलवार को तीन दिवसीय दौरे पर ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे पहुंचे। इस सम्मेलन में शामिल होने से पहले राजनाथ सिंह ने बेलारूस के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल विक्टर ख्रेनिन से द्विपक्षीय बातचीत की। इसके अलावा, राजनाथ सिंह रूस के रक्षा मंत्री जनरल सर्गेई शोगु से भी मिले। रूस में भारतीय राजदूत ने दोनों नेताओं की फोटो के साथ ट्वीट कर कहा कि दोनों नेताओं की बातचीत में भारत और रूस की गर्मजोशी से भरी दोस्ती और विश्वास की झलक थी। दोनों देशों ने रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने की पुष्टि की।

इससे पहले, विदेश मंत्री एस. जयशंकर 14 जुलाई को एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने दुशांबे पहुंचे थे। ताजिकिस्तान इस साल एससीओ की अध्यक्षता कर रहा है और मंत्री एवं अधिकारी स्तर की कई सिलसिलेवार बैठकों का आयोजन कर रहा है। एससीओ को नाटो के जवाब के तौर पर देखा जाता है।

भारत और पाकिस्तान 2017 में शंघाई सहयोग संगठन के स्थायी सदस्य बने थे। इस समूह की स्थापना 2001 में रूस, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने चीन के शहर शंघाई में आयोजित एक शिखर सम्मेलन में की थी।

ब्लिंकन ने नेपाल के नए पीएम देउबा से की फोन पर बातचीत

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने नेपाल के नए प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा से द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर बातचीत की। साथ ही कोरोना से निपटने की तैयारियों व पर्यावरण परिवर्तन के प्रभावों पर भी बातचीत की है।

अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने बताया कि गत मंगलवार को ब्लिंकन ने पीएम देउबा से टेलीफोन पर बातचीत की है। उन्होंने अमेरिका-नेपाल की साझेदारी के महत्व पर जोर दिया और अमेरिका की ओर से दी गईं 15 करोड़ वैक्सीनों पर चर्चा की। साथ ही नेपाल को कोरोना के संबंध में मिली अन्य सहायताओं का भी जिक्र हुआ। प्राइस ने कहा, विदेश मंत्री ब्लिंकन और पीएम देउबा ने पर्यावरण परिवर्तन के प्रभाव और इसे दूर करने के उपायों पर भी चर्चा की। इससे पहले, ब्लिंकन ने ट्वीट करके बताया था कि उन्होंने नेपाल के पीएम देउबा से फोन पर बात की है। नेपाल-अमेरिका के संबंधों को आगे बढ़ाने और कोरोना से मुकाबले पर विचार-विमर्श किया। दूसरी ओर, देउबा ने बताया कि द्विपक्षीय मुद्दों पर ब्लिंकन के साथ विचारों का आदान-प्रदान किया और कोविड-19 व पर्यावरण परिवर्तन जैसे मुद्दों पर सकारात्मक बातचीत हुई है।

संक्रमण बढ़ने के कारण अमेरिका में फिर से मास्क पहनना अनिवार्य हुआ

वाशिंगटन, एएनआइ : अमेरिका में कोरोना संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। यहां मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण टीके की दोनों खुराक लगे लोगों के लिए भी मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। इधर ओलिंपिक के दौरान जापान की राजधानी टोक्यो में इमरजेंसी लागू होने के बाद भी कोरोना के रिकार्ड मरीज मिल रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 3177 नए मामले सामने आए हैं।

अमेरिका में सेंटर फार डिजीज कंट्रोल एंड प्रीवेंशन (सीडीसी) ने डेल्टा वैरिएंट के कारण मरीजों में तेजी से हो रही वृद्धि के कारण मास्क लगाने की अनिवार्यता फिर शुरू कर दी गई है। सीडीसी की गाइडलाइन के अनुसार अब इनडोर में वैक्सीन लगे लोगों को भी मास्क लगाना होगा। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि जिन स्थानों पर संक्रमण की गति तेज है, उन स्थानों पर यात्रा के दौरान वह भी मास्क का प्रयोग करेंगे। अमेरिकी जनता से भी उन्होंने मास्क पहनने की अपील की है।

एपी के अनुसार सीडीसी के निदेशक रोशेल वालेंस्की ने कहा है कि वैज्ञानिक विश्लेषण में डेल्टा वैरिएंट से आने वाले मरीजों के अध्ययन चिंताजनक हैं।

- ओलिंपिक खेलों के दौरान टोक्यो में कोरोना के रिकार्ड मरीज
- डब्ल्यूएचओ ने कहा, संक्रमण में आठ फीसद, मौत में 21 फीसद की वृद्धि



जापान की युवाओं से अपील : जापान ने कोरोना का प्रसार रोकने में युवाओं से सहयोग मांगा है। सरकारी प्रवक्ता युकियो कोडके ने कहा, ओलिंपिक के दौरान संक्रमण रोकने में युवा मदद करें और भीड़भाड़ से बचें। टोक्यो में रेलवे स्टेशन पर मास्क पहने युवतियां। एपी

डब्ल्यूएचओ ने किया सावधान

एपी के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कहा है कि कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। पिछले सप्ताह में वैश्विक स्तर पर कोरोना संक्रमण में आठ फीसद की वृद्धि हुई है। मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले सप्ताह इस आंकड़े में भी 21 फीसद की वृद्धि हुई है।

आस्ट्रेलिया

बढ़ते संक्रमण के कारण सिडनी शहर में चार सप्ताह का लाकडाउन बढ़ा दिया गया है।

अमेरिका में वर्तमान में औसतन 57 हजार नए मरीज रोजाना आ रहे हैं।

सीडीसी के पूर्व निदेशक टाम फ्रिडेन ने सीएनएन से आशंका जताई कि आने वाले हफ्तों में दो लाख मरीज प्रतिदिन हो सकते हैं। एपी के अनुसार, ओलिंपिक खेलों के दौरान टोक्यो में कोरोना मरीजों की रिकार्ड संख्या दर्ज हो रही है। खेलों के शुरू होने के बाद अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा 3177 नए मामले आए हैं। विगत दिवस इन मरीजों की संख्या 2848 थी। टोक्यो में खिलाड़ियों को संक्रमण से बचाने के लिए इमरजेंसी लगी हुई है।

जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने जनता से घर से बिना कार्य न निकलने की अपील की है। विशेषज्ञों के अनुसार किसी भी खिलाड़ी के जनता से संक्रमित होने के कोई साक्ष्य नहीं हैं।

बांग्लादेश में जमात-ए-इस्लामी के 19 आतंकी गिरफ्तार

ढाका, आइएएनएस : बांग्लादेश के चिटोग्राम शहर से पुलिस ने आतंकी संगठन जमात-ए-इस्लामी और उसकी छात्र इकाई इस्लामी छात्र शिविर के 19 आतंकियों को गिरफ्तार किया है।

बांग्लादेश की पुलिस के अनुसार सोमवार की रात को अदुरपारा की मजार गली में स्थित रंगुनिया बिल्डिंग के एक घर से यह गिरफ्तारियां हुईं। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, आतंकियों ने कई संगठनों को बांग्लादेश की सरकार को अपदस्थ करने के लिए भड़काया था। इसके साथ ही उन्होंने ढाका-चिटगांव और कोक्स बाजार-चिटगांव हाईवे पर कई महत्वपूर्ण स्थानों और सरकारी संस्थानों को तबाह करने का भी प्रयास किया है।

पुलिस को खुफिया जानकारी मिली है कि विभिन्न स्थानों पर ऐसी गुपचुप गतिविधियां चल रही हैं। खासकर वार्ड आधारित जगहों पर युद्ध अपराध से जुड़े आतंकी इस्लाम के नाम पर अपनी साजिशों को अंजाम दे रहे हैं और निर्दोष लोगों को ब्लैकमेल करके अपना काम करा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने उदारवादी आवामी लीग सरकार और 1971 में जमात-ए-इस्लामी के युद्ध अपराधियों जैसे मतुर रहमान निजामी, अब्दुल कादेर मोल्लाह आदि के फांसी पर चढ़ाए जाने का विरोध करने की साजिशों से भी पर्दा हटाया है।

पड़ोस में आतंक
- पुलिस की छापेमारी के दौरान 15 अन्य आतंकी फरार, तलाश जारी
- सरकार को अपदस्थ करने के लिए रची जा रही थी साजिश

चंदगांव पुलिस स्टेशन के जांच अधिकारी राजेश बरुआ ने बताया कि एक खुफिया जानकारी के आधार पर रंगुनिया बिल्डिंग के एक मकान पर छापेमारी की गई थी। इस दौरान 15 अन्य आतंकी भागने में कामयाब हो गए। उनकी धरपकड़ के प्रयास जारी हैं।

चिटगांव उत्तर के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अबु बकर सिद्दीकी ने कहा, हसन मुहम्मद वासिन और जमात के उत्तर इकाई के प्रमुख आमिर समेत कुल 19 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। जमात के महासचिव रफीकुलइस्लाम और मुहम्मद इस्कंदर को एक बैठक में साजिश रचते हुए गिरफ्तार किया गया है। कुछ किताबें और फिरौती वसूलने की कुछ रसीदों की किताबें भी जब्त की गई हैं।

बलूचिस्तान में पांच लाख लोग भुखमरी के कगार पर

न्यूयार्क, एएनआइः पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भुखमरी के हालात हैं। यहां मौसम की मार, पानी की कमी, कोरोना महामारी और टिड्डियों के हमलों ने स्थितियां बिगाड़ दी हैं। सरकार की बेरुखी ने लाखों लोगों का संकट और बढ़ा दिया है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार यहां पांच लाख लोगों के सामने खाने का संकट है। एक लाख लोग ऐसे हैं, जिनका जीवन बचाने की तत्काल आवश्यकता है।

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) कार्यालय के मानवीय सहायता का समन्वय देखने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि खाद्य आपातकाल होने के साथ ही पानी का भीषण संकट पैदा हो रहा है। मौसम विभाग ने भी पूर्वानुमान लगाया है कि साल के अंत में दक्षिण-पश्चिम बलूचिस्तान, ईरान के सीमावर्ती क्षेत्र और अफगानिस्तान में सूखे जैसे स्थिति हो सकती है। अक्टूबर 2020 से मई 2021 तक औसत वर्षा का स्तर बहुत ही निचले स्तर पर पहुंच गया है। बलूचिस्तान के दक्षिणी जिलों के साथ ही 12 में से छह मध्य के जिले सूखे से प्रभावित हैं। इन सभी स्थानों पर निकट भविष्य में हालत सुधरती दिखाई नहीं दे रही है। उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में नागरिक सुविधाओं का अभाव है। आए दिन स्थानीय लोग बुनियादी जरूरतों की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते रहते हैं।

चीनी अपील पर मोरक्को में उइगर नेता गिरफ्तार

रबात, एपी : मोरक्को ने इंटरपोल द्वारा जारी रेड कार्नर नोटिस के आधार पर निर्वासन में रह रहे एक उइगर नेता यिदिरेसी एशान को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी चीन के अनुरोध पर की गई है। मोरक्को पुलिस और चीन द्वारा हिरासत में लिए लोगों पर नजर रखने वाले एक अधिकार समूह ने यह जानकारी दी है। कार्यकर्ताओं को डर है कि यिदिरेसी को चीन प्रत्यर्पित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है तथा चीन के अपनी सीमाओं के बाहर असंतुष्टों पर कार्रवाई करने के वृहद अभियान का हिस्सा है।

मोरक्को के राष्ट्रीय सुरक्षा महानिदेशालय ने कहा है कि एक चीनी नागरिक को इस्तांबुल से 20 जुलाई को कासाब्लांका के एक हवाई अड्डे पर उतरने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। महानिदेशालय ने कहा कि इंटरपोल ने आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल एक संगठन से उसके जुड़े होने के संदेह में रेड कार्नर नोटिस जारी कर रखा था। उन्होंने कहा कि इस नोटिस का मतलब है कि इंटरपोल की सबसे ज्यादा वांछित संदिग्धों की सूची। उसने बताया कि इंटरपोल ने चीन के अनुरोध पर यह नोटिस जारी किया था जिसने कार्यकर्ता के प्रत्यर्पण की मांग की है।

यिदिरेसी एशान के मित्र और सहकर्मी अब्दुवेली अयुप ने बताया कि कम्प्यूटर इंजीनियर और तीन बच्चों के पिता एशान (33) 2012 से तुर्की में रह रहा है, जहां उसने एक वेब डिजाइनर और कार्यकर्ता के तौर पर काम किया। उसके पास वहां के निवासी दस्तावेज भी हैं। एशान ने उइगर समुदाय के आनलाइन अखबार पर भी काम किया और चीन के शिनजियांग प्रांत में अत्याचारों के सुबूत जुटाने में कार्यकर्ताओं की मदद की।

चीन सरकार की निंदा पड़ी भारी, अरबपति व्यापारी सुन दावू को 18 साल की कैद

बीजिंग, रायटर : चीन की क्रूर सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का खामियाजा एक और अरबपति व्यापारी को भुगतना पड़ा है। शी जिनपिंग सरकार ने नामी कृषि कंपनी दावू एग्रीकल्चर ग्रुप के चेयरमैन सुन दावू को 18 साल जेल की सजा सुनाई है। उनके खिलाफ 'मुसीबत पैदा करने' और 'सरकारी संस्थानों' पर हमले के लिए 'भीड़ जुटाने' जैसे कई आरोप लगाए गए हैं। मालूम हो कि दावू से पहले अलीबाबा ग्रुप के संस्थापक जैक मा समेत कई रईस व्यापारियों को सरकार की आलोचना में मुंह खोलना भारी पड़ चुका है। इस तरह चीन सरकार आलोचकों का दमन कर रही है।

सुन दावू को मुखर व्यापारी और मूलभूत अधिकारों के प्रवक्ता के रूप में जाना जाता है। उनके खिलाफ ट्रायल गुपचुप तरीके से गाओबीदियन में चलाया गया। दावू पर आरोप है कि उन्होंने भीड़ को सरकारी इकाइयों पर हमले के लिए जुटाया, सरकारी प्रशासन में अवरोध पैदा किया, झगड़े और मुश्किलें पैदा कीं। उन्हें 18 साल जेल की सजा सुनाई गई है और 3.5 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगा है।

चीनी तानाशाही
- सुन दावू पर भीड़ को सरकारी इकाइयों पर हमले के लिए जुटाने का आरोप
- जेल के साथ ही 3.5 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगा है

वकीलों की तारीफ की थी

दरअसल, दावू ने सरकार के कानूनी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई के बीच वकीलों की तारीफ की थी। इसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। दावू के कर्मचारियों ने अगस्त 2020 में एक सरकारी कंपनी को उसकी इमारत गिराने से रोका था। इसके बाद दावू के अलावा 20 और लोगों को हिरासत में लिया गया था और उनके खिलाफ भी ट्रायल हुआ है और उन्हें दोषी करार दिया गया है।

लोगों का भारी समर्थन था

सुन के खिलाफ साल 2003 में अवैध फंड जुटाने का आरोप लगा था जिसके बाद उन्हें आम जनता का भारी समर्थन मिला था। इसके बाद से सुन ऐसे वकीलों की तारीफ करते थे जो आम लोगों की मदद करते हों क्योंकि सरकार ऐसे वकीलों को जेल में डाल देती थी। सुन के 2003 के केस के वकील भी फरवरी 2020 में गायब हो गए और उनके साथियों का कहना है कि उनके खिलाफ देश से विश्वासघात का आरोप लगा था।

परमाणु वार्ता रुकने पर खामनेई ने की अमेरिका की आलोचना

तेहरान, एपी : ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामनेई ने तेहरान के मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय प्रभाव तथा नाभिकीय मुद्दों पर वियना में हुई बैठक के बेनतीजा होने पर बुधवार को अमेरिका को अकड़ू करार दिया है। अयातुल्ला खामनेई का बयान ऐसे समय आया है जब उनके समर्थन से इब्राहिम रयसी अगले सप्ताह राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे हैं और नाभिकीय समझौते पर वियना में बातचीत रुक गई है।

हालांकि रयसी ने कहा है कि वह समझौते पर बातचीत दोबारा शुरू करना चाहते हैं और आर्थिक प्रतिबंध हटाने के बदले यूरेनियम संवर्धन को सीमित करने के लिए तैयार हैं लेकिन खामनेई ने अपने बयान में और अधिक कड़ा रवैया अपनाने को कहा है।

दोनों नेताओं ने 2015 में हुए परमाणु समझौते के दौरान अपनाए गए रवैये के लिए निवर्तमान राष्ट्रपति हसन रूहानी के आठ साल के कार्यकाल को बचकाना करार दिया है।


अयातुल्ला खामनेई

खामनेई ने वियना में हुई बैठक के बेनतीजा रहने पर बुधवार को अमेरिका को अकड़ू करार दिया

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामनेई सरकारी टेलीविजन चैनल पर कहा, 'आपके अनुभव को दूसरों को अपनाना चाहिए। यह अनुभव पश्चिमी देशों का अविश्वास है।' उन्होंने कहा, 'इस सरकार ने यह दिखाया है कि पश्चिमी देशों में विश्वास करना व्यर्थ है। पश्चिमी देश हमारी मदद नहीं करते, उन्हें जहां मौका मिलता है, वे हमला करते हैं।'

भयंकर गर्मी से गिरते-पड़ते क्वार्टर फाइनल में पहुंचे मेदवेदेव


शाट लगाते मेदवेदेव • एएफपी

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली : टोक्यो ओलिंपिक में गर्मी से खिलाड़ियों का बुरा हाल है। रूसी ओलिंपिक समिति (आरओसी) की तरफ से खेलने वाले टेनिस खिलाड़ी डेनिल मेदवेदेव बुधवार को अपने मैच के दौरान करीब 31 डिग्री सेल्सियस तामपान में जूझते हुए क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। हालांकि वहां पर तपन 37 डिग्री सेल्सियस की तरह महसूस हो रही थी। मैच के दौरान उन्होंने कहा कि इतनी गर्मी में तो मैं मर भी सकता हूं।

टेनिस की पुरुष सिंगल्स स्पर्धा में मेदवेदेव का सामना इटली के फाबियो फोगनिनी के साथ था। दिन में खेले जाने वाले इस मैच में मेदवेदेव कई बार मैदान में गिरते-पड़ते और टेनिस रैकेट के सहारे आराम करते दिखे। उन्होंने अपने मैच के दौरान दो मेडिकल टाइम आउट लिए और एक बार उनके ट्रेनर को कोर्ट पर आना पड़ा। हालांकि दूसरी वरीयता प्राप्त मेदवेदेव ने मैदान नहीं छोड़ा और फोगनिनी को 6-2, 3-6, 6-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मेदवेदेव और फोगनिनी को दूसरे और तीसरे सेट के बीच में 10 मिनट के लिए कोर्ट छोड़ने की इजाजत दी गई थी। बेहद तेज गर्मी का नियम लागू करके ऐसा किया गया। मेदवेदेव पदक दौर में जगह बनाने के लिए स्पेन के छठी वरीय पाब्लो कारेनो बुस्ता से भिड़ेंगे, जिन्होंने जर्मनी के डोमिनिक कोएफर को 7-6, 6-3 से हराया।

> मैं मैच खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं मर भी सकता हूं। अगर मैं मर गया तो क्या आप (अंपायर) जिम्मेदार होंगे?
> **डेनिल मेदवेदेव,** टेनिस खिलाड़ी, आरओसी

पत्रकार के आरओसी टीम को धोखेबाज बताने पर भड़के मेदवेदेव : मेदवेदेव ने मैच के बाद पत्रकार के सवाल पर आपत्ति जताई, जिसमें उसने पूछा कि क्या रूसी खिलाड़ी इन खेलों में धोखेबाजी का कलंक लेकर आए हैं। मेदवेदेव ने कहा कि अपनी जिंदगी में मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा और आपको खुद भी शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए।'

मैचों का बदला समय : मेदवेदेव को जूझते हुए देखने के बाद अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने अब आगामी मैचों का समय बदल दिया है। आइटीएफ ने कहा कि मैच स्थानीय समयानुसार गुरुवार से सुबह 11 बजे के बजाय दोपहर तीन बजे से शुरू होंगे।

नोवाक भी क्वार्टर फाइनल में

विश्व के नंबर एक टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविक ने आसानी से क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। उन्होंने आइटीएफ के मैच बदलने के फैसले का स्वागत किया और कहा कि इससे राहत मिली है। जोकोविक ने अपने मैच में स्पेन के एलेजांद्रो डेविडोविक फोकिना को आसानी से सीधे सेटों में 6-3, 6-1 से हराया। इसके अलावा पहली बार मिक्स्ड डबल्स में नीना स्टोजानोविक के साथ खेलते हुए भी उन्होंने ब्राजीलियाई जोड़ी मार्सेलो मेलो और लुइसा स्टेफनी को 6-3, 6-4 से हराया।

चीन ने बनाया विश्व रिकार्ड

टोक्यो : चीनी महिला नौकायन टीम (चेन युनक्सिया, झांग लिंग, लियू यांग और कुई शियाओतोंग) की नाव ने क्वाड्रपोल स्कल्स में 6.13 मिनट में स्पर्धा पूरी करते हुए नीदरलैंड्स के इस स्पर्धा में बनाए गए 2014 के रिकार्ड को दो सेकेंड से तोड़ा। चीनी नाव के छह सेकेंड बाद पोलैंड ने स्पर्धा का अंत करते हुए रजत पदक जीता, जबकि आस्ट्रेलियाई टीम ने कांस्य पदक जीता।

अपशब्द बोल बैठीं कायली : आस्ट्रेलियाई तैराक कायली मैककेन ने 57.47 सेकेंड के नए ओलिंपिक रिकार्ड समय के साथ 100 मीटर बैकस्ट्रोक स्पर्धा का स्वर्ण जीता। हालांकि जीत के बाद जब उनसे सवाल पूछा गया तो उनके मुंह से अपशब्द निकल गए जिसके लिए उन्होंने माफी मांगी।

सिंधू प्री-क्वार्टर फाइनल में

पीवी ने हांगकांग की एनवाई चियुंग को सीधे गेमों में किया पराजित



टोक्यो, प्रेट्र : गत विश्व चैंपियन भारत की पीवी सिंधू ने बुधवार को यहां ग्रुप-जे में हांगकांग की एनवाई चियुंग को हराकर टोक्यो ओलिंपिक की महिला सिंगल्स बैडमिंटन स्पर्धा के प्री-क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया, लेकिन पुरुष सिंगल्स खिलाड़ी बी साई प्रणीत लगातार दूसरा मैच हारकर बाहर हो गए। रियो ओलिंपिक की रजत पदक विजेता सिंधू ने दुनिया की 34वें नंबर की खिलाड़ी चियुंग को 35 मिनट चले मुकाबले में 21-9, 21-16 से हराकर ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया। सिंधू की चियुंग के खिलाफ छह मुकाबलों में यह छठी जीत है।

ब्लिचफेल्ट के खिलाफ भी सिंधू मजबूत : दुनिया की सातवें नंबर की खिलाड़ी सिंधू प्री क्वार्टर फाइनल में ग्रुप-आई में शीर्ष पर रहने वाली डेनमार्क की दुनिया की 12वें नंबर की खिलाड़ी मिया ब्लिचफेल्ट से भिड़ेंगी। सिंधू का ब्लिचफेल्ट के खिलाफ जीत-हार का रिकार्ड 4-1 है। डेनमार्क की खिलाड़ी ने सिंधू के खिलाफ एकमात्र जीत इस साल थाइलैंड ओपन में दर्ज की थी।

पदक तालिका

	स्वर्ण	रजत	कांस्य	कुल
जापान	12	4	5	21
चीन	11	5	9	25
अमेरिका	10	11	9	30
आरओसी	7	8	5	20
आस्ट्रेलिया	6	1	9	16
ग्रेट ब्रिटेन	5	6	5	16
द. कोरिया	4	2	5	11
जर्मनी	3	2	5	10
फ्रांस	3	2	3	8
नीदरलैंड्स	2	6	3	11
भारत	0	1	0	1

नोट : भारत तालिका में 42वें स्थान पर है। आरओसी (रूसी ओलिंपिक समिति)

अपने खेल से सिंधू ने किया परेशान : सिंधू ने अपने विविध शाट और गति में परिवर्तन करने की काबिलियत से चियुंग को पूरे कोर्ट पर दौड़ाकर परेशान किया। चियुंग ने अपने क्रास कोर्ट रिटर्न ने कुछ अंक हासिल किए, लेकिन हांगकांग की खिलाड़ी ने काफी सहज गलतियां की जिससे वह सिंधू पर दबाव बनाने में विफल रही। सिंधू ने अच्छी शुरुआत करते हुए स्कोर 6-2 किया और फिर 10-3 की बढ़त हासिल की। वह ब्रेक के समय 11-5 से आगे थी। ब्रेक के बाद सिंधू ने दबदबा बनाते हुए अपनी बढ़त को 20-9 किया और चियुंग के नेट पर शाट मारने के साथ पहला गेम जीत लिया। चियुंग ने दूसरे गेम में बेहतर खेल दिखाया। उन्होंने सिंधू को रैली में उलझाया और दोनों खिलाड़ी 8-8 से बराबर चल रही थी। सिंधू ने इस दौरान चियुंग के शाट को परखने में भी गलती की और फिर बाहर शाट मारकर ब्रेक के समय हांगकांग की खिलाड़ी को एक अंक की बढ़त दे दी। चियुंग ने दबाव डालने का प्रयास किया, लेकिन सिंधू ने दमदार स्मैश और बेहतर शाट के साथ 19-14 की बढ़त बना ली। सिंधू को छह मैच प्वाइंट मिले। उन्होंने एक शाट बाहर मारा और एक नेट पर उलझाया, लेकिन फिर स्मैश के साथ मैच जीत लिया।

> दूसरे गेम में मैंने लय हासिल की और फिर जीत दर्ज की। यह काफी तेज मुकाबला था और मैंने कुछ गलतियां भी की। मैंने अपनी रणनीति में बदलाव किया और चीजों पर नियंत्रण बनाने में सफल रही। बड़े मुकाबले से पहले इस तरह की परीक्षा महत्वपूर्ण होती है।
> **पीवी सिंधू**

प्रणीत का खराब प्रदर्शन जारी : पुरुष वर्ग में प्रणीत सर्वश्रेष्ठ खेल नहीं दिखा पाए और नीदरलैंड्स के मार्क कालजोव से 40 मिनट तक चले मैच में सीधे गेम में 14-21, 14-21 से हार गए। यह उनकी ग्रुप-डी में दूसरी हार थी। कालजोव ग्रुप में शीर्ष पर रहकर नाकआउट दौर में पहुंचे। केवल ग्रुप का विजेता खिलाड़ी ही आगे बढ़ता है।

मानसिक बीमारी के चलते गत चैंपियन जिम्नास्ट बाइल्स ओलिंपिक से हटीं

• सिमोन लगातार खराब प्रदर्शन से दुखी थीं

• जेड कैरी उनकी जगह अमेरिकी टीम में शामिल

टोक्यो, एपी : रियो ओलिंपिक की जिम्नास्टिक्स स्पर्धा में चार स्वर्ण पदक जीतने वालीं सिमोन बाइल्स ने अब टोक्यो ओलिंपिक से पूरी तरह अपना नाम वापस ले लिया है। सिमोन ने यह फैसला अपनी मानसिक बीमारी के चलते किया, जिसके बाद पूरे विश्व में उनके इस फैसले की सराहना भी हो रही है। वहीं क्वालीफाइंग में नौवें स्थान पर रहने वालीं जेड कैरी टीम में बाइल्स की जगह लेंगी।

सिमोन ने मंगलवार को जिम्नास्टिक्स की टीम स्पर्धा से बीच में ही अपना नाम वापस ले लिया था, जिसके चलते उनकी टीम अमेरिका को रजत पदक से संतोष करना पड़ा और रूसी ओलिंपिक समिति (आरओसी) ने स्वर्ण पदक पर अपना कब्जा जमाया था। इस स्पर्धा में बाइल्स ने वाल्ट में अपने जीवन का सबसे न्यूनतम स्कोर 13.766 का स्कोर किया। इसके तुरंत बाद उन्होंने अपना नाम वापस लेते हुए कहा, 'मुझे अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना है और शरीर की रक्षा करनी है।' सिमोन के इस फैसले की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी तारीफ भी हो रही है। अमेरिकी ओलिंपिक और पैरालंपिक समिति की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सारा हर्शलैंड ने कहा, 'हमें आप पर गर्व है।' बाइल्स ओलिंपिक और विश्व कप में 30 बार चैंपियन रही हैं और उन्हें ओलिंपिक इतिहास की सबसे अधिक पदक जीतने वाली एथलीट (पुरुष या महिला) बनने के लिए टोक्यो में चार पदक जीतने थे।


सिमोन बाइल्स • एएफपी

मानसिक बीमारी से ग्रस्त खिलाड़ियों के लिए बनी हेल्पलाइन

टोक्यो, एपी : अंतरराष्ट्रीय ओलिंपिक समिति (आइओसी) मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहे खिलाड़ियों के लिए 70 भाषाओं में हेल्पलाइन चला रही है। आइओसी के प्रवक्ता मार्क एडम्स ने कहा कि इसे मानसिक तौर पर फिट रखने के लिए हेल्पलाइन नाम दिया गया है और यह चौबीसों घंटे काम करती है। यह हेल्पलाइन ओलिंपिक खेल समाप्त होने के बाद भी तीन महीने तक अपनी सेवाएं देती रहेगी।

100 साल बाद तैराकी में ब्रिटेन ने रचा इतिहास

टोक्यो : 100 साल से भी अधिक समय बाद ब्रिटेन ने तैराकी प्रतियोगिता में रिले स्पर्धा का स्वर्ण जीता, जबकि अमेरिकी टीम पोडियम पर भी जगह नहीं बना पाई। ब्रिटेन ने दबदबा बनाते हुए पुरुष चार गुणा 200 मीटर फ्रीस्टाइल में जीत दर्ज की। टीम में 200 मीटर फ्रीस्टाइल के स्वर्ण पदक विजेता टाम डीन, 200 मीटर के रजत पदक विजेता डंकन स्काट, तीन बार के ओलिंपिक पदक विजेता जेम्स गाय और 18 साल के मैथ्यू रिचर्ड्स शामिल थे। ब्रिटेन ने छह मिनट 58.58 सेकेंड से खिताब जीता, लेकिन मामूली अंतर से विश्व रिकार्ड बनाने से चूक गई। अमेरिका ने रोम में 2009 में विश्व चैंपियनशिप में छह मिनट 58.55 सेकेंड का समय लिया था। अमेरिका अपने गौरवपूर्ण इतिहास में रिले में हिस्सा लेते हुए पहली बार पदक जीतने में विफल रही।

पावरफुल पूजा रानी पदक से एक कदम दूर

टोक्यो : भारतीय मुक्केबाज पूजा रानी (75 किग्रा) ने बुधवार को यहां ओलिंपिक खेलों में पदार्पण करते हुए शुरुआती मुकाबले में अल्जीरिया की इचरक चाएब को 5-0 से पराजित कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगर वह यह मुकाबला जीत लेती हैं तो उनका पदक पक्का हो जाएगा। मुक्केबाजी के नियमों के अनुसार सेमीफाइनल में पहुंचने पर ही पदक पक्का हो जाता है। मुक्केबाजी में दो खिलाड़ियों को कांस्य पदक दिया जाता है।

30 साल की भारतीय मुक्केबाजी ने प्री-क्वार्टर फाइनल में पूरे मुकाबले के दौरान अपने से 10 साल जूनियर प्रतिद्वंद्वी पर दबदबा बनाए रखा। दो बार की एशियाई चैंपियन पूजा ने दाहिने हाथ से दमदार मुक्कों से नियंत्रण बनाए रखा और उन्हें चाएब के रिंग में संतुलन की कमी का भी काफी फायदा मिला। तीनों राउंड में रानी का दबदबा रहा जबकि चाएब भी अपना पहला ओलिंपिक खेल रही थीं लेकिन, वह मुक्के सही जगह नहीं जड़ पा रही थीं। रानी ने विपक्षी से दूरी बनाकर चतुराई भरा प्रदर्शन किया। रानी ने पूरी बाउट के दौरान जवाबी हमले किए जबकि चाएब भी दमदार मुक्के लगाने का प्रयास कर रही थीं लेकिन, वे अपने लक्ष्य से चूकते रहे। रानी का ओलिंपिक का सफर काफी मुश्किलों से भरा रहा है। वह कंधे की चोट से जूझती रहीं जिससे उनका करियर खत्म होने का भी डर बना हुआ था। उनका हाथ भी जल गया था। वित्तीय सहयोग की कमी के बावजूद वह यहां तक पहुंची हैं। उनके पिता पुलिस अधिकारी हैं जो उन्हें इस खेल में नहीं आने देना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि मुक्केबाजी आक्रामक लोगों के लिए ही है। उनके ऊपर पूरे देश की उम्मीद है। वह जीतकर उसे पूरा कर सकती हैं।


पूजा रानी • एएफपी

दीपिका तीसरे दौर में

टोक्यो : दीपिका कुमारी ने अपेक्षानुरूप प्रदर्शन करते हुए ओलिंपिक की तीरंदाजी प्रतियोगिता की व्यक्तिगत स्पर्धा के तीसरे दौर में जगह बनाई, लेकिन तरुणदीप राय और प्रवीण जाधव दूसरे दौर से आगे बढ़ने में नाकाम रहे। विश्व की नंबर एक खिलाड़ी दीपिका को भी युमेनोशिमा पार्क पर चल रही हवाओं से सामंजस्य बैठाने में परेशानी हुई। उन्होंने महिला रिकर्व व्यक्तिगत वर्ग के पहले दौर में भूटान की कर्मा को 6-0 से हराया, लेकिन 24वीं वरीयता प्राप्त अमेरिकी जेनिफर मुसिनो फर्नांडिस से उन्हें कड़ी चुनौती मिली। दीपिका ने यह मैच 6-4 से जीता। दीपिका का यह ओलिंपिक खेलों में व्यक्तिगत वर्ग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इस अनुभवी भारतीय खिलाड़ी अमेरिका की 18 वर्षीय जेनिफर के खिलाफ सात अंक से शुरुआत की। इससे उन्हें पहला सेट 25-26 से गंवाना पड़ा, लेकिन अगले दो सेट में उन्होंने परफेक्ट-10 के तीन स्कोर बनाकर 28-25 और 27-25 से जीत दर्ज करके बढ़त बना दी। चौथे सेट में दीपिका का दूसरा तीर बुल्स आई से काफी दूर चला गया और उन्हें केवल छह अंक मिले। अमेरिकी तीरंदाज इसका फायदा उठाकर 25-24 से मुकाबले को बराबरी ला दिया। दीपिका को पांचवें सेट में जेनिफर की गलतियों का भी फायदा मिला जिसे इस भारतीय ने 26-25 से जीतकर मैच अपने नाम किया। इससे पहले दीपिका ने भूटान की कर्मा को हराया था। दीपिका ने पहले और दूसरे सेट में 26-23 के समान अंतर से जीत दर्ज की। दीपिका ने तीसरा सेट 27-24 से जीता।

राय और जाधव हुए विफल : पुरुष वर्ग में राय और जाधव दूसरे दौर से आगे नहीं बढ़ पाए। राय को अपने से कम रैंकिंग के खिलाड़ी इताय शैनी से शूट आफ में 5-6 से हार का सामना करना पड़ा जबकि जाधव अमेरिका के विश्व में नंबर एक ब्राडी एलिसन से 0-6 से हार गए। पुरुष व्यक्तिगत स्पर्धा में अनुभवी तीरंदाज अतानु दास गुरुवार को चीनी ताइपे के डेंग यू चेंग के खिलाफ एलिमिनेशन दौर की चुनौती पेश करेंगे।


दीपिका कुमारी • प्रेट्र

पीवी सिंधू • प्रेट्र

सीमा की चोट उभरी

भारतीय कुश्ती टीम के ओलिंपिक अभियान को पहलवान सीमा बिस्ला की चोट से तगड़ा झटका लग सकता है। सीमा बिस्ला (50 किग्रा) के साथ दो अन्य पहलवान अंशु मलिक (57 किग्रा) और सोनम मलिक (62 किग्रा) मंगलवार को टोक्यो पहुंची। जहां पहुंचते ही महिला पहलवान सीमा बिस्ला (50 किग्रा) ने शिकायत की है कि बुधवार को अभ्यास सत्र के दौरान उनकी गर्दन में चोट फिर से उभर आई है। चोट कितनी गंभीर है, इसका पता अगले सप्ताह से शुरू होने वाले सीमा के ओलिंपिक अभियान से चलेगा। इतना ही नहीं अगर चोट ज्यादा गंभीर हो जाती है तो ओलिंपिक में भाग लेने से भी वह पीछे हट सकती हैं।

दूसरी डोज के बिना ही टोक्यो पहुंचेंगे दीपक और रवि

अभिषेक त्रिपाठी • नई दिल्ली

> कोविशील्ड की पहली डोज के साथ ही दोनों पुरुष पहलवान ओलिंपिक में पहुंचेंगे

ओलिंपिक के लिए टोक्यो जाने वाले सभी भारतीय एथलीटों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगाने की बात कही गई थी लेकिन पुरुष फ्रीस्टाइल पहलवान रवि दहिया (57 किग्रा) और दीपक पूनिया (86 किग्रा) कोविशील्ड की सिर्फ एक डोज ही लेने के बाद टोक्यो ओलिंपिक में भाग लेने के लिए रवाना होंगे।

यह दोनों पहलवान (दीपक और रवि) बजरंग पूनिया (65 किग्रा) के साथ रूस के व्लादिकाव्काज शहर में अभ्यास कर रहे थे। जहां पर भारतीय अधिकारी इन्हें कोविशील्ड वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाने में विफल रहे। हालांकि बजरंग ने रूस जाने से पहले ही दोनों डोज लगवा लिए थे।

रूस ने इन दोनों पहलवानों के लिए स्पूतनिक वी वैक्सीन का प्रस्ताव रखा था, मगर भारतीय अधिकारियों ने यह कहकर मना कर दिया था कि वह मास्को में स्थित भारतीय दूतावास में कोविशील्ड की दूसरी डोज पहलवानों के लिए उपलब्ध करा देंगे। हालांकि, ऐसा नहीं हुआ और टोक्यो के लिए देश के 126 एथलीटों के दल में केवल यह दो पहलवान ही पूरी तरह से टीकाकरण के बिना ओलिंपिक में भाग लेंगे। दोनों ने भारत में कोविशील्ड की अपनी पहली डोज ली थी और वारसा (8-13 जून) में पोलिश ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट में भाग लेने के बाद पोलैंड में दूसरी डोज लेने के लिए तैयार थे। हालांकि बाद में, रवि और दीपक ने रूस के व्लादिकाव्काज शहर में अभ्यास की मांग की क्योंकि दोनों पहलवान अभ्यास के लिए वारसा में अपने स्तर का पहलवान नहीं ढूंढ़ पाए थे। पोलैंड की टीकाकरण नीति ने पहलवानों के लिए कोविशील्ड का दूसरा डोज लेना मुश्किल बना दिया था। हालांकि इसके बाद रूस में स्पूतनिक वैक्सीन उपलब्ध थी।

इस महीने की शुरुआत में, निशानेबाज सौरभ चौधरी, राही सरनोबत और दीपक कुमार को जगरेब में वैक्सीन की दूसरी डोज मिली थी। स्कीट शूटर मेराज अहमद खान, जिन्हें एक महीने पहले तक पहली खुराक नहीं मिली थी, उन्हें भी फिर जगरेब में जानसन एंड जानसन वैक्सीन का डोज दिया गया था। भारतीय ओलिंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा ने इस महीने की शुरुआत में दावा किया था कि टोक्यो पहुंचने से पहले सभी भारतीय एथलीटों को पूरी तरह से टीका लग जाएगा। भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) ने भी कहा था कि टोक्यो ओलिंपिक आयोजक समिति ने एथलीटों और अधिकारियों के लिए कोविड-19 टीकाकरण अनिवार्य नहीं किया है। इसके बावजूद भारत ने अपने दल का टीकाकरण प्राथमिकता के आधार पर करने का फैसला किया है।

महिला हाकी टीम की हार की हैट्रिक

टोक्यो, प्रेट्र : भारतीय महिला हाकी टीम को दूसरे हाफ में बेहतर प्रदर्शन के बावजूद धीमी शुरुआत का खामियाजा ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ 1-4 की हार के साथ भुगतना पड़ा जो टोक्यो ओलिंपिक की महिला हाकी स्पर्धा के पूल-ए में उसकी लगातार तीसरी हार है। गत चैंपियन ग्रेट ब्रिटेन की ओर से हेना मार्टिन (दूसरे और 19वें मिनट) ने दो जबकि लिली आउस्ले (41वें मिनट) और ग्रेस बाल्सडन (57वें मिनट) ने एक-एक गोल दागा। दुनिया की 11वें नंबर की टीम भारत की ओर से एकमात्र गोल शर्मिला देवी (23वें मिनट) ने किया।

भारत को इससे पहले विश्व में नंबर एक नीदरलैंड्स के खिलाफ 1-5 और जर्मनी के खिलाफ 0-2 से हार झेलनी पड़ी थी। भारत अपने अगले मुकाबले में 30 जुलाई को आयरलैंड से भिड़ेगा। अब उनका पदक जीतना नामुमकिन है।

गणपति और वरुण की जोड़ी ने भी किया निराश : सेलर के गणपति और वरुण ठक्कर की भारतीय जोड़ी ओलिंपिक की पुरुषों की स्किफ 49अर सेलिंग (पाल नौकायान) स्पर्धा की चार रेस के बाद 18वें स्थान पर रहीं। भारतीय जोड़ी बुधवार को हुई रेस में 18वें, 17वें और 19वें स्थान पर रही। मंगलवार को इनोशिमा याट हार्बर में 19 टीम की पहली रेस में वे 18वें स्थान पर रहे थे। प्रतियोगिता में आठ और रेस तथा एक पदक दौर बचा है। मंगलवार को विष्णु सरवनन और नेत्रा कुमानन छह रेस के बाद अपनी स्पर्धाओं में क्रमशः 22वें और 33वें स्थान पर रहे थे। सरवनन पुरुष लेजर स्पर्धा में पांचवीं और छठी रेस में क्रमशः 23वें और 22वें स्थान पर रहे थे जबकि नेत्रा महिलाओं की लेजर रेडियल स्पर्धा की दो रेस में क्रमशः 32वें और 38वें स्थान पर रही थीं। प्रत्येक स्पर्धाओं में रेस की सीरीज होती है। प्रत्येक रेस में स्थान के आधार पर अंक दिए जाते हैं। रेस में पहले स्थान पर रहने वाले को एक जबकि दूसरे स्थान पर रहने वाले को दो अंक मिलते हैं, बाकी प्रतिस्पर्धियों को भी अंक इसी प्रकार दिए जाते हैं।

फाइनल में नहीं पहुंच पाए अर्जुन और अरविंद

टोक्यो, प्रेट्र : भारतीय नौकाचालक अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह यहां दूसरे सेमीफाइनल में छठे और आखिरी स्थान पर रहकर नौकायन के पुरुषों के लाइटवेट डबल स्कल्स के फाइनल में जगह बनाने में नाकाम रहे। अर्जुन और अरविंद ने सी फोरेस्ट वाटरवे में छह टीमों के दूसरे सेमीफाइनल में छह मिनट 24.41 सेकेंड का समय लिया और यह भारतीय जोड़ी अंतिम स्थान पर रही। दोनों सेमीफाइनल में चोटी पर रहने वाली तीन-तीन टीमें फाइनल के लिए क्वालीफाई करती हैं। अर्जुन और अरविंद का सेमीफाइनल में पहुंचना ओलिंपिक में भारतीयों नौकाचालकों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।

भारत के आज के मैच

तीरंदाजी (व्यक्तिगत स्पर्धा)
खिलाड़ी : अतानु दास, अंतिम-32 एलिमिनेशन, सुबह 7:30 बजे से

बैडमिंटन : महिला सिंगल्स, अंतिम-16, सुबह 6:15 बजे से
खिलाड़ी : पीवी सिंधू

मुक्केबाजी : पुरुष, अंतिम-16, सुबह 8:45 बजे से
खिलाड़ी : सतीश कुमार

• महिला, अंतिम-16, दोपहर 3:35 बजे से, **खिलाड़ी :** एमसी मेरी कोम

घुड़सवारी : इवेंटिंग फर्स्ट हार्स इंस्पेक्शन, सुबह 6:00 बजे से
खिलाड़ी : फवाद मिर्जा

गोल्फ : पुरुष व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले राउंड, दोपहर 1:04 बजे से
खिलाड़ी : अनिर्बान लाहिड़ी और उदयन माने

हाकी : पुरुष टीम, पूल-ए, सुबह 6:00 बजे से, बनाम अर्जेंटीना

रोइंग : पुरुष लाइटवेट डबल्स स्कल्स फाइनल बी (रैंकिंग राउंड), सुबह 5:20 बजे से
खिलाड़ी : अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह

सेलिंग : पुरुष स्किफ 49ईआर रेस 5 व 6, सुबह 8:35 बजे से
खिलाड़ी : केसी गणपति

• पुरुष लेसर रेस 7 व 8, सुबह 8:35 बजे से
खिलाड़ी : विष्णु सरवनन

• महिला लेसर रेडियल रेस 7 व 8, सुबह 8:45 बजे से
खिलाड़ी : नेत्रा कुमानन

निशानेबाजी : महिला 25 मीटर पिस्टल क्वालीफिकेशन, सुबह 5:30 बजे से **खिलाड़ी :** राही सरनोबत और मनु भाकर

प्रसारण : सोनी नेटवर्क पर

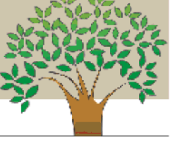
निशानेबाजी में बदल सकते हैं हालात


विजय कुमार
कलम से

भारतीय निशानेबाजी दल बेहतरीन तैयारियों के साथ ओलिंपिक खेलों में हिस्सा लेने के लिए टोक्यो गया था लेकिन ये हम सभी के लिए दुख की बात है कि जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तभी हम अपेक्षाओं के अनुसार अपनी योजना को लागू करने में विफल रहे। अब भी कुछ स्पर्धा बाकी हैं और मुझे उम्मीद है कि ये सभी छह निशानेबाज योजना पर अमल कर हालात बदल सकेंगे। मेरी शुभकामनाएं पूरी टीम के साथ हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि मनु भाकर 25 मीटर पिस्टल इवेंट में वापसी कर सकती हैं।

सौरभ चौधरी ने व्यक्तिगत क्वालीफाइंग स्पर्धा में शीर्ष पर रहकर शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन वह फाइनल में इसे जारी रखने में नाकाम साबित हुए। वह अभी काफी युवा हैं और जल्द ही सीख जाएंगे कि बड़े टूर्नामेंट में दबाव को कैसे काबू किया जाए। 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजों के खराब प्रदर्शन के बाद टीम पर दबाव पड़ गया। सबसे ज्यादा उम्मीदें दो मिक्स्ड टीम इवेंट में हिस्सा ले रही चार जोड़ियों से थी। ये इवेंट पहली बार ओलिंपिक खेलों में शामिल किए गए थे। ऐसे में भारतीयों के पास इसे भुनाने का अच्छा मौका था। काफी कुछ इस बात पर भी निर्भर करता है कि अपने देश के लिए कोटा सुरक्षित करने के बाद आप अपने इवेंट की तैयारी किस तरह करते हैं। यहां ये भी ध्यान देने वाली बात है कि एथलीटों को दबाव संभालने में कोचों का भी अहम योगदान होता है। बेशक हर कोई दबाव महसूस करता है। फिर चाहे वो युवा एथलीट हो या अनुभवी। जब निशानेबाज निशाने लगा रहा होता है तो कोच की भूमिका बड़ी हो जाती है। 2012 में जब मैं पहली स्टेज के बाद पांचवें नंबर पर था तब मेरे दिमाग में असंख्य विचार घूम रहे थे। कोच पावेल स्मिरनोव मेरा दिमाग हटाने के लिए मुझे जिम और गेम स्टेशंस ले गए। दूसरे दिन, दूसरी स्टेज से पहले कोच मुझे एक छोटी सी वॉक पर ले गए। इससे मुझे दबाव से निपटने में मदद मिली। तकनीकी इनपुट के अलावा कोच एथलीट को मानसिक तौर पर सहज कराने में भी अहम योगदान देता है। (टीसीएम)





मनोदशा

बचकर रहना होगा अस्वस्थ अभिमान से

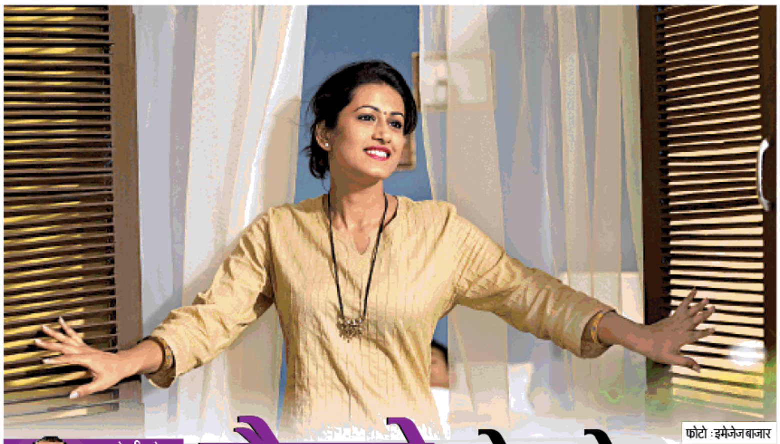


ओलिंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज भवानी देवी की जीत का सफर बेशक थम गया है, लेकिन उन्होंने अगले ओलिंपिक (2024) में वापसी के लिए तीव्र प्रतिबद्धता दिखाई है। अपनी हार से निराश होने के बजाय भवानी का यह दृढ़ संकल्प उनके आत्मसंयम एवं विश्वास को दर्शाता है। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे या सोचेंगे? वह अपनी धुन में रमी हुई हैं।

मनोचिकित्सकों के अनुसार, इसे स्वस्थ अभिमान कहेंगे। लेकिन जो लोग संशय में रहते हैं, हार या असफलता से शर्मसार महसूस करते हैं, जिन्हें अपनी क्षमताओं को लेकर अतिआत्मविश्वास होता है और जो दूसरों की सफलताओं व कार्यों का श्रेय लेने की कोशिश करते हैं, उन्हें हम अस्वस्थ अभिभान से ग्रसित कह सकते हैं। वरिष्ठ मनोचिकित्सक स्वाति भागचंदानी के शब्दों में, ऐसे व्यक्ति आलोचनाओं को स्वीकार नहीं कर पाते और न ही अपनी गलती मानते हैं। अमेरिकी लेखक एवं स्पीकर जान सी मैक्सवेल कहते हैं कि अभिमान दो प्रकार का होता है- स्वस्थ एवं अस्वस्थ। स्वस्थ अभिमान आत्मसम्मान एवं गौरव को प्रतिबिंबित करता है, जबकि अस्वस्थ अभिमान दंभ एवं अभिमान की आड़ में श्रेष्ठता साबित करने का प्रयास कहलाता है। 'आयरन मैन' का खिताब पाने वाले अभिषेक मिश्रा को दौड़ने का जुनून है। उन्होंने अपने अनुभवों को लेकर किताब लिखी है। इनकी मानें, तो लोग अति-आत्मविश्वास से बचने की सलाह देते हैं, लेकिन इससे भी अधिक घातक होता है अस्वस्थ अभिमान। वह बताते हैं, 'एक बार साइक्लिंग प्रतियोगिता में मैंने चार किलोमीटर की रेस पूरी कर ली थी, तभी अचानक जोर से आवाज हुई। करीब से एक अन्य प्रतिस्पर्धी गुजरा, तो मुझे लगा कि उसकी साइकिल का पहिया पंक्चर हुआ है, लेकिन अगले ही क्षण एहसास हुआ कि पहिया तो मेरी साइकिल का पंक्चर हुआ था। मैं 35 मिनट तक वहीं खड़ा रह गया। वह मेरा अस्वस्थ अभिमान ही तो था।'

मनोचिकित्सकों के अनुसार, अस्वास्थ्यकर अभिमान व्यक्तिगत श्रेष्ठता पर जोर देता है और अक्सर दूसरों पर ध्यान देने या उन्हें नीचा दिखाने के लिए किया जाता है। वहीं, स्वस्थ अभिमान प्रामाणिक क्षमता की बात करता है। लेखिका एवं मनोचिकित्सक अभिलाषा माथुर कहती हैं, जो लोग परिवार, समाज, देश का गौरव बढ़ाते हैं, वे सबके प्रेरणास्रोत बनते हैं। उनमें ईर्ष्या या अहंकार की भावना नहीं होती। वहीं, अस्वस्थ अभिमान में फंसा व्यक्ति स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझकर अपने इर्द-गिर्द एक मिथकीय संसार रच लेता है, जो उसकी सफलता में बाधक बनता है। यह अहंकार कई बार उन पर भारी पड़ जाता है। इससे दूसरों के साथ उनके संबंध प्रभावित होने लगते हैं। स्वस्थ अभिमान जीवन को सुंदर एवं सुखमय बनाता है।

अंशु सिंह



फोटो : इमेजेज बाजार

हौसले से टूटेगा मुश्किलों का पहाड़

उजाले की ओर



अमित कासलीवाल
जाने-माने मोटिवेशनल स्पीकर

बाहरी परिस्थितियां आपको तभी तक प्रभावित करती हैं, जब तक आप अपने भीतर की शक्ति से अनजान रहते हैं। आप अपने जीवन के चाहे जिस भी चरण में हों, आपमें अद्भुत शक्ति विद्यमान है। जब एक नन्हा कीट तमाम मुश्किलों से जूझकर खूबसूरत तितली में परिवर्तित हो सकता है, तो फिर आप क्यों नहीं निरंतर कार्य करते हुए प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं? कोरोना अस्थायी है। अब इससे आगे बढ़कर अच्छा सोचें और अपने हौसले से मुश्किलों का पहाड़ तोड़ने के लिए आगे बढ़ें...

प्रबंधन की दुनिया में प्रायः तितली का उदाहरण देते हुए आगे बढ़ने की राह को परिभाषित किया जाता रहा है। तितली के अंडे से कैसे एक छोटा-सा कीट निकलता है, फिर वह कैटरपिलर यानी इल्ली का रूप ले लेता है, जो पत्तियां खाकर जिंदा रहता है। फिर उसके चारों तरफ कड़ा खोल बनता है और आखिर में उस कठोर आवरण को तोड़कर एक बहुत सुंदर, रंगबिरंगी और हर एक को आकर्षित करने वाली तितली बाहर निकल कर आती है। इल्ली से संपूर्ण तितली बनने तक का यह रूपांतरण एक कठिन और निरंतर प्रक्रिया है, जिससे यह सीख मिलती है कि निरंतर कर्म करते रहने से ही प्रगति मिलती है।

यदि आप कोरोना काल में ऐसा समझ रहे हैं कि आपकी प्रगति रुक गई है, तो ऐसा कदापि नहीं है। यह एक अस्थायी परिस्थिति है। इसमें आप रुकें नहीं। खुद को संभालें और निरंतर काम करने के लिए प्रेरित रहें। मजबूत इरादों और हौसलों से तो पहाड़ भी हिल जाते हैं। माना कि वर्तमान दौर कठिन है, लेकिन इससे निपटने के लिए खुद के व्यवहार में बदलाव लाएं, अपने आप पर भरोसा करें। अगर आप सोच रहे हैं कि कोरोना के चलते हमारे सामाजिक संबंधों में दूरियां बन रही हैं तो उनका समाधान ढूंढ़िए। नाते-रिश्तेदारों-दोस्तों से संवाद का दायरा बढ़ाइए। अगर छात्र हैं और सोचते हैं कि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं तो शिक्षक से तालमेल बढ़ाएं। यह समय मूल्यवान है। इसमें हम अपना सोच बदल कर कामयाबी और बेहतरी की राह पर फिर से आगे बढ़ सकते हैं। जहां तक मेरी बात है, मैं तो ऐसा कर पा रहा हूं। आप भी करें, खुद को तितली के रूप में विकसित करें।

विश्वास दिलाएगा जीत : कैटरपिलर की तरह ही हमारे भीतर भी शक्ति और काबिलियत है, जो हमारे अविकसित व्यक्तित्व को परिपक्व और सुदृढ़ बना सकती है। इस शक्ति को कोरोना जैसी अस्थायी स्थिति प्रभावित नहीं कर सकती। आपका काम आपको सफलता के शिखर पर ले जा सकता है। बस इस विकास पथ पर आपको दृढ़ता से विश्वास करना है। जीवन में आई विषम परिस्थितियों और समस्याओं के लिए बुरा समय या कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं हो सकता। एक छोटे कैटरपिलर से तितली बनने के लिए आपको विचार रूपी अपने पंखों को विस्तृत करना होगा और पुरजोर शक्ति लगाकर संकल्प के साथ कठिनाई रूपी कड़े खोल को तोड़कर बाहर हवा में उड़ना सीखना होगा।

इस मुश्किल दौर में भी हमें अच्छे समय की आशा नहीं छोड़नी चाहिए। ध्यान रखिए कि इस नाजुक समय में आपका विश्वास डगमगाए नहीं। इसके लिए धैर्य बनाए रखना होगा। जीवन में नित नये अवसर आते हैं। परीक्षा की इस घड़ी में हमें काम करने के नये तरीकों और शैलियों को खोजना होगा। एक छोटा पौधा भी कुछ दिनों में अपना स्वरूप बदल लेता है। तो फिर हम मनुष्य उसी पुराने ढांचे में अपने जीवन की गाड़ी क्यों खींच रहे हैं। समय के अनुसार तब्दीलियां आज के समय की मांग है। हम जिंदगी में किसी भी मोड़ पर हों, अपनी अद्भुत क्षमता को पहचानें। आगे मिलने वाली उपलब्धियों पर ध्यान दें। खुद पर हमारा विश्वास ही हमें जीत दिला सकता है।

जीवन का हो ध्येय: जो लोग किसी महत्वाकांक्षा के साथ जीते हैं, उनके सामने उनका लक्ष्य और रास्ता स्पष्ट होता है। वे विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक रुख के साथ अपने समय को लाभप्रद बना लेते हैं। यही महत्वाकांक्षा उन्हें ऊर्जा देती है, इसका होना बहुत जरूरी है। जिनकी महत्वाकांक्षाएं नहीं होतीं, वे परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं, अपनी कठिनाइयों की कहानी सुनाते रहते हैं। इसलिए जीवन का एक ध्येय बनाएं। यह आपकी आंतरिक शक्ति और क्षमता को मजबूत करता है। किसी भी तरह की निराशा को नजरअंदाज करते हुए आपको एक सुनहरे भविष्य की कल्पना करनी होगी। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे, जब किसी महान लक्ष्य को पाने के लिए लोगों ने विपरीत परिस्थितियों को धता बता संपूर्ण मानव जाति के लिए भलाई का काम किया या कोई महान सफलता अर्जित की। यह जानना बहुत जरूरी है कि मैं कौन हूं? मेरा जन्म क्यों हुआ है? मैं क्या कर सकता हूं? इसके लिए ऐसी गतिविधियों से जुड़ना होगा, जो आपके सोच को बेहतर बनाएं। मन पर नियंत्रण करने में मददगार हों। हम सभी को ऐसी दुनिया बनानी है, जहां सबके भीतर संतोष व सुकून का भाव आए, सभी की प्रगति हो। इन सबके लिए जीवन में लक्ष्य का होना आवश्यक है।

प्रस्तुति : यशा माथुर

डर भी है हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता का शत्रु



इंद्रोनिल मुखर्जी
लाइफ कोच व बैच फ्लावर थेरेपिस्ट

जब संकट आता है तो सबसे पहले डर की भावना उभरकर आती है। यह हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को दुर्बल बना देती है। इस समय जीवन व मृत्यु के डर से बाहर निकलना और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना आवश्यक है। योग की धारणा के अनुसार, मानव का अस्तित्व पांच भागों में बंटा है, जिन्हें पंचकोश कहते हैं। पंचकोश सिद्धांत के अनुसार, हमारे शरीर में पांच कोश होते हैं-अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश व आनंदमय कोश। विज्ञानमय कोश के जागरण से हमारे भीतर साक्षी भाव उत्पन्न होता है, जिससे हमारी मानसिक और भावनात्मक बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस प्रक्रिया में फूलों से बनी दवा भी कारगर साबित होती है। हम फूलों के अर्क से बनी दवा से इस डर को दूर करने की कोशिश करते हैं, जिसे बैच फ्लावर थेरेपी कहते हैं।

वर्तमान से रखें दोस्ती



भूत और भविष्य मात्र कल्पना है, जो पल हमारे सामने है, वही सच है। जब आपको इसका ज्ञान हो जाएगा तो आप इसी पल में अपना बेहतर प्रदर्शन करने की सोचेंगे। हमें यह स्वीकार करना होगा कि जो आज है, बस वही हमारा है। वर्तमान समय के साथ दोस्ती कर लेना ही सबसे अच्छा उपाय है। वर्तमान के प्रति जब आप सजग रहते हैं तो बेहतर निर्णय ले पाते हैं। कोई नई आदत विकसित कर पाते हैं। कुछ नया सृजन करने की क्षमता के साथ-साथ अपना कल बेहतर बना पाते हैं। आप सोच पाते हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है, मुझे कोविड के नियमों का पालन करना है, मास्क जरूर लगाना है, खाने के लिए बाहर नहीं जाना है। इस तरह से खुद पर बेहतर नियंत्रण कर आप पुरानी गलतियों को नहीं दोहराते हैं और दूसरों के लिए मुसीबत का सबब नहीं बनते हैं। वर्तमान को समझकर और उसमें रहते हुए आप जीवन को उत्सव बनाएं, जीने के नये तरीके सोचें। जब आप जीवंत होते हैं तो एक छोटे बच्चे से भी कुछ सीख लेते हैं। इन दिनों जब पूरे देश में बारिश की फुहारें पड़ रही हैं तो सिर्फ बच्चे ही क्यों आनंद लें, बड़े क्यों नहीं। आइए इन फुहारों में भीग कर महसूस करें कि हम कितने शांत हैं, कितने सजग हैं।

समय हमें परख रहा है



हममें से मात्र आठ फीसद लोग ही अपने विचारों पर नियंत्रण रख पाते हैं। यही लोग अपने कार्यों के बीच बेहतरीन सामंजस्य बिठाते हुए सही दिशा में कदम उठाते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणास्रोत बनते हैं। आज का समय भी हमें परख रहा है। अपने विचारों को सही दिशा में मोड़ देने के लिए कह रहा है। हमें अपने विचारों में बौद्धिक और रचनात्मक बदलावों के लिए जगह रखनी चाहिए। जैसे-जैसे आप अपने सोच पर नियंत्रण पा लेंगे, वैसे-वैसे सही कदम उठाएंगे और खुश रहेंगे। यदि आप खुश होंगे तो दिन को उपयोगी बनाएंगे और यदि आपका मन अच्छा नहीं होगा तो अपने समय को व्यर्थ गंवा देंगे।

व्यायाम से सकारात्मकता का निर्माण

स्वस्थ जीवनशैली



जैस्मीन कश्यप
फिटनेस एक्सपर्ट

लंदन के लाइफ स्टाइल व वेलनेस कोच गार्थ डेलिकन लोगों को तनाव, बेचैनी आदि मानसिक व्याधियों से लड़ना सिखाते हैं। उनका मानना है कि एक्सरसाइज का मतलब जिम जाना या वजनदार चीजें उठाना ही नहीं होता। आप जिस चीज को आनंदपूर्वक कर सकते हैं, वह आपको स्वस्थ रख सकता है। यह महज सीढ़ी चढ़ना-उतरना, दूर तक पैदल चलना, साइकिल चलाना, तैराकी करना हो सकता है, जिससे आपके हृदय एवं धमनियों में रक्त का पर्याप्त संचार होता रहे। जब हम शारीरिक क्रिया करते हैं, तो हृदय की गति तेज हो जाती है। मांसपेशियों में चुस्ती आ जाती है। इससे दिमाग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और आप अवसाद से बचे रहते हैं। इतना ही नहीं, यह उच्च रक्तचाप, स्ट्रोक के खतरे को भी कम करता है। अमेरिकी डायबिटीज एसोसिएशन के एक अध्ययन के अनुसार, नियमित व्यायाम करने वाले मधुमेह जैसी बीमारी तक का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। वहीं, जो लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, वे अपनी बेचैनी पर काफी हद तक काबू पा सकते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए जिम जाने की जरूरत नहीं होती। घर पर किताबों, दूध या पानी से भरे कैन की मदद से वजन आदि उठाने का प्रयास कर सकते हैं। इसी प्रकार, जब सामूहिक व्यायाम करते हैं, तो उससे दूसरों से बेहतर तरीके से जुड़ पाते हैं। उन पर विश्वास कर पाते हैं।



कोरोना काल में अभी भी जब बाहर जाना सीमित है, वैसे में आनलाइन भी समूह में व्यायाम करना फायदेमंद रहेगा। सोनाली एक फिटनेस फ्रीक हैं। व्यायाम के लिए समय निकाल ही लेती हैं। कुछ न किया, तो इमारत की सीढ़ियां ही चढ़-उतर लेती हैं। तभी तो 55 वर्ष की आयु में भी न सिर्फ उनका चेहरा दमकता है, बल्कि उनका खुशमिजाज स्वभाव आसपास के लोगों को खुश रहने के लिए प्रेरित करता है।

- व्यायाम से तन एवं मन दोनों रहते हैं सेहतमंद।
- हड्डियों से लेकर मांसपेशियां तक होती हैं मजबूत।
- नींद न आने की शिकायत होती है दूर।
- डिमेंशिया एवं अल्जाइमर का खतरा होता है कम।

दरअसल, व्यायाम से दिमाग में ऐसे रसायन (एंडोर्फिंस) उत्पन्न होते हैं, जो हमें खुश रखने में सहायक होते हैं। हम नकारात्मक वातावरण में भी अपना मानसिक संतुलन नहीं खोते हैं। वयस्कों के अलावा बच्चे व किशोर भी अपनी दिनचर्या में शारीरिक व्यायाम को शामिल कर अपनी एकाग्र शक्ति को बढ़ा सकते हैं। अनिद्रा की शिकायत को दूर कर सकते हैं। इससे उनका खुद पर भरोसा बढ़ेगा। जब परिवार के सभी सदस्य व्यायाम के प्रति गंभीर होंगे, तो न सिर्फ उनके सोच में परिवर्तन आएगा, बल्कि आसपास के माहौल पर भी सकारात्मक असर होगा।

साधु स्वभाव को अपनाने में है सुख

जीने की राह



आचार्य प्रशांत

जब चोट लगती है, तो हम आमतौर पर दो प्रकार की प्रतिक्रियाएं करते हैं। एक तो हम पलट कर वार करना चाहते हैं यानी जीतना चाहते हैं, दूसरी यह कि हममें जीतने की हिम्मत नहीं रहती और हम अपने को संवेदना-शून्य कर लेते हैं कि चोट ही न लगे। दोनों ही स्थितियों में कष्ट पैदा होगा। जो संसार को जीतना चाहेगा, वह भी कलह में उतर गया और जिसने अपने आप को संवेदनाशून्य कर लिया, वह भी कष्ट में उतर गया। वहीं, साधु वह है जो यह जान गया है कि संसार को जीता नहीं जा सकता। जब उसे चोट पहुंचाई जाती है, तो उसमें यह भाव नहीं उठता कि मुझे जिसने चोट पहुंचाई है, मैं उस पर विजय प्राप्त कर लूं। साधु वह है जो समझ जाए कि इसमें हार ही हार है। वह अच्छे से समझ गया है कि संसार से उलझना ही हार है। इसका यह अर्थ नहीं है कि उसने जीत के दरवाजे बंद कर दिए हैं। उसने कहा है, 'जीत है, पर संसार में नहीं है।' फिर जीत कहां है? जीत राम में है। ऐसा नहीं है कि साधु को आप आहत करेंगे, मात्र तभी वह आपसे उलझना नहीं चाहता। आप जब उसकी प्रशंसा करेंगे, वह तब भी आपसे नहीं उलझना चाहेगा। साधु कभी निंदा या प्रशंसा के चक्करों में नहीं पड़ता। इस साधु स्वभाव को अपनाने में सुख ही सुख है।



पुस्तक 'भागे भला न होएगा' से साभार

अपनी राय हमें जरूर बताएं : feature@jagran.com

आज का भविष्यफल

के. ए. दुबे पद्मेश

आज की ग्रह स्थिति: 29 जुलाई, 2021 गुरुवार श्रावण मास कृष्ण पक्ष षष्ठी का राशिफल।
आज का राहुकाल: दोपहर 01:30 बजे से 03:00 बजे तक।
आज का दिशाशूल: दक्षिण।
विशेष: पंचक।

मेष: भावुकता में नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास फलीभूत होगा। दांपत्य जीवन सुखमय होगा।

वृष: यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद होगी, लेकिन मैत्री संबंधों में तनाव आ सकता है। चल या अचल संपत्ति के मामलों में आशातीत सफलता मिलेगी।

मिथुन: महिला अधिकारी का सहयोग रहेगा। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। दूसरे से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी।

कर्क: व्यावसायिक मामलों में प्रगति होगी। शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। धार्मिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी।

सिंह: भावुकता में नियंत्रण रखें। नेत्र या उदर विकार के प्रति सचेत रहें। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। व्यावसायिक मामलों में सफलता मिलेगी।

कन्या: उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। किसी कार्य के संपन्न होने से आपके प्रभाव तथा वर्चस्व में वृद्धि होगी।

तुला: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास फलीभूत होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।

वृश्चिक: आर्थिक मामलों में सुधार होगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। व्यावसायिक मामलों में प्रगति होगी।

धनु: महिला रिश्तेदार से तनाव मिल सकता है। धर्म गुरु या पिता का सहयोग रहेगा। व्यावसायिक योजना फलीभूत होगी। शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति होगी।

मकर: रिश्तों में मधुरता आएगी। व्यावसायिक प्रयास फलीभूत होगा। शासन सत्ता का सहयोग रहेगा। रचनात्मक प्रयास फलीभूत होंगे।

कुंभ: सम्मान में वृद्धि होगी। दूसरे से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। किसी कार्य के संपन्न होने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।

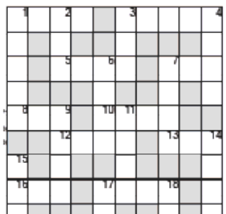
मीन: आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है।

कल 30 जुलाई का पंचांग



कल का दिशाशूल: पश्चिम।
विशेष: पंचक दोपहर 02:02 बजे तक
कल की भद्रा: प्रातः 03:55 बजे से शाम 04:44 बजे तक।
विक्रम संवत 2078 शके 1943 दक्षिणायन, उत्तरगोल, वर्षा ऋतु श्रावण मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी 29 घंटे 27 मिनट तक, रेवती नक्षत्र 14 घंटे 02 मिनट तक, तत्पश्चात् अश्विनी नक्षत्र धृति योग तत्पश्चात् शूल योग मीन में चंद्रमा तत्पश्चात् मेष में।

वर्ग पहेली-1651



© Bird Features & Writing Agency

बाएं से दाएं
1 [illegible] (4)।
3 [illegible] (5)।
5 [illegible] (4)।
7 [illegible] (3)।
8 [illegible] (3)।
10 [illegible] (4)।
12 [illegible] (4)।
13 [illegible] (3)।
16 [illegible] (3)।
17 [illegible] (4)।
19 [illegible] (5)।
20 [illegible] (4)।

ऊपर से नीचे
1 [illegible] (5)।
2 [illegible] (3)।
3 [illegible] (3)।
4 [illegible] (4)।
6 [illegible] (4)।
7 [illegible] (4)।
9 [illegible] (4)।
11 [illegible] (4)।
14 [illegible] (3,2)।
15 [illegible] (4)।
17 [illegible] (3)।
18 [illegible] (3)।

कल का हल



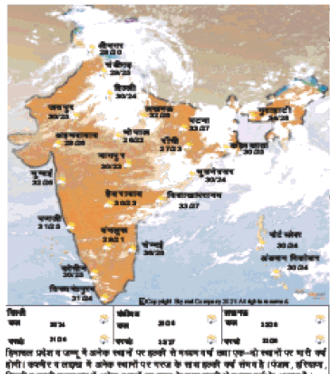
जागरण सुडोकू-1651

1		3		6	5		4	
					9	7		3
7		9		1			5	
	7			4			8	
3		1			2	4		7
		8	1			3		
	3			7	1		2	8
	1					6		
8		7	6					1

कल का हल

4	8	5	1	6	2	7	9	3
6	1	7	8	3	9	4	2	5
9	3	2	7	4	5	6	1	8
3	6	1	9	8	7	5	4	2
2	7	9	6	5	4	3	8	1
8	5	4	3	2	1	9	6	7
7	2	6	5	9	8	1	3	4
5	9	8	4	1	3	2	7	6
1	4	3	2	7	6	8	5	9

मौसम



हिमाचल प्रदेश व जम्मू में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा तथा एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा होगी। कश्मीर व लद्दाख में अनेक स्थानों पर गरज के साथ हल्की वर्षा संभव है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व उत्तरी राजस्थान में अनेक स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा के आसार हैं।

कल पढ़ें



हर तरह का किरदार निभाना चाहिए

[illegible]

भारत-श्रीलंका के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए

वर्ष 1987 में आज ही भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति जेआर जयवर्धने के साथ कोलंबो में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसका उद्देश्य श्रीलंका में चल रहे गृह युद्ध को रोकना था।





अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की स्थापना को मंजूरी मिली

1958 में आज ही अमेरिकी संसद ने नेशनल एयरोनाटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया था। एक अक्टूबर 1958 से नासा का परिचालन शुरू किया गया। अंतरिक्ष के क्षेत्र में नासा के नाम कई उपलब्धियां दर्ज हैं।

जेआरडी टाटा ने शुरू की थी भारत की पहली एयरलाइंस

भारत में सिविल एविएशन के जनक कहे जाने वाले जेआरडी टाटा का जन्म आज ही 1904 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। 1929 में इन्हें भारत के पहले पायलट का लाइसेंस मिला। 1932 में कराची से बंबई फ्लाइट उड़ाकर टाटा एयरलाइंस सेवा शुरू की थी। 1946 में इसका नाम एयर इंडिया लिमिटेड किया गया, जिसका 1953 में राष्ट्रीयकरण हुआ। इन्हें 1957 में पद्मविभूषण और 1992 में भारत रत्न मिला। 29 नवंबर 1993 को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इनका निधन हो गया।



इधर-उधर की

बंदरों के दो गुट की लड़ाई से रुक गया ट्रैफिक



लोगों के दखल से लड़ाई और तेज हो गई। इंटरनेट मीडिया

बैंकाक, एजेंसी : इंसानों में शक्ति प्रदर्शन की बात तो आपने सुनी होगी, लेकिन जानवर भी पीछे नहीं हैं। थाइलैंड के लोपबुरी शहर की घटना इसी की बानगी है। यहां बंदरों के दो गुटों में ऐसी भिड़ंत हुई कि सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गया। एक प्रत्यक्षदर्शी ने घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर डाला, जिसमें बंदर एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और दोनों ओर से ट्रैफिक रुका हुआ है। इस लड़ाई में कई बंदर घायल हो गए और सड़क पर खून फैल गया। नेशनल पार्क्स के प्रवक्ता ने कहा, इनके बीच की लड़ाई शक्ति प्रदर्शन, भोजन और मादा बंदरों के साथ को लेकर थी।

स्तनपान से बच्चों में कम होता है बीपी

आगे भी फायदा ▶ वयस्क होने पर हार्ट और वास्कुलर स्वास्थ्य रहता है बेहतर

कनाडा के मैक मास्टर यूनिवर्सिटी के विज्ञानियों का शोध



सेहतकारी है मां का दूध। फाइल फोटो

वाशिंगटन, एएनआइ : मां के दूध को वैसे ही अमृत नहीं कहते हैं। यह कितना सेहतकारी है, इसकी पुष्टि एक और हालिया शोध से हुई है। इसमें बताया गया है कि जिन बच्चों को कुछेक दिन भी स्तनपान कराया जाता है, उनका रक्तचाप (ब्लड प्रेशर- बीपी) कम रहता है और इसका फायदा बच्चों को वयस्क होने पर भी बेहतर हार्ट और वास्कुलर स्वास्थ्य के रूप में मिलता है।

शोध का यह निष्कर्ष अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के जर्नल में प्रकाशित हुआ है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि कार्डियोवास्कुलर रोगों के जोखिम कारकों की शुरुआत बचपन में भी हो सकती है। बता दें कि हाई ब्लड प्रेशर कार्डियोवास्कुलर रोगों का प्रमुख जोखिम कारक माना जाता है। शोध में इस बात की पुष्टि हुई कि स्तनपान का संबंध बच्चों के वयस्क होने पर हृदय या कार्डियोवास्कुलर रोगों के जोखिम कम करने से भी है। लेकिन अभी यह सुनिश्चित नहीं हो सका है कि इस तरह के फायदे के लिए कितनी अवधि तक स्तनपान की जरूरत है।

कनाडा के हैमिल्टन में मैक मास्टर यूनिवर्सिटी में चाइल्ड कोहार्ट स्टडी के शोधकर्ता कोजेटा मिलिकु का कहना कि जीवन के शुरुआती दिनों में स्तनपान और बचपन में ब्लड प्रेशर से उसके संबंध पर यह पहला अध्ययन है। मिलिकु ने बताया कि जिन नवजातों को कम मात्रा में भी मां का पहला दूध (कलास्ट्रम) मिला, उनमें तीन साल की उम्र में ब्लड प्रेशर कम था।

कलास्ट्रम में बच्चों के विकास के लिए जरूरी तत्वों, प्रतिरक्षी घटकों (इम्यूनोलाजिक कंपोनेंट्स) तथा स्टेम सेल की अधिकता होती है, जो काफी फायदेमंद होता है। खास बात यह कि ये सिर्फ मानव दूध में पाए जाते हैं।

शोध के तौर-तरीके : अध्ययन के लिए कनाडियन चाइल्ड कोहार्ट स्टडी में शामिल तीन हजार बच्चों के डाटा का इस्तेमाल किया गया। इन बच्चों का जन्म 2009-2012 के बीच हुआ था। अस्पताल के रिकार्ड से नवजातों को स्तनपान कराए जाने और करीब 2,400 बच्चों की देखभाल संबंधी डाटा प्रश्नावली के माध्यम से एकत्रित किए गए।

इनमें से 98 फीसद नवजातों को स्तनपान कराए गए थे, जिनमें से चार फीसद अस्पताल में रहने के दौरान सीमित ही स्तनपान करने वाले थे। अध्ययन में शामिल सिर्फ दो फीसद नवजातों को बिल्कुल ही स्तनपान नहीं कराया गया था। स्तनपान करने वाले बच्चों में से 78 फीसद को छह माह या उससे अधिक समय तक और 62 फीसद को कम से कम तीन माह तक सिर्फ स्तनपान कराया गया था।

शोध के निष्कर्ष

- जिन बच्चों को बिल्कुल भी स्तनपान नहीं कराया गया, उनमें तीन साल की उम्र में हाई ब्लड प्रेशर (औसत 103/60 एमएम एचजी) पाया गया। जबकि जिन बच्चों को स्तनपान कराया गया था (कितने भी समय तक), उनका औसत ब्लड प्रेशर 99/58 एमएम एचजी) पाया गया।
- जिन नवजातों को अस्पताल में रहने के दौरान सीमित स्तनपान ही कराया जा सका, उनका भी औसत ब्लड प्रेशर 99/57 एमएम एचजी था।
- जिन नवजातों को स्तनपान कराया गया, उनके तीन साल के होने पर भी ब्लड प्रेशर कम रहा, भले ही उनका बाडी मास इंडेक्स (बीएमआइ) या मां की जीवनशैली की कैसी भी रही हो।
- उन बच्चों का भी ब्लड प्रेशर कम रहा, जिन्हें किसी भी अवधि तक स्तनपान कराया गया या उसके साथ पूरक पोषण आहार दिए गए।

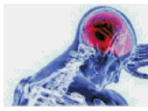


वायु प्रदूषण कम करने के लिए एयर बबल

वैश्विक स्तर पर बढ़ रहे वायु प्रदूषण से मानव जीवन के अस्तित्व पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में पोलैंड ने एक प्राकृतिक एयर प्यूरीफायर तैयार किया है, जो वातावरण में मौजूद कार्बन डाईआक्साइड सहित अन्य हानिकारक गैसों को अपने अंदर समाहित कर प्रचुर मात्रा में आक्सीजन का उत्सर्जन करता है। इसके अंदर लगे दर्जनों कांच के बाक्स में हानिकारक तत्वों को सोखने वाले शैवाल रखे गए हैं। इसे एयर बबल नाम दिया गया है। फिलहाल इसे अभी राजधानी वारसा स्थित स्टेडियम में लगाया गया है। एएफपी

कोरोना संक्रमण से मरीजों में ब्रेन स्ट्रोक का खतरा

अनुसंधान



गंभीर साइड इफेक्ट। फाइल फोटो

कोरोना महामारी में सबसे ज्यादा खतरा ऐसे लोगों में बना हुआ है, जो उच्च रक्तचाप (हाई ब्लड प्रेशर) या मधुमेह (डायबिटीज) के मरीज हैं। अब एक नए अध्ययन में सामने आया है कि इन दोनों बीमारी वाले लोगों में कोरोना संक्रमित होने के बाद ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा सबसे ज्यादा रहता है।

यह अध्ययन ब्रिटेन के साउथहैंपटन यूनिवर्सिटी के एक दल ने किया है। अध्ययन में यह भी देखने को मिला कि ज्यादा उम्र वालों के साथ ही ब्रेन स्ट्रोक का खतरा कोरोना संक्रमित युवाओं में भी बना रहता है। अध्ययन का परिणाम जर्नल ब्रेन कम्युनिकेशंस में प्रकाशित हुआ है। इस अध्ययन में 267 ऐसे लोग शामिल किए गए, जो कोरोना संक्रमित हुए। संक्रमित होने के बाद इनके मस्तिष्क संबंधी रोगों का अध्ययन किया गया। अध्ययन में आधे मरीजों में ब्रेन स्ट्रोक होने के खतरे देखे गए। इनमें से 60 साल की उम्र वाले मरीजों में से चौथाई को ब्रेन स्ट्रोक हुआ। इस उम्र वर्ग में अधिकांश कोरोना मरीज स्ट्रोक के खतरे वाले स्तर पर थे। 10 फीसद से ज्यादा मरीजों की हालत गंभीर हुई और उनको इंटेसिव केयर यूनिट और वेंटीलेटर की आवश्यकता पड़ी।

अध्ययन दल के डा. एमी रोश रशेल ने बताया कि कोरोना संक्रमण नर्वस सिस्टम के एक से ज्यादा हिस्सों को प्रभावित कर सकता है। मरीज की खून की धमनियों में रुकावट हो सकती है। शरीर के किसी भी हिस्से में खून का थक्का बनने की भी दिक्कत आ सकती है। -आइएएनएस

मरणासन्न तारे भी कर सकते हैं छोटी अवधि का गामा-रे विस्फोट

नासा ने खोजा उच्च ऊर्जावान विस्फोट, जीआरबी 200826ए दिया नाम, एरीज नैनीताल के विज्ञानी डा. पांडेय ने नापी खगोलीय विस्फोट के स्थान की दूरी

जागरण संवाददाता, नैनीताल

नासा ने हाल में ही एक विशिष्ट प्रकार के उच्च ऊर्जा विस्फोट की खोज की है। यह खगोलीय विस्फोट अब तक देखे गए बेहद ऊर्जावान छोटी अवधि का गामा-रे विस्फोट है। इससे पता चलता है कि मरणासन्न तारे भी छोटी अवधि का गामा-रे विस्फोट कर सकते हैं। इस खोज में आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान (एरीज) के वरिष्ठ विज्ञानी डा. शशिभूषण पांडेय ने विस्फोट वाले स्थान की दूरी मापन का महत्वपूर्ण कार्य किया है। विज्ञानियों ने इसे जीआरबी 200826ए नाम दिया है।

विज्ञानी डा. शशिभूषण पांडेय ने बताया कि इस विस्फोट की खोज 26 अगस्त 2020 में नासा ने फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप से की थी। इसके बाद इसकी सत्यता की पुष्टि के लिए विज्ञानियों ने अध्ययन शुरू किया। यह विस्फोट ब्रह्मांड के सबसे बड़े विस्फोटों में से एक है। इसे नासा के विंड व मार्श मिशन ने भी आब्जर्व किया। इस विस्फोट से निकलने वाला जेट यानी आवाज व प्रकाश समूह ब्रह्मांड की आधी आयु से पृथ्वी की ओर आ रहा था। इसके आने की अवधि गामा किरणों में करीब एक सेकेंड रही थी। जिसे लेकर माना गया कि यह अभी तक का सबसे छोटे ज्ञात विस्फोटो में से एक है। इसी कारण इस खोज ने गामा किरणों के विस्फोट यानी जीआरबी का पता लगाने में एक कीर्तिमान स्थापित किया है।

डा. शशिभूषण ने बताया कि विस्फोट के स्थान की दूरी जानने के लिए उन्होंने स्पेन की कैनरी द्वीप समूह स्थित 10.4 मीटर आप्टिकल दूरबीन का प्रयोग किया। अध्ययन से पता चला कि एक तरह से यह असफल विस्फोट था। इसके बावजूद यह हमारी आकाशगंगा की ऊर्जा से 1.4 करोड़ गुना अधिक थी। इस खोज से यह भी पता चला है कि संकुचित तारे से उत्सर्जित होने वाली छोटी अवधि की जीआरबी बहुत ही कम होते होंगे। यही नहीं, ज्यादातर विशालकाय तारों का अंत जेट और जीआरबी उत्पन्न किए बिना ही हो जाता है। लिहाजा जीआरबी की अधिक मात्रा इसके मूल स्रोत की जानकारी नहीं दे सकती। खोजकर्ता विज्ञानियों का कहना है यह खोज भूसे के ढेर से सुई खोजने जैसी है। जो ब्रह्मांड में होने वाले महाविस्फोटों को समझने में नए आयाम जोड़ेगी।



ब्रह्मांड का एक और रहस्य आया सामने। फाइल फोटो

सौरमंडल का विनाश करने की ताकत रखती हैं ये शक्ति

सुपरनोवा और जीआरबी ब्रह्मांड के वे विस्फोट हैं, जो तारों के अंत समय में ब्लैक होल को जन्म दे सकते हैं। ऐसे विस्फोट जेट जैसी महा ऊर्जावान स्थिति का निर्माण करते हैं। जो अपने सामने वाले तारों व ग्रहों को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। यदि ऐसा कोई विस्फोट हमसे नजदीक या हमारी आकाशगंगा में होगा तो वह पृथ्वी समेत हमारे सौरमंडल का विनाश कर जाएगा। पांच सौ प्रकाश वर्ष की दूरी पर होने वाला विस्फोट भी हमारे सेटेलाइट व संचार व्यवस्था को बाधित कर सकता है। महाविस्फोट करने वाले तारे सूर्य से कई गुना बड़े होते हैं।

स्क्रीन शॉट

डाक्टर जी की शूटिंग करने भोपाल पहुंचीं रकुल प्रीत सिंह



फिल्म डाक्टर जी में डाक्टर के किरदार में हैं रकुल प्रीत। इंस्टाग्राम

अभिनेता आयुष्मान खुराना के बाद अब अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह भी आगामी फिल्म डाक्टर जी की शूटिंग के लिए भोपाल पहुंच गई हैं। आयुष्मान गत 12 जुलाई से ही भोपाल में इस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। रकुल प्रीत ने मंगलवार को फिल्म की टीम की तरफ से उनके स्वागत में लिखे कार्ड की तस्वीर इंस्टाग्राम पर साझा करते हुए यह जानकारी सार्वजनिक की। फिल्मकार अनुराग कश्यप की बहन अनुभूति कश्यप के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में आयुष्मान स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर उदय गुप्ता का किरदार निभा रहे हैं, जबकि रकुल प्रीत उनकी सीनियर डाक्टर फातिमा का किरदार निभा रही हैं। यह फिल्म एक मेडिकल इंस्टीट्यूट के कैंपस की पृष्ठभूमि पर आधारित है। अनुभूति की बतौर निर्देशक यह पहली फिल्म है। इससे पहले उन्होंने पिछले साल गुलशन देवैया अभिनीत डार्क कामेडी वेब सीरीज अफसोस का निर्देशन किया था। अनुभूति ने ही विशाल वाघ, सुमित सक्सेना और सौरभ भरत के साथ मिलकर इस फिल्म को लिखा भी है। आयुष्मान की बात करें तो इस फिल्म की शूटिंग शुरू करने से पहले उन्होंने अनुभव सिन्हा के निर्देशन में फिल्म अनेक की शूटिंग पूरी की थी। वहीं रकुल प्रीत के हाथों में मौजूदा समय में इस फिल्म के अलावा मेडे, थैंक गाड और अटैक जैसी फिल्में हैं।

अस्सी तुस्सी, लस्सी पिस्सी जैसे शब्दों को मिलाकर बना हवा हवाई गाना...



सिंगिंग रियलिटी शो में बतौर मेहमान पहुंचीं कविता कृष्णमूर्ति। टीम सोनी

खुशी, गम और प्यार के अलग-अलग भावों को दर्शाते गानों के बनने के पीछे भी कई बार कुछ दिलचस्प कहानियां होती हैं। कुछ ऐसी ही दिलचस्प कहानी रही साल 1986 में रिलीज हुई फिल्म मिस्टर इंडिया के गाने हवा हवाई की.... जिसे श्रीदेवी पर फिल्माया गया था। इस गाने के बनने की पीछे की कहानी को साझा किया गायिका कविता कृष्णमूर्ति ने, जो सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 के मंच पर गायक कुमार सानू के साथ आगामी एपिसोड की शूटिंग के दौरान बतौर मेहमान पहुंचीं। शो से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, फ्रेंडशिप डे को समर्पित इस एपिसोड में प्रतिभागियों ने दोस्ती से संबंधित दोनों गायकों के गाने गाए। इस दौरान विशाखापत्तनम की प्रतिभागी शन्मुख प्रिया ने कविता के गाए हवा हवाई गाने पर परफार्म किया। उसे सुनकर कविता ने इस गाने से जुड़ा एक किस्सा बताया कि संगीतकार लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल की जोड़ी के लक्ष्मीकांत जी का महबूब स्टूडियो में एक अपना रिकार्डिंग स्टूडियो था। मैं वहीं बैठी हुई थी, तो प्यारे भाई (प्यारेलाल) उस समय संगीतकारों को तैयार कर रहे थे और उस समय तक लक्ष्मीकांत जी ने सिर्फ तीन-चार शब्द कंपोज किए थे। तभी किसी म्यूजिशियन ने कहा कि अस्सी तुस्सी शब्दों को नोट डाउन (लिखें) करें और उसमें लस्सी पिस्सी भी जोड़ें। दूसरे म्यूजिशियन ने कहा कि यदि गाने में हांगकांग है, तो किंग कांग भी होना चाहिए। इसी बीच जावेद साहब (जावेद अख्तर) आए और कहा कि मोम्बासा गाने का आखिरी शब्द होना चाहिए। यही सारी चीजें इस गाने की शुरुआत का हिस्सा बन गईं और गाना तैयार हुआ।

बचपन से हील्स का शौक रहा, इसे पहनना एक एहसास है : मानुषी छिल्लर



पृथ्वीराज फिल्म में नजर आएंगी मानुषी। इंस्टाग्राम

सितारे अक्सर लोगों के सामने बड़ी हील्स और अप टू डेट होकर आते हैं, लेकिन अकेले में वह भी खुद के लिए कंफर्ट चाहते हैं। हालांकि शो बिजनेस में कंफर्ट के साथ बहुत बार समझौता करना पड़ता है। हाई हील्स के साथ सितारों को पूरे दिन शूट भी करना पड़ता है। बात करें अगर पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर की तो हील्स को लेकर उनकी राय कुछ और है। एक इंटरव्यू के दौरान मानुषी ने कहा कि मुझे बचपन से हील्स का शौक रहा है। मैं जब छोटी थी, तब कई बार मम्मी की हील्स पहन लेती थी। दोस्त कहते थे कि इतनी लंबी पहले से ही हो, हील्स क्यों पहनती हो, लेकिन मेरे लिए हील्स पहनना हमेशा से ही एक एहसास रहा है। हील्स एक भावना है। मैं मानती हूं हील्स वाली सैंडल्स बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होती हैं। लेकिन मुझे उन्हें देखना पसंद है। मेरे ख्याल से आपकी लंबाई कम हो या ज्यादा हील्स का उससे कोई लेना-देना नहीं है। इसी तरह मुझे साड़ियों का भी बहुत शौक है। मम्मी को मैंने हमेशा साड़ी में देखा है। वह तो आफिस भी साड़ी पहनकर जाती रही हैं। मेरा बस चले तो हर जगह मैं साड़ी में ही जाऊं। मानुषी फिल्म पृथ्वीराज से बालीवुड में डेब्यू करने के लिए तैयार हैं।

दिल्ली की सर्दी में मुंह से भाप निकलती थी तो उसमें भी कविता होती : दिव्येंदु

कर्मभूमि और जन्मभूमि दोनों के बीच में से किसी एक को चुन पाना किसी के लिए भी मुश्किल है। दोनों की ही अपनी अहम जगह होती है। मिर्जापुर के मुन्ना भैया यानी दिव्येंदु शर्मा दिल्ली से हैं और उनकी कर्मभूमि मुंबई है। ऐसे में दोनों के बीच किसी एक को चुनना उनके लिए भी मुश्किल था। एक लाइव चैट के दौरान एक यूजर ने उनसे पूछा कि दिल्ली की सर्दी पसंद है या मुंबई की पानीपुरी। इस पर दिव्येंदु ने दिल्ली की सर्दी को याद करते हुए कहा कि दिल्ली की सर्दी इतनी गुलाबी होती है कि उसके क्या कहने। कालेज के लड़कों के लिए बेस्ट मौसम है। जब हम कालेज में थे और किसी लड़की से फ्लर्ट करते थे या किसी को डेट करते थे, तो सर्दियों के मौसम की अहमियत और बढ़ जाती थी। शाम को डेट पर कहीं खड़े होकर बातें करते वक्त जो भाप ठंड की वजह से मुंह से निकलती थी, उसमें भी एक कविता होती थी। गरमा गरम चाय की एक प्याली से दो प्याली बनाना, स्ट्रीट फूड खाना उसका मजा दिल्ली में ही है। मुंबई की पानीपुरी भी कम नहीं है। एक्टर बनने के बाद जो सबसे ज्यादा मैं मिस करता हूं, वह है आजादी से घूमना-फिरना। अब पहले की तरह रास्तों पर घूम नहीं सकता हूं। मैं इस बात की शिकायत नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब मुझे पता है कि लोग मुझे देख रहे हैं, तो जैसा मैं वास्तव में हूं, वैसा नहीं रह पाता हूं। मिर्जापुर सीजन 3 को लेकर दिव्येंदु ने कहा कि मुझे उसकी रिलीज तारीख पता है, लेकिन मैं बता नहीं सकता हूं, क्योंकि फिर मजा किरकिरा हो जाएगा।



मिर्जापुर में अपने किरदार मुन्ना भैया के लिए प्रसिद्ध हैं दिव्येंदु। इंस्टाग्राम



द एंपायर होगी शबाना आजमी की पहली वेब सीरीज ● इंस्टाग्राम

हमेशा से करियर में ऐतिहासिक किरदार निभाना चाहती थी। इसमें मेरी भूमिका किंगमेकर की होगी, जो शिक्षित और असाधारण है।

द एंपायर में पहली बार ऐतिहासिक किरदार निभाना चैलेंजिंग रहा : शबाना

डिजिटल प्लेटफार्म सिर्फ नए कलाकारों को ही नहीं बल्कि पुराने और अनुभवी कलाकारों को भी नए प्रयोग करने के मौके दे रहा है। इस प्लेटफार्म पर कुछ ऐसा ही मौका देखते हुए अभिनेत्री शबाना आजमी ने भी अपनी पहली वेब सीरीज द एंपायर स्वीकार की है। पहले इसका निर्माण मुगल शीर्षक से किया गया था, लेकिन बाद में निर्माताओं ने नाम बदल दिया। इस शो के बारे में शबाना का कहना है, 'मुझे इसकी स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई। मुझे पता था कि यह काफी अलग होने वाला है। मैं हमेशा से कोई ऐतिहासिक किरदार निभाना चाहती थी और इस शो में पहली बार ऐतिहासिक किरदार निभाना मेरे लिए चैलेंजिंग रहा। मेरे किरदार की विशेषता है कि वह एक शिक्षित और असाधारण महिला है और वह किंगमेकर है। हम अक्सर किसी पुरुष को किंगमेकर के तौर पर देखते हैं, लेकिन इस कहानी में वह किंगमेकर है। इस शो के निर्माता निखिल आडवाणी और निर्देशक मिताक्षरा कुमार का शानदार नजरिया है। खासतौर पर मिताक्षरा का, जिनकी दिलचस्पी फ्रेम की हर बारीकी पर होती है। यह मेरे लिए काफी आकर्षक था।' वहीं डिजिटल प्लेटफार्म के बारे में शबाना कहती हैं, 'जब लोग डिजिटल प्लेटफार्म पर कोई कंटेंट देखते हैं तो उनका नजरिया आम सिनेमा देखने से अलग होता है। इसमें उनके पास आपका काम या कहानी न पसंद आने पर शो बंद करने की सुविधा होती है। बतौर कलाकार यह चुनौती मुझे आकर्षित करती है। आने वाले समय में डिजिटल प्लेटफार्म सभी कलाकारों के लिए उम्र और लिंग से ताल्लुक न रखकर सिर्फ कहानी से ताल्लुक रखने वाला चैलेंजिंग काम लाएगा।' डिज्नी प्लस हाटस्टार के लिए बने इस शो में शबाना के साथ कुणाल कपूर मुख्य भूमिका में हैं।

'जैद से शादी सबसे खास फैसला'



हालिया रिलीज फिल्म 14 फेरे में नजर आई हैं गौहर ● इंस्टाग्राम

इंटरनेट मीडिया पर अपने फैंस से जुड़ने वालों में गौहर खान का नाम भी शुमार है। वह अक्सर खुद से जुड़ी बातें साझा करती रहती हैं। बुधवार को गौहर ने इंस्टाग्राम पर अपने फैंस के लिए एक सवाल-जवाब सेशन रखा। सवालों को चुनकर गौहर ने उस पर जवाब दिए। एक फैन ने पूछा कि कैसे हम आपसे इतना जुड़ जाते हैं? ऐसा लगता है कि आप हम जैसी ही हैं। इस पर गौहर ने अपनी एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, 'हां, क्योंकि मैं आप जैसी ही हूं। हम सभी इंसान हैं। अल्लाह किसी को भी जन्म के वक्त अलग से कोई प्वाइंट्स नहीं देते हैं।' एक फैन ने जीवन के सबसे अहम निर्णय के बारे में पूछा, जिसके लिए वह शुक्रगुजार हों। इस पर गौहर ने अपने पति जैद दरबार के साथ तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि जैद से शादी करना। एक यूजर ने जब उनसे पूछा कि मैरिड लाइफ ज्यादा बेहतर है या सिंगल लाइफ थी? इस पर गौहर ने जैद के साथ एक वीडियो साझा किया और लिखा यकीनन शादीशुदा जिंदगी। एक फैन ने गौहर से पूछा कि अगर उन्हें इस धरती से कुछ मिटाने का मौका मिले, तो वह क्या मिटाना चाहेंगी। इस पर गौहर ने लिखा, 'असहिष्णुता और नफरत।'

एमटीवी अनवाइंड शो अगले महीने से

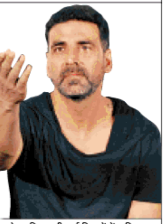


नए म्यूजिक शो का हिस्सा होंगे दर्शन रावल ● इंस्टाग्राम

सिनेमा और डिजिटल प्लेटफार्म की तरह इन दिनों टेलीविजन शो में भी निर्माता अलग-अलग प्रयोग कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही प्रयोगात्मक कदमों के तहत एमटीवी पर नया म्यूजिक शो एमटीवी अनवाइंड शुरू होने जा रहा है। इस शो में सोनू निगम, लकी अली, बादशाह, दर्शन रावल, बेनी दयाल, असीस कौर, हर्षदीप कौर, कैलाश खेर, पैपान, रोचक कोहली, अमाल मलिक, अरमान मलिक, मोनाली ठाकुर, अर्जुन कानूनगो, स्नेहा खानवलकर, आस्था गिल, रीत तलवार जैसे देश के जाने-माने कलाकार अलग-अलग जानर्स (विधाओं) के गानों पर परफार्म करेंगे। 10 एपिसोड वाले इस शो में संगीतप्रेमी न सिर्फ अपने चहेते कलाकारों के पुराने गानों को सुन सकेंगे बल्कि कलाकार इसमें कुछ नए गानों को भी प्रस्तुत करेंगे। इस शो के बारे में संगीतकार दर्शन रावल ने कहा, 'हर नया गाना हम कलाकारों के साथ-साथ श्रोताओं के लिए भी प्रयोग करने और कुछ नया खोजने का एक मौका देता है। मुझे इस शो से जुड़ने पर गर्व है। इस शो के जरिये हमें एक अनोखे तरीके से अपने जीवन में कुछ नई रचनात्मक चीजें जोड़ने का मौका मिल रहा है। इस शो का प्रसारण 13 अगस्त से एमटीवी पर शुरू होगा।

सिपाही पर लिखी कविता सुनकर भावुक हुए अक्षय कुमार

यूं तो अक्षय कुमार रफ एंड टफ एक्टर माने जाते हैं, लेकिन जब बात देश के सैनिकों की होती है, तो वह काफी भावुक भी हैं। हाल ही में अजय देवगन का देश के सिपाही पर कविता पढ़ते हुए वीडियो देखकर अक्षय भावुक हो गए। दरअसल, अजय की आगामी फिल्म भुज : द प्राइड आफ इंडिया होगी, जिसमें वह भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्णिक के किरदार में नजर आएंगे। इस फिल्म में उन्होंने मनोज मुंतशिर की लिखी एक कविता पढ़ी है। उसी कविता पर अजय ने वीडियो बनाकर ट्विटर पर पोस्ट किया था। अक्षय ने इस वीडियो को ट्विटर पर साझा करते हुए लिखा कि इस वीडियो को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे नहीं पता था तुम्हारे (अजय) अंदर एक इतना अच्छा कवि छुपा है। किस-किस बात पर दिल जीतोगे यार। इस पर अजय ने जवाब दिया, मेरी काव्य कौशल की तारीफ करने के लिए अक्की तुम्हारा शुक्रिया। मैं इसके लिए कविता को लिखने वाले मनोज मुंतशिर को भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जैसे ही अक्षय को पता चला कि कविता मनोज मुंतशिर ने लिखी है। उन्होंने अपनी गलती सुधारते हुए तुरंत एक और पोस्ट किया और लिखा कि मुझे पता चला है कि इस खुबसूरत कविता को मनोज मुंतशिर ने लिखा है और अजय ने इसे अपनी जुबानी सुनाया है।



देशभक्ति वाली कई फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं अक्षय ●जागरण आर्काइव